LKS

दैनिक लोकतंत्र की शान

लोकतंत्र का स्तंभ

RNI NO.: DELHIN / 2008 / 23928

www.loktantrakishaan.com

दिल्ली से प्रकाशित

गुरुवार 09 अप्रैल 2026

अमेरिका-इजराइल ने ईरान पर हमले रोके, होर्मुज खुलेगा, दो हफ्ते का संघर्ष विराम प्रभावी

एजेंसी। वाशिंगटन/तेल अवीव/ तेहरान

अमेरिका और ईरान दो सप्ताह के संघर्ष विराम पर सहमत हो गए हैं। ईरान के 10 सूत्री प्रस्ताव पर यह समझौता राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की समयसीमा से दो घंटे से भी कम समय पहले हुआ। ट्रंप ने मंगलवार की समय सीमा तय करते हुए तेहरान से होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोलने या फिर समूची सभ्यता को मिटा दिए जाने का सामना करने की चेतावनी दी थी। मंगलवार देर रात ट्रंप की सहमत होने की घोषणा उनकी असाधारण चेतावनी से एकदम उलट रही। यह घोषणा पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के मध्यस्थता प्रयासों के बाद सामने आई। गल्फ न्यूज, अल जजीरा, तसनीम, सीबीएस न्यूज और सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराकची ने पुष्टि की है कि अगले दो हफ्तों तक होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने की अनुमति ईरानी सेना के प्रबंधन में दी जाएगी। अराकची ने बुधवार तड़के अपने एक्स हैंडल पर ईरान के सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की ओर से युद्ध में प्रस्तावित युद्ध विराम के बारे में बयान जारी किया। इसमें कहा गया है कि अमेरिका के 15 और ईरान के 10 सूत्री प्रस्ताव के बाद शांति का यह अवसर मिला है। बयान में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और सैन्य प्रमुख का आभार जताया गया है। इसमें कहा गया है कि दो सप्ताह की अवधि के लिए ईरान के सशस्त्र बलों के साथ समन्वय और तकनीकी सीमाओं का ध्यान रखते हुए होर्मुज़ जलडमरूमध्य से सुरक्षित मार्ग संभव होगा। उल्लेखनीय है कि अमेरिका-इजराइल के 28 फरवरी को ईरान के खिलाफ शुरू किए गए सैन्य अभियान में अयातुल्ला सैयद अली खामेनेई, कई वरिष्ठ सैन्य कमांडरों की मौत हो गई थी। इसके बाद छिड़ा युद्ध खाड़ी देशों तक फैल गया। होर्मुज जलडमरूमध्य पर ईरान ने कड़ा पहरा बैठा दिया। जहाजों के आवागमन पर रोक लगा दिया। इससे सारी दुनिया में तेल और गैस का संकट पैदा हो गया। संघर्ष विराम पर सहमत होने के बावजूद ईरान ने इस बात पर जोर दिया है कि इस्लामाबाद में होने वाली बातचीत संघर्ष की समाप्ति का संकेत नहीं होगी, बल्कि कूटनीतिक प्रयासों के विस्तार के रूप में होगी। यह अमेरिका की जीत हैः व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलीन लेविट ने अमेरिका-ईरान सीजफायर समझौते को अमेरिका की जीत बताया है। उन्होंने कहा कि इसे राष्ट्रपति ट्रंप और जाबांज सेना ने मुमकिन बनाया। उन्होंने एक्स पर कहा कि ईरान के खिलाफ अमेरिका के सैन्य अभियान ने प्रशासन को कड़ी बातचीत करने का मौका दिया, जिससे अब एक कूटनीतिक समाधान और लंबे समय तक शांति की राह खुली है। उन्होंने लिखा, "इसके अलावा राष्ट्रपति ने होर्मुज को फिर से खुलवाया। ईरान की शर्तों पर ही बढ़ेंगे अगले कदमः ईरानी अधिकारी अमेरिका के साथ इस सीजफायर समझौते को ईरान के लिए एक "जीत" के तौर पर पेश कर रहे हैं। वह अब नागरिकों से वादा कर रहे हैं कि अब अगले कदम ईरान की शर्तों पर बढ़ेंगे।

पश्चिम एशिया में युद्धविराम का स्वागत कर भारत ने जताई स्थाई शांति की उम्मीद

नई दिल्ली। भारत ने ईरान-अमेरिका के बीच पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष में दोनों पक्षों के युद्ध विराम की घोषणा करने का स्वागत किया है। भारत ने कहा है कि दुनिया इसकी बहुत कीमत चुका चुकी है और उम्मीद है कि अब यह आगे स्थाई शांति की ओर बढ़ेगा। विदेश मंत्रालय ने बुधवार को एक बयान में कहा कि हम युद्धविराम का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि इससे पश्चिम एशिया में स्थायी शांति स्थापित होगी। जैसा कि हमने पहले भी कई बार कहा है, मौजूदा संघर्ष को जल्द से जल्द समाप्त करने के लिए तनाव कम करना, संवाद और कूटनीति अत्यंत आवश्यक है। बयान में कहा गया है कि इस संघर्ष ने पहले ही लोगों को भारी पीड़ा पहुंचाई है और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति एवं व्यापार नेटवर्क को बाधित किया है। हम आशा करते हैं कि होर्मुज जलडमरूमध्य से निर्बाध नौवहन और वैश्विक व्यापार का प्रवाह जारी रहेगा। उल्लेखनीय है कि अमेरिका आखिरकार संघर्ष विराम पर सहमत हो गया। इस पर इजराइल ने भी हां कर दी है। दोनों ने मध्यस्थ देशों का मान रख लिया और अब ईरान के साथ आमने-सामने की बातचीत की तैयारी की जा रही है। 28 फरवरी को ईरान पर अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हमले से पश्चिम एशिया का सैन्य संघर्ष शुरू हुआ था।

ज्वलंत मुद्दा | संपादकीय

शर्तों के साथ ईरान और अमेरिका के बीच 15 दिन का सीज फायर

ईरान और अमेरिका के बीच दो सप्ताह के लिए युद्ध विराम के लिए सहमति बन गई है। अमेरिका की ओर से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसका ऐलान किया। ईरान ने भी अधिकृत रूप से इसकी घोषणा की। सीज फायर के बाद हमले तत्काल रूप से बंद हो गए हैं। ईरान ने इसके लिए अधिकृत रूप से आदेश जारी किए हैं। युद्ध विराम को लेकर 10 शर्तों के साथ ईरान ने प्रस्ताव पेश किया है। चीन द्वारा दोनों पक्षों को समझाइस दिए जाने के बाद 15 दिन के लिए युद्ध विराम घोषित किया गया है। इसकी घोषणा होते ही, इसके सकारात्मक परिणाम भारत सहित दुनिया के सभी देशों में देखने को मिले हैं। एक नई आशा की किरण जागी है। दोनों पक्ष गंभीरता के साथ विचार करके स्थाई रूप से युद्ध रोकने और शांति के लिए प्रयास करेंगे। इसके लिए दोनों पक्षों का एक मंच पर आना जरूरी था। पाकिस्तान ने तीनों पक्षों के बीच बातचीत के लिये जो प्रयास किया, वह सार्थक हुआ।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा इस फैसले में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और पाकिस्तान के सैन्य प्रमुख असीम मुनीर का उल्लेख किया। डोनाल्ड ट्रंप ने यह उल्लेख किया है, ईरान को स्टेट आफ हार्मोज को फिर से खोलना होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया, अमेरिका ने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। अमेरिका अब तेहरान के साथ निर्णायक फैसले की स्थिति में आ गया है। अब जो भी समझौता होगा वह दीर्घकालिक शांति के लिए होगा। ईरान की ओर से शीर्ष अधिकारी बातचीत करने के लिए पाकिस्तान आएंगे। अमेरिका के उपराष्ट्रपति इस बातचीत में शामिल होंगे। इस फैसले के आते ही सारी दुनिया के देशों ने राहत की सांस ली है। ऊर्जा संबंधी संकटों और युद्ध को लेकर जो स्थिति बनी हुई थी। उससे सारी दुनिया को अस्थाई रूप से राहत मिली है।

भारत में इसका बड़ा असर देखने को मिला। शेयर बाजार ने 2800 अंकों की छलांग लगाई। कच्चे तेल के दाम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तेजी के साथ गिरे। इस युद्ध में अमेरिका द्वारा ईरान को खत्म करने की जो धमकी दी जा रही थी, चीन, रूस और उत्तर कोरिया के इस युद्ध में शामिल होने की संभावना बन गई थी। पिछले एक साल से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से टैरिफ को लेकर दबाव बना रहे थे। वेनेजुएला के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को उठाकर अमेरिका में बंधक बनाया गया। इसके तुरंत बाद ईरान पर हमला किया गया। इससे सारी दुनिया के देश अमेरिका से नाराज थे। अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप का विरोध शुरू हो गया है। अंतरराष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन करते हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कांग्रेस की मंजूरी लिए बिना जिस तरह से ईरान पर हमला किया था। अमेरिकी कानून के अनुसार केवल 45 दिन तक वह इस तरह की कार्रवाई राष्ट्रपति कर सकते थे।

सैयद जकी हैदर | सम्पदक/प्रकाशक
MOBE NO.9911371802
EMAIL. SYEDZAKIHAIDER786@GMAIL.COM

संक्षिप्त समाचार

खड़गे के कथित बयान पर असम में विवाद, आरएसएस ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत

गुवाहाटी/सिलचर। असम में चुनावी माहौल के बीच एक कथित विवादास्पद बयान को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की उत्तर असम और दक्षिण असम इकाइयों ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। यह शिकायत गुवाहाटी के दिसपुर पुलिस स्टेशन और सिलचर पुलिस स्टेशन में अलग-अलग दर्ज कराई गई है। आरएसएस का आरोप है कि दक्षिण असम के श्रीभूमि जिले के करीमगंज दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के नीलामबाजार में आयोजित एक चुनावी रैली के दौरान दिए गए भाषण में धार्मिक भावनाओं और राजनीतिक संगठनों को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणियां की गईं। शिकायत में दावा किया गया है कि खड़गे ने आरएसएस और भाजपा की विचारधारा की तुलना "ज़हरीले साँप" से करते हुए उनके खिलाफ कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया। आरोप है कि भाषण में एक उदाहरण के माध्यम से यह कहा गया कि यदि कोई खतरा सामने हो तो पहले उसे खत्म करना चाहिए, जिसे आरएसएस ने उकसावेपूर्ण और संवेदनशील बताया है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की ओर से दायर शिकायतों में कहा गया है कि इस तरह के बयान चुनावी माहौल में सामाजिक सौहार्द और सांप्रदायिक संतुलन को प्रभावित कर सकते हैं।

देश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की सप्लाई स्थिर : सरकार

नई दिल्ली। पश्चिम एशिया में सीजफायर की घोषणा का स्वागत करते हुए केंद्र सरकार ने बुधवार को कहा कि इससे क्षेत्र में स्थायी शांति आएगी। सरकार ने कहा कि देश में पेट्रोल और डीजल की सप्लाई स्थिर है। तेल रिफाइनरियां पर्याप्त कच्चे तेल के साथ पूरी क्षमता से चल रही हैं, जबकि 23 मार्च से अब तक 5 किलो के लगभग 8,90,000 सिलेंडर बेचे जा चुके हैं। कोयला आधारित बिजली देश की ऊर्जा जरूरतों का लगभग 70 फीसदी हिस्सा पूरा करना जारी रखे हुए है। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव (मार्केटिंग और ऑयल रिफाइनरी) सुजाता शर्मा ने अंतर-मंत्रालयी प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए यह जानकारी दी। सुजाता शर्मा ने कहा कि पिछले पांच दिनों में ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने करीब 1,600 जागरूकता कैंप लगाए हैं, जिनमें लगभग 14,000 सिलेंडर बांटे गए हैं। उन्होंने कहा कि कल लगभग 1.1 लाख गैस सिलेंडर की सप्लाई की गई, जिससे 23 मार्च से अब तक पांच किलो वाले गैस सिलेंडर की कुल बिक्री लगभग 8.9 लाख हो गई है। उन्होंने बताया कि घरेलू जरूरतों को प्राथमिकता दी जा रही है, जिसमें खाद बनाने वाले प्लांटों को लगभग 95 फीसदी गैस की सप्लाई मिल रही है। पेट्रोल और डीजल की सप्लाई स्थिर है और कहीं भी कमी नहीं है क्योंकि रिफाइनरियां पर्याप्त कच्चे तेल के साथ पूरी क्षमता से चल रही हैं। शर्मा ने कहा कि सरकार ने सप्लाई बढ़ाने के लिए C3 और C4 स्ट्रीम को एलपीजी पूल में भेजने का निर्देश दिया है, जबकि पेट्रोकेमिकल्स के लिए सीमित इस्तेमाल की अनुमति दी है।

प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की 11वीं वर्षगांठ पर सफलता की सराहना की

एजेंसी। नई दिल्ली

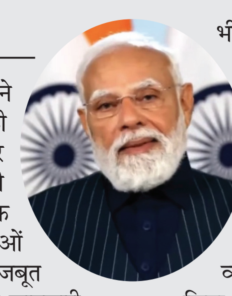

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की 11वीं वर्षगांठ के अवसर पर इसकी सफलता की सराहना करते हुए कहा कि यह योजना देश के युवाओं के लिए स्वरोजगार का मजबूत माध्यम बनकर उभरी है। यह जानकारी प्रधानमंत्री कार्यालय ने दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि 11 वर्ष पहले शुरू की गई इस योजना ने यह साबित किया है कि यदि लोगों को सही अवसर और समर्थन मिले, तो वे न केवल आत्मनिर्भर बन सकते हैं बल्कि राष्ट्र निर्माण में भी महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर अपने संदेश में भी लिखा कि यह योजना युवाओं को सशक्त बनाने में बेहद प्रभावी रही है और आने वाले समय में भी इसी तरह देश की प्रगति को गति देती रहेगी। इस अवसर पर उन्होंने एक संस्कृत सुभाषित भी साझा किया, जिसमें एक बुद्धिमान व्यक्ति के गुणों का वर्णन किया- "आत्मज्ञानं समारंभस्थितिक्षा धर्मनित्यता। यमर्था नापकर्षन्ति स वै पण्डित उच्यते॥" प्रधानमंत्री ने श्लोक का अर्थ बताते हुए कहा कि जो व्यक्ति अपनी क्षमताओं को समझता है, आत्मनिर्भर होता है, धैर्य रखता है, धर्म का पालन करता है और लालच से विचलित नहीं होता वही सच्चे अर्थों में बुद्धिमान होता है।

दो माह 'ग्राउंडेड' रहने के बाद अब फिर से उड़ान भर सकेंगे तेजस लड़ाकू जेट

एजेंसी। नई दिल्ली

तकनीकी गड़बड़ी मिलने के बाद विमान के ब्रेक सॉफ्टवेयर को किया गया अपग्रेड

लगभग दो महीने तक जमीन पर खड़े रहने के बाद अब फिर से तेजस लड़ाकू जेट उड़ान भर सकेंगे। लगातार तीन दुर्घटनाओं के बाद 'ग्राउंडेड' किये गए विमानों की जांच में कई खामियां मिली थीं, जिन्हें ठीक किये जाने के बाद वायु सेना ने उड़ान भरने की मंजूरी दी है। उड़ान पर रोक के चलते ही इसी साल 27 फरवरी को पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में हुए 'वायु शक्ति' अभ्यास में स्वदेशी तेजस मार्क-1 शामिल नहीं हो पाया था। दरअसल, 07 फरवरी को एक तेजस विमान पश्चिमी मोर्चे के एक फॉरवर्ड बेस से टेक ऑफ करते समय रनवे से फिसलकर पास की मिट्टी की खाई में जा गिरा था। सिंगल-सीटर एयरक्राफ्ट का पायलट बच गया, लेकिन उसे चोटें आईं थी। इसी दुर्घटना के बाद भारतीय वायु सेना ने अपने तेजस लड़ाकू जेट बेड़े को जमीन पर रोक दिया, क्योंकि यह तेजस विमान की तीसरी दुर्घटना थी। इससे पहले पहली दुर्घटना मार्च 2024 में जैसलमेर के पास हुई थी, जब पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में हुए 'वायु शक्ति' अभ्यास में प्रदर्शन करके लौटते समय क्रैश हो गया था। दूसरा क्रैश नवंबर 2025 में हुआ था, जब जेट दुबई एयरशो में एक एरोबैटिक डिस्प्ले में शामिल था। इस दुर्घटना में पायलट की मौत हो गई थी। भारतीय वायु सेना ने इसके बाद लगभग 35 एकल सीट वाले तेजस हल्के लड़ाकू विमानों के अपने पूरे बेड़े को विस्तृत तकनीकी जांच के लिए जमीन पर रोक दिया, ताकि इसकी जांच करके प्रणालीगत दोष दूर किये जा सकें। ऐसी जांच आमतौर पर तब की जाती है, जब किसी संभावित तकनीकी खराबी का शक हो। जांच के दौरान वायु सेना और हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) की कमेटी ने पाया कि विमान के ब्रेक सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी की वजह से यह हादसा हुआ। विमान के ब्रेकिंग सॉफ्टवेयर में सुधार की जरूरत थी, जो किया गया। एचएएल के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक डीके सुनील ने बताया कि फ्लीट की पूरी जांच में पहियों को पकड़ने वाले अंडर-कैरिज की मेटलर्जी, ब्रेक लगाने के लिए इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रो-मैग्नेटिक सिस्टम और सॉफ्टवेयर की समीक्षा की गई।

तमिलनाडु चुनावः पीएम मोदी के धुआंधार प्रचार से कांग्रेस और डीएमके गठबंधन पर उठे सवाल

चैन्नई। तमिलनाडु में चुनावी पारा अपने चरम पर है और राज्य की सभी प्रमुख पार्टियां मतदाताओं को लुभाने के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगा रही हैं। हालांकि, इस चुनावी रण में दो बड़े राष्ट्रीय चेहरों की सक्रियता ने नई बहस छेड़ दी है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के लिए लगातार राज्य के दौरे कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तमिलनाडु में प्रचार से अब तक की दूरी कई राजनीतिक सवाल खड़े कर रही है। पिछले दो महीनों के भीतर प्रधानमंत्री मोदी ने अपने सहयोगियों के पक्ष में माहौल बनाने के लिए तीन बार तमिलनाडु का दौरा किया है। उनका यह आक्रामक अभियान यहीं रुकने वाला नहीं है, क्योंकि वे 15 अप्रैल को फिर से नागरकोइल में एनडीए उम्मीदवारों के समर्थन में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री के इस ताबड़तोड़ प्रचार के ठीक विपरीत, राहुल गांधी ने अब तक तमिलनाडु में एक भी रैली नहीं की है। उनकी इस अनुपस्थिति ने इन अटकलों को हवा दे दी है कि कांग्रेस और द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) गठबंधन के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है।

देशभर में 9 से 23 अप्रैल तक मनाया जाएगा 8वां पोषण पखवाड़ा

नई दिल्ली। केंद्र सरकार 9 से 23 अप्रैल तक पूरे देश में 8वां पोषण पखवाड़ा 2026 मनाने जा रही है। इस वर्ष का मुख्य विषय "जीवन के पहले छह वर्षों में मस्तिष्क के विकास को अधिकतम करना" रखा गया है, जिसका उद्देश्य बच्चों के समग्र विकास की मजबूत नींव तैयार करना है। यह अभियान 'कुपोषण मुक्त भारत' के लक्ष्य को मजबूत करने के साथ-साथ जन-जागरूकता और सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा देगा। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अनुसार, इस पखवाड़े का राष्ट्रीय स्तर पर शुभारंभ 9 अप्रैल को दिल्ली के विज्ञान भवन में दोपहर 3 से 4 बजे के बीच होगा। कार्यक्रम का नेतृत्व केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी करेंगी। इस अवसर पर राज्य मंत्री सवित्री ठाकुर और विभाग के सचिव अनिल मलिक भी उपस्थित रहेंगे। मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर जानकारी साझा करते हुए बताया कि यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में संचालित "मिशन पोषण 2.0" के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह पहल बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिए शुरुआती वर्षों में पोषण और देखभाल को सुदृढ़ करने पर केंद्रित है। पोषण पखवाड़े के दौरान देशभर के आंगनवाड़ी केंद्रों में माताओं, अभिभावकों, परिवारों और स्थानीय संस्थाओं की भागीदारी से विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाएंगी।

विधानसभा चुनावः असम, केरल और पुडुचेरी में मतदान कल, सभी तैयारियां पूरी

एजेंसी। नई दिल्ली

असम, केरल और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव के लिए 9 अप्रैल (गुरुवार) को एक ही चरण में मतदान कराया जाएगा। चुनाव आयोग और स्थानीय प्रशासन ने शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी मतदान सुनिश्चित करने के लिए व्यापक तैयारियां पूरी कर ली हैं। असम की 126, केरल की 140 और पुडुचेरी की 30 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों की किस्मत 09 अप्रैल को ईवीएम में बंद हो जाएगी। इन सभी सीटों के लिए मतदान प्रक्रिया एक ही चरण में पूरी की जाएगी। असम में कुल 2.5 करोड़ मतदाता हैं, जिनमें 1.25 करोड़ पुरुष, 1.25 करोड़ महिलाएं और 343 तीसरे लिंग के मतदाता शामिल हैं। 18-19 आयु वर्ग के 5.75 लाख युवा मतदाता पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। असम की 126 विधानसभा सीटों के लिए 722 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। यहां बहुमत का आंकड़ा 64 है। राज्य की 15वीं विधानसभा का कार्यकाल 20 मई, 2026 को समाप्त होने वाला है। इसी तरह से केरल विधानसभा की 140 सीटों के लिए 890 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। यहां मुकाबला त्रिकोणीय है, जिसमें प्रमुख राजनीतिक दल शामिल हैं। सरकार बनाने के लिए 71 सीटों के बहुमत की आवश्यकता है। राज्य में कुल 2.71 करोड़ मतदाता हैं, जिनमें 1.32 करोड़ पुरुष, 1.39 करोड़ महिलाएं और 273 तीसरे लिंग के मतदाता शामिल हैं। वहीं, पुडुचेरी में 30 सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं, जिनमें से पांच सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित हैं। सरकार बनाने के लिए 16 सीटों के बहुमत की आवश्यकता है। यहां कुल 9.44 लाख मतदाता हैं, जिनमें लगभग 4.43 लाख पुरुष, 5 लाख महिलाएं और 139 तीसरे लिंग के मतदाता शामिल हैं। असम चुनाव के लिए 31,490 पोलिंग स्टेशनों पर 25,054,463 मतदाता मताधिकार के हकदार हैं और इन सभी मतदान केंद्रों की निगरानी लाइव वेबकास्ट के ज़रिए की जाएगी।

दो पासपोर्ट और नागरिकता पर क्या है नियम, जिस पर विवादों में घिरी हैं हेमंत की पत्नी रिंकी

एजेंसी। गुवाहाटी

इन दिनों भारतीय नागरिकता और पासपोर्ट चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। दरअसल असम विधानचुनाव के बीच कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने आरोप लगाया है कि सीएम हिमंता बिस्वा सरमा की पत्नी रिनिकी भुइयां के पास तीन देशों का पासपोर्ट है। आरोप के मुताबिक रिनिकी के पास यूएई, एंटीगा-बार्बूडा और इजिप्ट का पासपोर्ट है। इन सबकी वैधता 2027 से 2031 के बीच खत्म होने वाली है। कांग्रेस प्रवक्ता खेड़ा के इन आरोपों के बाद सीएम सरमा ने भी जवाब दिया है। उन्होंने इन आरोपों को कांग्रेसी प्रोपोगैंडा बताकर कहा कि उनकी पत्नी कांग्रेस नेता को जिंदगी भर जेल में सड़ाएगी। इस बीच सवाल उठता है कि क्या एक भारतीय नागरिक कई देशों का पासपोर्ट रख सकता है। बात दें कि पासपोर्ट एक्ट 1967 के मुताबिक अगर किसी व्यक्ति ने गलत ढंग से पासपोर्ट हासिल किया है, तब अधिकारियों को पासपोर्ट जब्त करने का अधिकार है। इतना ही नहीं, अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य पासपोर्ट को अनुचित रूप से हासिल करता है, तब उस रद्द किया जा सकता है। सेक्शन 12 के तहत पासपोर्ट को लेकर धोखाधड़ी, छुपाने या इसके दुरुपयोग पर दंडित किया जा सकता है। खासतौर पर गलत तरीके से कई पासपोर्ट रखने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। क्या देश में दोहरी नागरिकता की इजाजत है। इस बारे में भारतीय नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 9 में साफ प्रावधान है। इसके मुताबिक अगर कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता पाता है, तब उसकी भारतीय नागरिकता खुद ही खत्म होगी। इसके अलावा संविधान भी एक साथ भारतीय और विदेशी नागरिकता रखने की अनुमति नहीं देता। नागरिकता अधिनियम की धारा 7ए के तहत प्रस्तुत, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया योजना उन कुछ भारतीय मूल के व्यक्तियों को भारत में आजीवन वीजा के साथ रहने और काम करने की अनुमति देता है जिन्होंने विदेशी नागरिकता ग्रहण की है।

खरगे, राहुल, प्रियंका ने मोहसिना किदवई के निधन पर दुख जताया

नई दिल्ली। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने पार्टी की वरिष्ठ नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री मोहसिना किदवई के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। मोहसिना किदवई का आज उत्तर प्रदेश के नोएडा स्थित आवास पर 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे लंबे समय से उम्रजनित समस्याओं से पीड़ित थीं। खरगे ने एक्स पोस्ट में उनके निधन पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा कि मोहसिना किदवई ने अपने जीवन के छह दशक से अधिक समय देश की सेवा को समर्पित किए और वे पार्टी की एक मजबूत व मार्गदर्शक नेता रहीं। किदवई लोकसभा और राज्यसभा दोनों की सदस्य रहीं और कांग्रेस कार्य समिति की सम्मानित सदस्य के रूप में उन्होंने कठिन समय में पार्टी को दिशा दी। उनका निधन कांग्रेस और राष्ट्र के लिए अपूरणीय क्षति है। राहुल गांधी ने भी उनके निधन पर शोक जताया। उन्होंने कहा कि मोहसिना किदवई एक अत्यंत वरिष्ठ, वफादार और समर्पित नेता थीं, जिनका पूरा जीवन जनसेवा के लिए समर्पित रहा।

Mfg & mkt by.. ANGEN PHARMACEU-TICALS (OPC) PRIVATE LIMITED

Distributorship ke liye contact Karen .
(9315755133 / ya email Karen)
angenpharmaceuticals@gmail.com

खास खबर

पश्चिम बंगाल चुनाव के दूसरे चरण के लिए कांग्रेस ने 8 उम्मीदवारों की नई सूची जारी की, 7 बदले

लोकतंत्र की शान : नई दिल्ली। कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए बुधवार को 8 उम्मीदवारों की नई सूची जारी की। पार्टी ने इस सूची में बड़ा फेरबदल करते हुए सात सीटों पर पहले घोषित प्रत्याशियों को बदल दिया है। पार्टी महासचिव केसी वेणुगोपाल की ओर से जारी सूची में कुल 8 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। इनमें से सात उम्मीदवार पहले घोषित प्रत्याशियों की जगह लेंगे, जबकि हावड़ा सीट पर प्रणब भट्टाचार्य को नया उम्मीदवार बनाया गया है। सूची के अनुसार नाकाशिपारा से ताहिर एसके को गोलाम किबरिया मंडल की जगह उम्मीदवार बनाया गया है। छपरा से आसिफ खान को रहीदुल मंडल की जगह उतारा गया है। हावड़ा से प्रणब भट्टाचार्य को नया उम्मीदवार घोषित किया गया है। मिनाखां (एससी) से सुनयना बिस्वास को बरनाली नस्कर की जगह टिकट दिया गया है। मंदिरबाजार (एससी) से चांद सरदार को कौशिक बैद्य की जगह उम्मीदवार बनाया गया है। रैना (एससी) से पम्पा मलिक को अनिक साहा की जगह उतारा गया है। केतुग्राम से एसके अबू बक्कर को मोफिरुल कासिम की जगह उम्मीदवार बनाया गया है। औसग्राम (एससी) से तापस बराल को निशा बराल की जगह टिकट दिया गया है।

हिंदू देवी-देवताओं के अपमान वाली राणा अय्युब की पोस्ट पर हाई कोर्ट सख्त, कार्रवाई के निर्देश

लोकतंत्र की शान : नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने पत्रकार राणा अय्युब के हिन्दू देवी-देवताओं और विनायक सावरकर पर 2013 से लेकर 2017 के बीच किए गए पोस्ट पर कड़ा एतराज जताया है। जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने कहा कि राणा अय्युब के पोस्ट अपमानजनक, भड़काऊ और सांप्रदायिक हैं। उच्च न्यायालय ने इसके लिए दिल्ली पुलिस और सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स के खिलाफ जरुरी कार्रवाई करने का आदेश दिया। उच्च न्यायालय ने राणा अय्युब को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 10 अप्रैल को होगी। उच्च न्यायालय ने राणा अय्युब के अलावा दिल्ली पुलिस को भी नोटिस जारी किया। उच्च न्यायालय ने कहा कि इस मामले पर गंभीरता से विचार करने की जरुरत है। कोर्ट ने कहा कि एक्स, दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार समन्वय से काम करे। याचिका अमिता सचदेवा ने दायर की है। याचिकाकर्ता ने इसके पहले साकेत कोर्ट में याचिका दायर की थी। साकेत कोर्ट ने राणा अय्युब के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश देते हुए दिल्ली पुलिस को जांच करने का आदेश दिया था। दिल्ली पुलिस ने कहा था कि जिन पोस्ट को लेकर याचिका दायर की गई है वो अब एक्स पर मौजूद नहीं हैं। अमिता सचदेवा ने याचिका दायर कर कहा है कि राणा अय्युब ने हिन्दू देवताओं राम और सीता, वीर सावरकर और हिन्दू राष्ट्रवाद और भारत विरोधी भावनाओं को प्रदर्शित करने का काम किया है। अमिता सचदेवा ने कहा है कि वो सनातन धर्म की अनुयायी हैं। जब उन्होंने राणा अय्युब का पोस्ट देखा तो उन्हें काफी आघात लगा। अमिता ने अपनी याचिका में राणा अय्युब के 2013 से 2017 के बीच के सात पोस्ट का उल्लेख किया है।

दिल्ली हाई कोर्ट ने ट्रांसजेंडर संशोधन कानून पर केंद्र को नोटिस जारी किया

लोकतंत्र की शान : नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकार से संबंधित कानून में संशोधन की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय की अध्यक्षता वाली बेंच ने मामले की अगली सुनवाई 22 जुलाई को करने का आदेश दिया। याचिका वकील डॉ. चंद्रेश जैन ने दायर की है। याचिका में कहा गया है कि ट्रांसजेंडर संशोधन कानून ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को संविधान के तहत मिले मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। याचिका में कहा गया है कि इस संशोधन के बाद ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को खुद से अपने जेंडर की पहचान बताने की बजाय सरकार के वेरिफिकेशन और प्रमाणन की जरुरत होगी। याचिका में कहा गया है कि जेंडर की पहचान किसी व्यक्ति की गरिमा, स्वायत्तता और निजता का एक अहम पहलू है और इसे किसी चिकित्सकीय या प्रशासनिक स्क्रूटनी का मोहताज बनाकर नहीं रखा जा सकता है। याचिका में उच्चतम न्यायालय के लीगल सर्विसेज अथॉरिटी बनाम केंद्र सरकार के फैसले का जिक्र किया गया है, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने स्वप्रमाणित जेंडर की पहचान को संविधान की धारा 14, 19(1)(ए) और 21 के तहत मौलिक अधिकार माना है। याचिका में कहा गया है कि इस संशोधन के जरिये मौलिक कानून से पीछे हटने का काम किया गया है। ये संशोधन बराबरी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अलावा अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों का उल्लंघन है। ट्रांसजेंडर की पहचान की प्रमाणन प्रक्रिया से उन्हें मिलने वाले कल्याणकारी लाभों और कानूनी सुरक्षा से वंचित होना पड़ेगा।

संदिग्ध आतंकी मसरत आलम की याचिका पर एनआईए को नोटिस

लोकतंत्र की शान : नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने संदिग्ध आतंकी मसरत आलम भट्ट की जेल में अपने परिवार से फोन पर बात करने की सुविधा देने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) को नोटिस जारी किया है। जस्टिस अनूप जयराम भांभानी की बेंच ने एनआईए को दो हफ्ते में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 7 मई को करने का आदेश दिया। आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में मसरत आलम भट्ट साल 2019 से हिरासत में है। मसरत आलम की ओर से पेश वकील ने कोर्ट से कहा कि याचिकाकर्ता पिछले करीब डेढ़ साल से अपने परिवार के सदस्यों से संपर्क नहीं कर सका है। दरअसल, जेल प्रशासन सर्कुलर जारी कर कहा कि मकोका, देश के खिलाफ अपराध, आतंकी गतिविधियों के आरोपितों को फोन करने की सुविधा नहीं की जाएगी। याचिका में कहा गया है कि पहले कैदियों को अपने परिवार के सदस्यों से मिलने को सुविधा मिलती थी, उसे सभी कैदियों के लिए बहाल किया जाए। मसरत आलम भट्ट के खिलाफ 4 अक्टूबर 2019 को टेरर फंडिंग के मामले में चार्जशीट दाखिल की गई थी। इस चार्जशीट में मसरत आलम भट्ट के अलावा अलगाववादी नेता यासिन मलिक, आसिया अंद्राबी, इंजीनियर रशीद और शब्बीर शाह को आरोपित बनाया गया था। चार्जशीट में भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी, 121, 121ए, और 124ए के अलावा गैरकानूनी गतिविधियां निरोधक कानून की धारा 13, 16, 17,18, 20, 38, 39 और 40 के तहत आरोप लगाए गए हैं।

देश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की सप्लाई स्थिर : सरकार

लोकतंत्र की शान

नई दिल्ली। पश्चिम एशिया में सीजफायर की घोषणा का स्वागत करते हुए केंद्र सरकार ने बुधवार को कहा कि इससे क्षेत्र में स्थायी शांति आएगी। सरकार ने कहा कि देश में पेट्रोल और डीजल की सप्लाई स्थिर है। तेल रिफाइनरियां पर्याप्त कच्चे तेल के साथ पूरी क्षमता से चल रही हैं, जबकि 23 मार्च से अब तक 5 किलो के लगभग 8,90,000 सिलेंडर बेचे जा चुके हैं। कोयला आधारित बिजली देश की ऊर्जा जरूरतों का लगभग 70 फीसदी हिस्सा पूरा करना जारी रखे हुए है। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव (मार्केटिंग और ऑयल रिफाइनरी) सुजाता शर्मा ने अंतर-मंत्रालयी प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए यह जानकारी दी। सुजाता शर्मा ने कहा कि पिछले पांच दिनों में ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने करीब 1,600 जागरूकता कैंप लगाए हैं, जिनमें लगभग 14,000 सिलेंडर बांटे गए हैं। उन्होंने कहा कि कल लगभग 1.1 लाख गैस सिलेंडर की सप्लाई की गई, जिससे 23 मार्च से अब तक पांच किलो वाले गैस सिलेंडर की कुल बिक्री लगभग 8.9 लाख हो

गई है। उन्होंने बताया कि घरेलू जरूरतों को प्राथमिकता दी जा रही है, जिसमें खाद बनाने वाले प्लांटों को लगभग 95 फीसदी गैस की सप्लाई मिल रही है। पेट्रोल और डीजल की सप्लाई स्थिर है और कहीं भी कमी नहीं है क्योंकि रिफाइनरियां पर्याप्त कच्चे तेल के साथ पूरी क्षमता से चल रही हैं। शर्मा ने कहा कि सरकार ने सप्लाई बढ़ाने के लिए C3 और C4 स्ट्रीम को एलपीजी पूल में भेजने का निर्देश दिया है, जबकि पेट्रोकेमिकल्स के लिए सीमित इस्तेमाल की अनुमति दी है। सुजाता शर्मा ने बताया कि नेचुरल गैस के संबंध में घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता दी गई है और उनकी आपूर्ति को सुरक्षित रखा गया है। इसके साथ ही उद्योगों को भी नेचुरल गैस की सप्लाई शुरू की गई है। ड्राफ्ट स्टेट सीबीजी पॉलिसी जारी की गई है, जो राज्य इस पॉलिसी को अपनाएंगे, उन्हें अतिरिक्त कमर्शियल एलपीजी आवंटन में प्राथमिकता दी जाएगी। भारत सरकार ने सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि वे ऐसे सुधार लागू करें, जिससे प्राथमिकता वाले कमर्शियल एलपीजी की आपूर्ति आसान हो सके। इसके तहत लगभग 18 राज्यों ने कदम उठाए हैं और उन्हें अतिरिक्त एलपीजी का आवंटन दिया गया है। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव ने कहा कि मार्च से अब तक लगभग 3,87,000 पीएनजी कनेक्शन दिए गए हैं और लगभग 4,21,000 नए उपभोक्ता पंजीकृत हुए हैं। जिन उपभोक्ताओं के पास एलपीजी और पीएनजी दोनों कनेक्शन हैं, उनसे एलपीजी कनेक्शन सरेंडर करने का अनुरोध किया गया है। उन्होंने कहा कि अब तक 17,000 से अधिक उपभोक्ता अपना एलपीजी कनेक्शन सरेंडर कर चुके हैं। इसके साथ ही सभी नागरिकों से अपील है कि अफवाहों पर ध्यान न दें और अपनी जरूरत के अनुसार ही ईंधन खरीदें। शर्मा ने कहा कि गड़बड़ियों पर रोक लगाने के लिए निगरानी बढ़ा दी गई है। हाल ही में लगभग 4,000 छापे मारे गए और पिछले कुछ दिनों में लगभग 56,000 सिलेंडर ज़ब्त किए गए। तेल मार्केटिंग कंपनियों ने 1,770 कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं, 51 डिस्ट्रीब्यूटरों को निलंबित किया है और 175 के खिलाफ कार्रवाई की है। पेट्रोल, डीज़ल और एलपीजी की सप्लाई लगातार बनी हुई है। नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे घबराएं नहीं और केवल आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करें।

सीजफायर का स्वागतः विदेश मंत्रालयःविदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ईरान और अमेरिका के बीच सीजफायर का स्वागत करते हुए उम्मीद जताई कि इससे पश्चिम एशिया में स्थायी शांति आएगी। उन्होंने कहा कि संघर्ष को जल्द से जल्द खत्म करने के लिए तनाव कम करना, बातचीत और कूटनीति ज़रूरी हैं। इस संघर्ष ने पहले ही लोगों को बहुत ज्यादा तकलीफ दी है और दुनियाभर में ऊर्जा की सप्लाई और व्यापार के नेटवर्क को बाधित किया है। जायसवाल ने कहा कि उम्मीद है कि होर्मुज जलडमरूमध्य से जहाजों की आवाजाही की पूरी आज़ादी और दुनिया भर में व्यापार का प्रवाह बना रहेगा।उन्होंने कहा कि भारत उन सभी कदमों का स्वागत करता है जिनसे शांति और स्थिरता आती है। उन्होंने उम्मीद जताई कि पश्चिम एशिया में यह घटनाक्रम यूक्रेन में भी शांति की कोशिशों को बढ़ावा देगा।

भारत के खदानों और बिजली संयंत्रों में कोयले का पर्याप्त भंडारःवहीं, कोयला मंत्रालय में संयुक्त सचिव संजीव कुमार कासी ने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि खदानों, पावर प्लांटों, बंदरगाहों और ट्रांजिट में कोयले का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है, जिसे बहुत कम समय की सूचना पर उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराया जा सकता है। उन्होंने बताया कि बिजली उत्पादन के मामले में हमें बिल्कुल भी कमी का सामना नहीं करना पड़ रहा है और कोयले का उत्पादन उसी गति से कर रहे हैं, जिस गति से उसका उपभोग हो रहा है।" उन्होंने दावा किया कि भारत के पास इस समय खदानों और बिजली संयंत्रों में कोयले का पर्याप्त भंडार मौजूद है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि उपभोक्ताओं तक बहुत कम समय में भी आपूर्ति पहुंचाई जा सके। बिजली उत्पादन क्षमता में कोई कमी नहीं है क्योंकि कोयले का उत्पादन खपत के स्तर के साथ तालमेल बिठाए हुए है। उन्होंने कहा कि कोयला आधारित बिजली, देश की ऊर्जा ज़रूरतों का लगभग 70 फीसदी हिस्सा पूरा करना जारी रखे हुए है। समन्वित प्रयासों के माध्यम से भारत ने कोयले की किफायती और पर्याप्त आपूर्ति बनाए रखी है और लगातार दूसरे वर्ष 1 अरब टन कोयले के उत्पादन का लक्ष्य हासिल किया है।

केन्द्र ने राजस्थान के बालोतरा पेट्रोकेमिकल परियोजना की लागत और निवेश में की बढ़ोत्तरी

लोकतंत्र की शान

नई दिल्ली। केन्द्र सरकार ने एचपीसीएल की राजस्थान के बालोतरा जिले के पचपदरा में बन रही राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड (एचआरआरएल) की लागत और उसमें इक्विटी निवेश में संशोधन किया है। संशोधित परियोजना लागत अब 79,459 करोड़ रुपये की गई है। परियोजना से भारत की ऊर्जा आत्मनिर्भरता बढ़ेगी और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र की आयात पर निर्भरता कम होगी। परियोजना के 1 जुलाई, 2026 को वाणिज्यिक परिचालन शुरू होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने आज संशोधन को मंजूरी दी। परियोजना की लागत पहले 43,129 करोड़ रुपये थी। वहीं, परियोजना में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) भी 8,962 करोड़ रुपये का अतिरिक्त इक्विटी निवेश करेगा। मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी देते हुए केन्द्रीय

मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे ऊर्जा सुरक्षा बढ़ेगी, पेट्रोकेमिकल्स के लिए आयात पर निर्भरता कम होगी और घरेलू विनिर्माण क्षेत्रों को बढ़ावा मिलेगा। इससे इस क्षेत्र में औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा, स्थानीय कच्चे तेल का उपयोग होगा और भारत एक रिफाइनिंग हब के रूप में स्थापित होगा। इससे रोज़गार के महत्वपूर्ण अवसर (लगभग 25,000 नौकरियाँ) पैदा होंगे और समग्र आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। उल्लेखनीय है कि राजस्थान के बालोतरा जिले के पचपदरा स्थित एचआरएल एक 90 लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष (एमएमटीपीए) की क्षमता वाला ग्रीनफील्ड रिफाइनरी-सह-पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स है। इसकी पेट्रोकेमिकल उत्पादन क्षमता 24 लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष है। परियोजना का कार्यान्वयन एचआरएल कर रहा है। एचआरएल एचपीसीएल और राजस्थान सरकार का संयुक्त उद्यम (जेवी) है। इसमें क्रमशः दोनों की हिस्सेदारी 74 प्रतिशत और 26 प्रतिशत है।

अरुणाचल प्रदेश की दो जल विद्युत परियोजनाओं में निवेश को मंजूरी

लोकतंत्र की शान

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश की दो जल विद्युत परियोजनाओं में निवेश को मंजूरी दी है। इसमें अरुणाचल प्रदेश के अंजॉ जिले में 1200 मेगावाट की कलाई-II जलविद्युत परियोजना और कामले, क्रा दाडी और कुरुंग कुमे जिलों में 1720 मेगावाट की कमला जलविद्युत परियोजना शामिल है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की आर्थिक मामलों की समिति ने निवेश को मंजूरी दे दी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में आयोजित पत्रकार वार्ता में इन फैसलों की जानकारी दी। पहली परियोजना की लागत 14105.83 करोड़ रुपये है और जिसे 78 महीनों में पूरा किया जाना है। दूसरी परियोजना की 26,069.50 करोड़ रुपये लागत है और इसका निर्माण 96 महीनों में पूरा किया जाएगा। कलाई-II जलविद्युत परियोजना से प्रतिवर्ष 4852.95 एमयू (मिलियन यूनिट) ऊर्जा उत्पन्न होने की उम्मीद है। लोहित बेसिन की पहली जलविद्युत परियोजना होने के नाते, यह राज्य में बिजली आपूर्ति को मजबूत करेगी, चरम मांग प्रबंधन में सहायता करेगी और राष्ट्रीय ग्रिड को संतुलित करने में योगदान देगी। केंद्र सरकार राज्य की इक्विटी हिस्सेदारी के लिए 750 करोड़ रुपये की केंद्रीय वित्तीय सहायता के अतिरिक्त, सहायक अवसंरचना के

अंतर्गत सड़कों, पुलों और संबंधित पारेषण लाइनों के निर्माण के लिए बजटीय सहायता के रूप में 599.88 करोड़ रुपये प्रदान करेगी। कमला जलविद्युत परियोजना इससे 6870 एमयू ऊर्जा उत्पन्न होने की उम्मीद है। इस परियोजना से उत्पन्न बिजली अरुणाचल प्रदेश राज्य में बिजली आपूर्ति की स्थिति को मजबूत करेगी, चरम मांग प्रबंधन में सहायता करेगी, राष्ट्रीय ग्रिड संतुलन में योगदान देगी और ब्रह्मपुत्र घाटी में बाढ़ नियंत्रण में लाभ प्रदान करेगी। कमला परियोजना का कार्यान्वयन एनएचपीसी लिमिटेड और अरुणाचल प्रदेश सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम कंपनी के माध्यम से किया जाएगा। भारत सरकार बाढ़ नियंत्रण घटक के लिए 4743.98 करोड़ रुपये और सहायक बुनियादी ढांचे के लिए 1340 करोड़ रुपये की बजटीय सहायता प्रदान करेगी।

सबरीमाला मंदिर मामले में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी- धर्म में क्या अंधविश्वास है, यह तय करना अदालत का अधिकार

लोकतंत्र की शान

नई दिल्ली। सबरीमाला मंदिर मामले पर सुनवाई करते हुए उच्चतम न्यायालय ने कहा कि किसी धर्म में कौन सी प्रथा अंधविश्वास है यह तय करने का अधिकार उसके पास है। उच्चतम न्यायालय ने ये बातें तब कही जब केंद्र सरकार ने दलील दी कि एक धर्मनिरपेक्ष अदालत इस मुद्दे पर फैसला नहीं कर सकती, क्योंकि जज कानून के विशेषज्ञ होते हैं, धर्म के नहीं। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 9 सदस्यीय संविधान बेंच के समक्ष इस मामले की सुनवाई का आज दूसरा दिन था। सुनवाई के दौरान केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि एक धर्मनिरपेक्ष अदालतें ये नहीं तय कर सकती कि अनिवार्य धार्मिक प्रथा क्या है, क्योंकि वो धार्मिक विद्वान नहीं हैं। मेहता ने कहा कि वास्तविक धर्मनिरपेक्षता वह है, जहां राज्य धर्म में हस्तक्षेप नहीं करे और धर्म राज्य में दखल न दे। तब जस्टिस बीवी

नागरत्ना ने कहा कि सार्वजनिक नैतिकता स्थिर नहीं है। जो 1950 के दशक में अनैतिक या अश्लील माना जाता था वह आज वैसा नहीं है। जस्टिस नागरत्ना ने पूछा कि क्या हम 50 के दशक के मानकों को संकीर्ण मानसिकता कह सकते हैं। उन्होंने कहा कि समाज के साथ नैतिकता बदलती रहती है, इसलिए इसे केवल एक पुराने नजरिये से नहीं देखा जा सकता है। मेहता ने कहा कि अदालतों को आस्था के मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। उन्होंने विभिन्न राज्यों में धार्मिक बंदोबस्ती कानूनों का हवाला देते हुए कहा कि पुजारियों की नियुक्ति की शक्ति राज्य को देना सिद्धांतों का उल्लंघन है। आज सुनवाई शुरु होते ही याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ वकील राजीव धवन ने समय के आवंटन का मुद्दा उठाते हुए कहा कि अगर सारा समय सॉलिसिटर जनरल ही लेंगे तो याचिकाकर्ताओं को अपनी बात रखने का मौका नहीं मिलेगा। इस पर कोर्ट ने सभी वरिष्ठ वकीलों को पर्याप्त समय देने का आश्वासन दिया। उच्चतम न्यायालय की 9 जजों की संविधान बेंच ने इस मामले पर 7 अप्रैल से सुनवाई शुरु की थी। केंद्र सरकार ने इस मामले पर दाखिल अपने हलफनामे में कहा है कि सबरीमाला मंदिर में माहवारी से जुड़े आयु वर्ग की महिलाओं के प्रवेश पर रोक धार्मिक आस्था और स्वायतता का मामला है। केंद्र सरकार ने कोर्ट से इस प्रतिबंध को बरकरार रखने की मांग की है और कहा है कि ऐसे मामलों में न्यायिक समीक्षा की सीमा सीमित होनी चाहिए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली इस बेंच में जस्टिस बीवी नागरत्ना, जस्टिस एमएम सुंदरेश, जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह, जस्टिस अरविंद कुमार, जस्टिस एजे मसीह, जस्टिस पीबी वराले, जस्टिस आर महादेवन और जस्टिस जॉयमाल्या बागची शामिल हैं। उच्चतम न्यायालय ने 28 सितंबर, 2018 को 4-1 के बहुमत से फैसला सुनाया था। कोर्ट ने कहा था कि महिलाओं के साथ काफी समय से भेदभाव होता रहा है। महिला पुरुष से कमतर नहीं है। एक तरफ हम महिलाओं को देवी स्वरुप मानते हैं दूसरी तरफ हम उनसे भेदभाव करते हैं। कोर्ट ने कहा था कि बायोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल वजहों से महिलाओं के धार्मिक विश्वास की स्वतंत्रता को खत्म नहीं किया जा सकता है। तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा समेत चार जजों ने कहा था कि ये संविधान की धारा 25 के तहत मिले अधिकारों के विरुद्ध है। जस्टिस इंदू मल्होत्रा ने बाकी चार जजों के फैसले से अलग फैसला सुनाया था। उन्होंने कहा था कि धार्मिक आस्था के मामले में कोर्ट को दखल नहीं देना चाहिए। उन्होंने कहा था कि पूजा में कोर्ट का दखल ठीक नहीं है। मंदिर ही यह तय करे कि पूजा का तरीका क्या होगा।

खरीफ फसलों के लिए 'पीएंडके' उर्वरकों पर पोषक तत्व आधारित सब्सिडी को मंजूरी

लोकतंत्र की शान

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने देश में इस साल की खरीफ की फसल (एक अप्रैल से 30 सितंबर) के लिए फॉस्फेटिक और पोटाशिक (पी एं ड के) उर्वरकों पर पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (ए न बी ए स) को मंजूरी दे दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में उर्वरक विभाग के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। इस साल की खरीफ फसलों के लिए अनुमानित बजट लगभग 41,533.81 करोड़ रुपये है, जो पिछले साल की खरीफ की फसलों की तुलना में करीब 4,317 करोड़ रुपये अधिक है। पिछले वर्ष खरीफ 2025 के लिए बजट 37,216.15 करोड़ रुपये था। केंद्र ने कहा कि इस निर्णय से किसानों को डीएपी और एनपीकेएस ग्रेड सहित 'पीएंडके' उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित होगी और उन्हें सब्सिडी दरों पर किफायती मूल्य पर उर्वरक मिलेंगे।

केंद्र ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में उर्वरकों हालिया कीमतों को ध्यान में रखते हुए सब्सिडी दरों को मंजूरी दी गई है। वर्तमान में सरकार 28 ग्रेड के 'पीएंडके' उर्वरक, जिनमें डीएपी भी शामिल है, किसानों को सब्सिडी दरों पर दी जा रही है। उल्लेखनीय है कि एनबीएस योजना अप्रैल 2010 से लागू है और इसके तहत उर्वरक कंपनियों को अनुमोदित दरों पर सब्सिडी दी जाती है ताकि किसानों तक उर्वरक सस्ती दरों पर पहुंच सके।

सेनाध्यक्ष ने लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर 'प्रचंड' में उड़ान भरकर परखी लड़ाकू क्षमता

लोकतंत्र की शान

नई दिल्ली। सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने बुधवार को बेंगलुरु में हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) का दौरा किया। उन्होंने लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर 'प्रचंड' में उड़ान भरकर इसकी लड़ाकू क्षमता, फुर्ती और मिशन की तैयारी का अनुभव किया। जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने एचएएल के हेलीकॉप्टर हैंगर के दौरे में चल रहे ऑपरेशन्स और क्षमताओं के बारे में जानकारी हासिल की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने भी फरवरी में जैसलमेर एयरफोर्स स्टेशन से प्रचंड में उड़ान भरी थी। चीन के खतरों को देखते हुए सेना ने असम के मिसामारी में प्रचंड को तैनात किया

है। यहां से वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) महज 250 किमी. दूरी पर है। इसी तरह अरुणाचल प्रदेश में चार एलसीएच तैनात किये गए हैं, जो एलएसी के अग्रिम इलाकों को कवर कर रहे हैं। एचएएल से सेना को 05 और वायुसेना को 10 हेलीकॉप्टर मिल चुके हैं, जिनका इस्तेमाल दोनों सेनाएं कर रही हैं। भारतीय सेनाओं की भविष्य की जरूरतों के हिसाब से विशेष तौर पर तैयार किये गए यह हेलीकॉप्टर दुर्गम स्थानों और सघन पर्वतीय क्षेत्रों में भी कारगर हैं। इसे कई तरह के बड़े बम, बंदूकों और मिसाइलों से लैस किया जा सकता है। इसे खासतौर पर ऊंचे पहाड़ों लद्दाख, सियाचिन जैसे इलाकों के लिए डिजाइन किया गया है। सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने आज एचएएल में निर्मित होने वाले लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड, एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर 'ध्रुव' और लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर (एलयूएच) के हैंगर का भी दौरा किया और चल रहे ऑपरेशन्स और क्षमताओं के बारे में जानकारी हासिल की। उन्होंने एचएएल के अधिकारियों के साथ चर्चा की, जिसका नेतृत्व एचएएल के सीएमडी डॉ. डी. के. सुनील ने किया। साथ ही डायरेक्टर (ऑपरेशंस) रवि के और वरिष्ठ अधिकारियों ने उन्हें खास कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी। अधिकारियों से बातचीत करते हुए उन्होंने भारत की रक्षा तैयारियों को मजबूत करने में एचएएल के योगदान की तारीफ की।

केंद्र ने जयपुर मेट्रो फेज-2 को दी मंजूरी, 41 किमी लंबा कॉरिडोर बनेगा

लोकतंत्र की शान

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने जयपुर शहर की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में बड़ा फैसला लेते हुए जयपुर मेट्रो फेज-2 परियोजना को मंजूरी दे दी है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस 41 किलोमीटर लंबे नॉर्थ–साउथ कॉरिडोर को स्वीकृति प्रदान की गई। जयपुर तेजी से विकसित हो रहा शहर है और इसकी बढ़ती आबादी एवं पर्यटन को देखते हुए यह परियोजना बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि फेज-2 के शुरू होने से शहर के बड़े हिस्से को मेट्रो से जोड़ दिया जाएगा और यह ईस्ट-वेस्ट एवं नॉर्थ-साउथ दोनों कॉरिडोर को एकीकृत करेगा।यह मेट्रो कॉरिडोर प्रह्लादपुरा से टोड़ी मोड़ तक बनाया जाएगा, जिसमें कुल 36 स्टेशन होंगे। इनमें से दो स्टेशन भूमिगत होंगे जबकि शेष एलिवेटेड होंगे। परियोजना की कुल लागत 13,038 करोड़ रुपये निर्धारित की गई है। इसका निर्माण राजस्थान मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आरएमआरसीएल) द्वारा किया जाएगा, जो केंद्र और राजस्थान सरकार का संयुक्त उपक्रम है। यह परियोजना जयपुर के प्रमुख क्षेत्रों जैसे सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया, वीकेआईए, जयपुर एयरपोर्ट, टोंक रोड, एसएमएस अस्पताल, स्टेडियम, अंबाबाड़ी और विद्याधर नगर को आपस में जोड़ेगी। एयरपोर्ट क्षेत्र में कुछ स्टेशन भूमिगत होंगे, जबकि बाकी हिस्सा एलिवेटेड रहेगा। फेज-2 को वर्तमान में संचालित फेज-1 से जोड़ा जाएगा, जिससे पूरे शहर में एकीकृत मेट्रो नेटवर्क तैयार होगा। फेस-1 के साथ खासाकोटी में इसका बड़ा इंटरचेंज बनेगा। अभी फेज-1 के 11.64 किमी लंबे कॉरिडोर पर रोजाना करीब 60,000 यात्री सफर करते हैं, और फेज-2 के शुरू होने के बाद इस संख्या में काफी वृद्धि होने की संभावना है। सरकार के अनुसार इस परियोजना से शहर में ट्रैफिक जाम कम होगा, प्रदूषण में कमी आएगी और लोगों को बेहतर व तेज परिवहन सुविधा मिलेगी। परियोजना का आर्थिक आंतरिक प्रतिफल दर (ईआईआरआर) 14 प्रतिशत से अधिक है, जो इसकी आर्थिक व्यवहार्यता को दर्शाता है। इस मेट्रो प्रोजेक्ट को राजस्थान टीओडी नीति-2025 और राष्ट्रीय शहरी परिवहन लक्ष्यों के अनुरूप तैयार किया गया है। इसे सितंबर 2031 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

संक्षिप्त समाचार

रामपुरः अपहरण की झूठी सूचना देकर प्रेमिका के परिजनों को फंसाने की साजिश, 02 आरोपी गिरफ्तार

लोकतंत्र की शान , मंडल प्रभारी अवनीत कुमार शर्मा, रामपुर जनपद के थाना स्वार क्षेत्र में एक युवक द्वारा प्रेमिका के परिजनों को अपहरण के झूठे केस में फंसाने की नीयत से फर्जी सूचना देने का मामला सामने आया है। पुलिस ने मामले का सफल अनावरण करते हुए दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार गुमशुदा मोहम्मद हाशिम पुत्र मोहम्मद नूर, निवासी अलीनगर जागीर, थाना स्वार, जनपद रामपुर द्वारा अपने अपहरण को लेकर UP-112 पर झूठी सूचना दी गई थी। बताया जा रहा है कि यह पूरी साजिश प्रेमिका के परिजनों को अपहरण के झूठे मुकदमे में फंसाने हेतु रची गई थी। मामले में दिनांक 01.04.2026 को आवेदक द्वारा थाने में प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिसमें बताया गया कि उनका पुत्र दिनांक 31.03.2020 की रात बिना बताए कहीं चला गया था और काफी तलाश के बावजूद नहीं मिला। इसके संबंध में थाना स्वार पर गुमशुदगी दर्ज की गई थी। प्रकरण की जांच के दौरान पुलिस को मामला संदिग्ध प्रतीत हुआ, जिस पर गहन छानबीन की गई। जांच में यह स्पष्ट हुआ कि युवक द्वारा जानबूझकर झूठी सूचना देकर लोगों को फंसाने की कोशिश की गई। पुलिस अधीक्षक सोमेंद्र मीणा के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना स्वार पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस द्वारा मामले में आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है।

जनसेवा का संकल्पः विधायक रामवीर सिंह ने सैकड़ों परिवारों को दिए राशन कार्ड

मंडल प्रभारी अवनीत कुमार शर्मा , मुंडापांडे/मुरादाबाद। कुंदरकी/मुंडापांडे आज क्षेत्र में पात्र लाभार्थियों को सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने हेतु आयोजित कार्यक्रम में कुंदरकी विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक ठाकुर रामवीर सिंह द्वारा राशन कार्ड वितरित किए गए। इस दौरान ब्लॉक मुंडा पांडे में 280 एवं ब्लॉक कुंदरकी में 260 पात्र परिवारों को राशन कार्ड प्रदान किए गए। विधायक ठाकुर रामवीर सिंह ने लाभार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र एवं प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है कि कोई भी पात्र व्यक्ति सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे। उन्होंने कहा कि पहले आमजन को राशन कार्ड बनवाने के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन अब सरकार की पारदर्शी व्यवस्था के माध्यम से योजनाओं का लाभ सीधे जनता तक पहुंचाया जा रहा है। विधायक ठाकुर रामवीर सिंह ने आगे कहा कि उनका संकल्प है कि कुंदरकी विधानसभा क्षेत्र का प्रत्येक पात्र परिवार सरकारी योजनाओं से जुड़कर लाभान्वित हो और क्षेत्र का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित हो। इस अवसर पर ब्लॉक प्रमुख मुंडा पांडे नवदीप यादव, ब्लॉक प्रमुख कुंदरकी गुलाम जिलानी, रब्बानी जिलानी, बिजेंद्र चौधरी विकासखंड अधिकारी राजेंद्र सिंह मंडल अध्यक्ष महेंद्र सिंह सैनी, नीरज चंद्रा, कुंदरकी मंडल अध्यक्ष संजय कश्यप, रतनपुर कलां मंडल अध्यक्ष बब्लू जाटव, बृजेश लोधी जिला मंत्री भाजपा अरविन्द ठाकुर, नसीम खान, अंकित चौहान, परशुराम सैनी, सरवर अली, चिराग अली, प्रधान फिरासत अली, फारूक अली, मनोज मास्टर, ठाकुर सोमिल सिंह रोहित सिंह रजनीश चौहान, संबंधित विभाग के अधिकारी, जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में लाभार्थी उपस्थित रहे।

ईरानी सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खामेनेई की शहादत पर महमूदाबाद हाउस में शोक सभा

लोकतंत्र की शान : अब्दुल्लाह खान ब्यूरो चीफ , महमूदाबाद सीतापुर : ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला सैय्यद अली खामेनेई और इजरायली हमले में शहीद हुए निर्दोष छात्रों की याद में कैसरबाग स्थित महमूदाबाद हाउस में एक विशाल शोक सभा का आयोजन किया गया। इस सभा का आयोजन प्रोफेसर अली खान राजा महमूदाबाद की ओर से किया गया।

प्रतिनिधि की उपस्थितिः इस सभा में ईरान के सर्वोच्च नेता के विशेष प्रतिनिधि और नई दिल्ली स्थित ईरान कल्चर हाउस के प्रमुख, अयातुल्ला डॉ. अब्दुल मजीद हकीम इलाही ने विशेष रूप से शिरकत की।

शोक और निंदाः सभा में उपस्थित वक्ताओं ने अमेरिका और इजरायल द्वारा किए गए हमलों की कड़े शब्दों में निंदा की। उन्होंने अयातुल्ला खामेनेई और मासूम छात्रों की शहादत पर गहरा दुख व्यक्त किया।

एकजुटता का संदेशः कार्यक्रम में विभिन्न धर्मों और क्षेत्रों के विद्वानों, कवियों, बुद्धिजीवियों और गणमान्य व्यक्तियों ने हिस्सा लिया।

प्रमुख वक्ताः सभा को मौलाना सैयद अरूजुल हसन मीसम, मौलाना फजल मन्नान और अन्य बुद्धिजीवियों ने संबोधित किया। एजाज जैदी ने फारसी में अपनी शोक कविता (नज़्म) प्रस्तुत की।

प्रोफेसर अली खान का वक्तव्यः "यह लड़ाई केवल इस्लाम की नहीं बल्कि पूरी मानवता की लड़ाई है। आज हर धर्म और विचारधारा के लोग ईरान के साथ खड़े हैं, जो इस बात का सबसे बड़ा सबूत है इस मौके पर सपा अल्पसंख्यक सभा के प्रदेश अध्यक्ष शकील नदवी, किला सेकरेट्री अनवार हुसैन,सफ़दर अमीन,मंसूर खान, सइद रहमान अंसारी, समेत सैकड़ो लोग मौजूद रहे

थाना क्षेत्र के ग्राम कुरथरा में पति-पत्नी के बीच हुइ मारपीट के दौरान पति के सिर मे गंभीर चोट लग जाने से पति की मौत हो गई सूचना पर पहुंची क्षेत्राधिकारी रामनगर गरिमा पंथ

लोकतंत्र की शान : अब्दुल्लाह खान ब्यूरो चीफ ,मसौली बाराबंकी। प्रभारी निरीक्षक अजय प्रकाश त्रिपाठी ने मौका मुआयना कर शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पत्नी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।

बुधवार की दोपहर ग्राम कुरथरा निवासी 32- वर्षीय मोहित पुत्र रामकुमार व उसकी पत्नी शिल्पा वर्मा के बींच किसी बात को लेकर विवाद हो गया बताया जा मोहित शराब का आदी था, जिसके कारण पति-पत्नी के बीच अक्सर विवाद होता रहता था। बुधवार दोपहर करीब 12 बजे घर पर ही दोनों के बीच कहासुनी हुई, जो जल्द ही मारपीट में बदल गई मारपीट के दौरान शिल्पा ने डंडे से मोहित के सिर पर हमला कर दिया सिर मे गंभीर चोट लगने के कारण मोहित की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही गाँव मे अफरातफरी मच गयी सूचना पर पहुंची मसौली पुलिस ने शव को कब्जे मे लेते हुए पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक मोहित के एक 14 वर्षीय पुत्र अभय उर्फ गोलू व 10 वर्षीय पुत्री सृष्टि हैं। पुलिस पत्नी को हिरासत मे लेकर मामले की गहनता से जांच कर रही है। क्षेत्राधिकार रामनगर गरिमा पंत, प्रभारी निरीक्षक अजय प्रकाश त्रिपाठी, वरिष्ठ उपनिरीक्षक शमशाद अली मौक़े पर पहुंच कर ग्रामीणों के बयान किया। प्रभारी निरीक्षक अजय प्रकाश त्रिपाठी ने बताया कि मृतक शराब का आदी था इसी को लेकर आये दिन विवाद होता रहता था आज भी दोनो के बींच इसी को लेकर विवाद हुआ और दोनो के बींच हुई मारपीट मे मोहित के सिर गंभीर चोट लगने से मौत हो गयी है।

भारतीय किसान संघ ने विभिन्न समस्याओं को लेकर D M के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा

लोक तंत्र की शान प्रवीण अग्रवाल जिला प्रभारी अमरोहा

हसनपुर/रहराः बुधवार को भारतीय किसान संघ गंगेश्वरी खण्ड की मासिक बैठक पंचायत भवन रहरा में आयोजित हुई जिसमें किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर विचार विमर्श किया गया और छः सूत्रीय ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय अमरोहा के नाम मुख्य खण्ड विकास अधिकारी रहरा को सौंपा गया, बैठक में चन्द्र प्रकाश शर्मा ने बताया कि हर घर नल हर घर जल योजना के अंतर्गत बनाई गई पानी की टंकिया जिले के अधिकांश गांवों में केवल सफेद हाथी की तरह खड़ी हैं उनको शीघ्र चालू कराया जाए जिससे ग्रामवासियों को शुद्ध पीने का पानी उपलब्ध हो सके और दूषित पानी से होने वाली बीमारियों से बचा जा सके, पानी की पाइप लाइन बिछाने के लिए सड़के खोदी गई थी वो अभी भी ठीक नहीं कराई गई है जिससे ग्रामीण वासियों को आने जाने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है उन्हें ठीक कराया जाए, बलॉक अध्यक्ष दीवांशु यादव ने बताया कि आपूर्ति विभाग द्वारा अनेक पात्र राशन कार्ड धारकों के राशन कार्ड काट दिए गए हैं कुछ राशन कार्ड धारकों के यूनिट काट दिए हैं जांच कराकर पात्र राशन कार्ड धारकों के राशन कार्ड पुनः चालू कराए जाए और कार्डो में यूनिटों को शीघ्र जोड़ा जाए, सरकार द्वारा की गई घोषणा कि बिना उपभोक्ता की अनुमति के स्मार्ट मीटर नहीं लगाए जाएंगे का स्वागत करता है, जिला उपाध्यक्ष डॉक्टर शिव चरन सैनी ने बताया कि किसान निराश्रित गौवंशीय पशुओं से परेशान है जिन्हें पकड़वाकर गौशालाओं में भिजवाया जाए, जिला जैविक प्रमुख एडवोकेट हरिप्रकाश राणा ने संगठन के विस्तार के बारे में विस्तार से बताया, जिला कोषाध्यक्ष धर्मपाल सिंह चौहान ने कहा कि गंगेश्वरी ब्लॉक के पोरारा में प्राचीन देवी मंदिर ओर बाबा हरिशंकर आश्रम के सामने जल भराव के कारण गंदगी फैल रही है समस्या का समाधान कराया जाए, इस बैठक में प्रचार प्रमुख अखिलेश शास्त्री, ब्लॉक उपाध्यक्ष कुमरपाल सिंह, संजय सिंह, डॉ लल्तू चौहान, मनोज शर्मा, पंकज चौहान ,मनोहर सिंह, तेजपाल सिंह सैनी, जितेंद्र सिंह, भूदेव सिंह आदि भारी संख्या में किसान भाई मौजूद रहे।

डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के चित्रकूट नोड को मिली गति, बीईएल को 75 हेक्टेयर भूमि का आवंटन

लोकतंत्र की शान

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के चित्रकूट नोड में 75 हेक्टेयर भूमि का आवंटन पत्र भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक मनोज जैन को सौंपा। यह पहल चित्रकूट डिफेंस नोड के व्यवस्थित एवं चरणबद्ध विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण संस्थागत कदम मानी जा रही है, जो प्रदेश में रक्षा विनिर्माण अवसंरचना को सुदृढ़ करने के साथ-साथ बुंदेलखंड क्षेत्र में औद्योगिक आधार के विस्तार को नई गति प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि यह पहल उत्तर प्रदेश को रक्षा विनिर्माण के क्षेत्र में एक सशक्त और विश्वसनीय पहचान दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, साथ ही बुंदेलखंड क्षेत्र के समग्र आर्थिक एवं औद्योगिक विकास को नई गति प्रदान करेगी। मध्य भारत में रणनीतिक रूप से स्थित चित्रकूट नोड अपनी उत्कृष्ट लॉजिस्टिक कनेक्टिविटी और भौगोलिक अनुकूलता के कारण रक्षा उत्पादन के लिए एक उभरता हुआ केंद्र बन रहा है, जो आने वाले समय में निवेश, रोजगार सृजन और उच्च-प्रौद्योगिकी आधारित औद्योगिक विकास का प्रमुख आधार सिद्ध होगा।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छठी उत्तर प्रदेश कृषि विज्ञान कांग्रेस 2026 का किया शुभारंभ

लोकतंत्र की शान

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित छठी उत्तर प्रदेश कृषि विज्ञान कांग्रेस-2026 का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कृषि क्षेत्र के समग्र विकास के लिए व्यापक व दूरदर्शी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि समय आ गया है कि कृषि को प्रोडक्शन से प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी से प्रॉफिटेबिलिटी और अंततः प्रॉफिटेबिलिटी से प्रॉस्पेरिटी तक ले जाया जाए। विकसित व आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना तभी साकार होगी, जब किसान समृद्ध होगा। उत्पादन बढ़ाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसे लाभप्रद और टिकाऊ बनाना आवश्यक है। प्रोडक्शन से प्रॉस्पेरिटी तक की यह यात्रा ही भविष्य का मार्ग तय करेगी और उत्तर प्रदेश इस दिशा में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए तैयार है।

सीमित संसाधनों में असाधारण प्रदर्शन-कि तीन दिवसीय इस आयोजन में कृषि के विभिन्न आयामों पर गंभीर विचार-विमर्श होगा, जिसमें जमीनी स्तर के अनुभवों, नवाचारों और सफल प्रयोगों को साझा किया जाएगा। यह मंच केवल चर्चा का नहीं, बल्कि ठोस एक्शन प्लान तैयार करने का माध्यम बनना चाहिए, जिससे किसानों को वास्तविक लाभ मिल सके।

मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश की कृषि क्षमता का उल्लेख करते हुए कहा कि यह राज्य देश की लगभग 16-17 प्रतिशत आबादी का निवास स्थान है, जबकि यहां केवल 11 प्रतिशत कृषि योग्य भूमि उपलब्ध है। इसके बावजूद यूपी देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन में लगभग 21 प्रतिशत का योगदान देता है। यह योजनाबद्ध प्रयासों, किसानों की मेहनत और प्रभावी नीतियों का परिणाम है। राज्य ने कृषि विकास दर को 8 प्रतिशत से बढ़ाकर लगभग 18 प्रतिशत तक पहुंचाने में सफलता प्राप्त की है, जो एक उल्लेखनीय उपलब्धि है।

खून से लथपथ मिली युवक की लाश, परिजनों ने लगाया ट्रैक्टर चालक पर कुचलकर हत्या का आरोप

लोक तंत्र की शान प्रवीण अग्रवाल जिला प्रभारी अमरोहा

हसनपुर/ सैद नंगलीः बुधवार को थाना क्षेत्र के गांव दमगढ़ी खुर्द गांव में एक 18 वर्षीय युवक का शव उझारी दमगड़ी लिंक मार्ग पर सड़क किनारे संदिग्ध परिस्थितियों में मिला, मृतक के परिजनों ने गांव के ही एक ट्रैक्टर चालक पर युवक को घर से बुलाकर ले जाने और ट्रैक्टर से कुचल कर हत्या करने का गंभीर आरोप लगाया है, बता दें कि 18 वर्षीय मुकेश पुत्र भूरा बुधवार श्याम करीब 4 बजे गांव के एक ट्रैक्टर चालक के साथ उझारी जाने की बात कह कर घर से निकला था कुछ ही समय बाद उसका उझारी दमगड़ी लिंक मार्ग पर एक आम के बाग के पास लहू लूहान हालत में सब मिला जिससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई, घटना के बाद ट्रैक्टर लेकर चालक मौके से फरार हो गया सूचना मिलने पर मृतक के परिजन घटनास्थल पर पहुंचे और उन्होंने आरोप लगाया कि मुकेश की सोची समझी साजिश के तहत ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या की गई है आक्रोशित परिजनों ने ट्रैक्टर चालक के खिलाफ तत्काल मुकदमा दर्ज करने की मांग करते हुए शव उठाने से इनकार कर दिया और मौके पर विरोध प्रदर्शन किया, घटना की गंभीरता को देखते हुए थाना अध्यक्ष विकास कुमार सेहरावत पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे तथा हसनपुर पुलिस क्षेत्राधिकारी पंकज कुमार त्यागी ने भी घटनास्थल पर पहुंच कर निरीक्षण किया, पुलिस द्वारा कड़ी कार्रवाई और आरोपी चालक के विरुद्ध कार्यवाही करने के ठोस आश्वासन के बाद ही परिजन शांत हुए और शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाने दिया, मुकेश अपने तीन भाइयों और एक बहन में सबसे बड़ा था, थाना अध्यक्ष विकास सहरावत ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, परिजनों की तहरीर के आधार पर अग्रिम कार्यवाही की जाएगी तथा मामले की पुलिस गहनता से जांच कर रही है और आरोपियों को किसी भी कीमत पर बक्सा नहीं जाएगा।

खुद को पत्रकार बताने वाला निकला झोलाछाप, क्लीनिक सील

लोक तंत्र की शान प्रवीण अग्रवाल जिला प्रभारी अमरोहा

हसनपुरः बुधवार को तहसील क्षेत्र के आदमपुर में स्थित ढवारसी बस स्टैंड पर पत्रकारिता की आड़ में चल रहे अवैध इलाज के खेल का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। यहां एक युवक खुद को पत्रकार बताकर बिना किसी मान्यता प्राप्त डिग्री के क्लीनिक संचालित कर रहा था और मरीजों का इलाज कर उनकी सेहत से खिलवाड़ कर रहा था। मामले की जानकारी सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने त्वरित कार्रवाई करते हुए क्लीनिक को सील कर दिया। बताया जा रहा है कि आरोपी न केवल झोलाछाप डॉक्टर के रूप में काम कर रहा था, बल्कि अन्य अवैध क्लीनिक संचालकों के खिलाफ खबरें प्रकाशित कर उनसे अवैध वसूली भी करता था। वह खुद को पत्रकार बताकर अधिकारियों पर दबाव बनाने की कोशिश करता था, जिससे क्षेत्र में उसका प्रभाव बना हुआ था। सूत्रों के मुताबिक, आरोपी संभल जनपद के एक गांव का निवासी है और उस पर पहले भी कार्रवाई हो चुकी है। यहां तक कि उसे संभल पुलिस द्वारा जिला बदर भी किया जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद वह आदमपुर में अपनी गतिविधियां चला रहा था। मामले की सूचना मिलने पर रहरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी डॉ. शशांक चौधरी के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मौके पर छापेमारी की। टीम के पहुंचते ही आरोपी मौके से फरार हो गया। जांच के दौरान क्लीनिक पूरी तरह अवैध पाया गया, जहां कोई वैध दस्तावेज या लाइसेंस उपलब्ध नहीं था। छापेमारी के दौरान एक अवैध डेंटल क्लीनिक समेत कुल चार क्लीनिकों की जांच की गई, जिनमें सभी बिना पंजीकरण और आवश्यक कागजातों के संचालित होते मिले। स्वास्थ्य विभाग ने तत्काल कार्रवाई करते हुए सभी क्लीनिकों को सील कर दिया। साथ ही क्लीनिक संचालकों जितेंद्र, मेराजुल हसन, हरिओम और फहीम के खिलाफ संबंधित थाने में तहरीर देकर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। स्थानीय लोगों में जहां भय का माहौल है, वहीं अवैध क्लीनिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई को लेकर संतोष भी देखा जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि ऐसे फर्जी और अवैध क्लीनिकों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। सीएचसी प्रभारी डॉ. शशांक चौधरी ने बताया कि आदमपुर में बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे क्लीनिकों पर सख्त कार्रवाई की गई है और आगे भी इस तरह के मामलों में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने लोगों से अपील की है कि इलाज के लिए केवल पंजीकृत और प्रमाणित चिकित्सकों के पास ही जाएं, ताकि किसी भी प्रकार के खतरे से बचा जा सके।

कांग्रेस की पूर्व केंद्रीय मंत्री मोहसीना क़िदवई के निधन से बाराबंकी ज़िलें मे शोक की लहर

लोकतंत्र की शान, अब्दुल्लाह खान ब्यूरो चीफ

बाराबंकी : कांग्रेस की कद्दावार नेत्री मोहसिना किदवई का 94 वर्ष की उम्र में निधन, पूर्व केंद्रीय मंत्री मोहसिना किदवई हमारे बीच नहीं रहीं, नोएडा के अस्पताल में ली आखिरी सांस। राजनीतिक जगत में शोक की लहर, राजीव गांधी सरकार में रही थीं अहम मंत्री। लोकसभा और राज्यसभा की रह चुकी थीं सदस्य। शाम 5 बजे निजामुद्दीन में किया जाएगा सुपुर्देखाक।

मोहसिना किदवई (1 जनवरी 1932 में जन्मी, 8 अप्रैल 2026 को हुआ निधन)-भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक वरिष्ठ और कदवार नेता थीं, जिन्होंने 6 दशक से अधिक समय तक राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाई। इंदिरा और राजीव गांधी सरकार में केंद्रीय मंत्री रहीं किदवई का राजनीतिक करियर बेदाग रहा। उन्होंने मेरठ और बाराबंकी से लोकसभा सांसद के रूप में प्रतिनिधित्व किया। मोहसिना किदवई के बारे में मुख्य

बातें: निधनः आज 8 अप्रैल 2026 को 94 वर्ष की आयु में नोएडा में निधन।

राजनीतिक करियरः उत्तर प्रदेश विधान परिषद (1960) से शुरुआत, 3 बार लोकसभा और 2 बार राज्यसभा सदस्य। केंद्रीय मंत्री पदः इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के कार्यकाल में मंत्री (स्वास्थ्य, परिवार कल्याण आदि)। पार्टी में भूमिकाः कांग्रेस वर्किंग कमेटी और सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की सदस्य रही उनका पूरा जीवन समाजसेवा मे ही कटा है वह एक दृढ़ धर्मनिरपेक्ष नेता थीं, जिनका नाम कभी भ्रष्टाचार के आरोपों में नहीं आया।।

दबंगों के होसले बुलंद छेड़छाड़ का विरोध करने पर महिला का सर फाड़ा महिला ने पुलिस से की शिकायत

लोकतंत्र की शान, मंडल प्रभारी अवनीत कुमार शर्मा

जनपद मुरादाबाद के थाना मूंढापांडे क्षेत्र की ग्राम पंचायत करनपुर में सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार एक महिला ने एक व्यक्ति पर आरोप लगाया है कि वह अपने घर से मंगलवार रात्रि के 8 बजे दुकान से कुछ सामान लेने के लिएं जा रही थी कि रास्ते में बेठे एक दबंग ने महिला की ओर गंदे इशारे करके अश्लील गाने गाने लगा जिसका विरोध करने पर दबंग व्यक्ति ने महिला को पीटते हुए उस का सर फाड़ दिया। जिसकी शिकायत लेकर महिला करनपुर पुलिस चौकी में पहुंची महिला की शिकायत के अनुसार पुलिस जांच में जुट गई है। मगर कुछ सफेदपोश लोग मामले को शांत कराने में लगे हैं। इस विषय में जब हमारी बात चौकी इंचार्ज से हुई तो उन्होंनें बताया कि मामले की जांच चल रही है जांच में जो भी साक्षे निकलकर सामने आते हैं उसी के आधार पर कार्यवाही की जाएगी।

जनसमस्याओं को लेकर राष्ट्र सेवी संगठन का जोरदार प्रदर्शन, एसडीएम को सौंपा ज्ञापन

लोक तंत्र की शान प्रवीण अग्रवाल जिला प्रभारी अमरोहा

हसनपुरः बुधवार को नगर और ग्रामीण क्षेत्र की ज्वलंत समस्याओं को लेकर राष्ट्र सेवी संगठन के कार्यकर्ताओं ने तहसील परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया। संगठन के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन उपजिलाधिकारी (एसडीएम) कार्यालय में सौंपकर जल्द कार्रवाई की मांग की।प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्ण कुमार शर्मा ने प्रदेश सरकार की नीतियों के पालन में स्थानीय प्रशासन की ढिलाई पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने 1 अप्रैल से सरकारी केंद्रों पर गेहूं की खरीद शुरू करने के आदेश दिए थे, लेकिन हसनपुर क्षेत्र में अब तक खरीद प्रक्रिया ठप पड़ी है। किसान अपनी उपज लेकर परेशान हैं।इसके अलावा, उन्होंने खाद्य विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि क्षेत्र के पात्र गरीबों के राशन कार्ड काट दिए गए हैं। उन्होंने मांग की कि वंचित परिवारों के नाम तुरंत सूची में जोड़े जाएं ताकि उन्हें सरकारी राशन मिल सके। संगठन ने अन्य स्थानीय समस्याओं को भी प्रमुखता से उठाया। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि लगाए गए स्मार्ट मीटर गलत रीडिंग दे रहे हैं, जिससे उपभोक्ताओं पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। हसनपुर नगर में प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्र लाभार्थियों को लाभ न मिलने पर रोष प्रकट किया गया। हसनपुर से भदौरा को जाने वाला मार्ग पूरी तरह जर्जर हो चुका है, जिससे आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं।प्रशासन की अनदेखी के चलते जनता मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रही है। अगर गेहूं की खरीद तुरंत शुरू नहीं हुई और जर्जर सड़कों की मरम्मत न की गई, तो संगठन आंदोलन के लिए बाध्य होगा।इस अवसर पर मुख्य रूप से मोनू अग्रवाल, गजराज सिंह , भूपेंद्र सिंह, सुरभित गुप्ता एड, संजीव कुमार,सहित संगठन के दर्जनों कार्यकर्ता और स्थानीय नागरिक मौजूद रहे। प्रशासन ने ज्ञापन लेकर उचित वैधानिक कार्रवाई का आश्वासन दिया है।

संक्षिप्त समाचार

वैशाली में युवक ने जहर खाकर की आत्महत्या, मरने से पहले वीडियो बनाकर पत्नी को भेजा

हाजीपुर। वैशाली में रात युवक ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। मरने से पहले उसने वीडियो बनाकर पत्नी को भेजा। घटना पातेपुर थाना क्षेत्र के खेसराही गांव की है। मृतक की पहचान स्वर्गीय राम शीरताज सिंह के बेटे महाकांत सिंह के रूप में हुई है। मृतक के चचेरे भाई मुकेश कुमार ने बताया कि महाकांत ने 11 साल पहले हाजीपुर के सांची पट्टी में प्रेम विवाह किया था। शादी के बाद से उनकी पत्नी रिशु देवी कथित तौर पर उन पर घर की पूरी जमीन बेचकर हाजीपुर में रहने का दबाव बना रही थीं। महाकांत इस बात से सहमत नहीं थे, वो हर बार इनकार कर देते थे। उन्हें अपने परिवार को छोड़कर नहीं जाना था। इस विवाद के कारण महाकांत की पत्नी बार-बार अपने मायके चली जाती थीं और पिछले तीन साल से वह वहीं रह रही थीं। मंगलवार रात करीब 9 बजे महाकांत सिंह ने अपने मोबाइल पर एक वीडियो बनाते हुए जहर खा लिया। उन्होंने यह वीडियो अपनी पत्नी को मोबाइल पर भेजा था। हालांकि, महाकांत की पत्नी ने इस घटना की जानकारी अपने ससुराल वालों को नहीं दी। ग्रामीणों में से कुछ लोगों को वह वीडियो मिला, जिसके बाद उन्होंने महाकांत के परिवार को सूचित किया। परिवार के सदस्य जब महाकांत के कमरे में पहुंचे, तो उन्हें वह मृत अवस्था में मिले। पत्नी को घटना की जानकारी होने के बावजूद वह तुरंत ससुराल नहीं पहुंचीं और बुधवार सुबह करीब 8 बजे वहां आईं। इसके बाद पातेपुर थाने की पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस तत्काल घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए हाजीपुर सदर अस्पताल भेज दिया गया है। महाकांत सिंह अपने तीन भाइयों में सबसे छोटे थे। उनके परिवार में दो बेटे और एक बेटी हैं। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है।

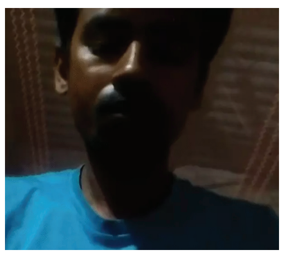

साली से शादी की जिद पर टावर पर चढ़ा युवक, वैशाली में 4 घंटों तक चला ड्रामा, कूदने की दी धमकी

हाजीपुर। वैशाली जिले में एक युवक अपनी साली से शादी की जिद पर एक बिजली टावर पर चढ़ गया। उसने टावर से कूदने की धमकी दी, जिसके बाद इलाके में 4 घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा चला और भारी भीड़ जमा हो गई। यह घटना चांदपुरा थाना क्षेत्र के धर्मपुर रामराय पंचायत में हुई। युवक की पहचान जगा शर्मा के पुत्र के रूप में हुई है। वह एयरटेल के एक टावर पर चढ़ा था और लगातार अपनी साली से शादी कराने की मांग कर रहा था। इस दौरान राज कुमार ने कहा कि मेरा मांग है कि मुझे प्यार चाहिए वो मुझे प्यार करें। वो लड़की कोई और नहीं मेरी साली है। उसको रखने से मेरी पत्नी को कोई दिक्कत नहीं है। दो बच्चे मुझे भी है, दो बच्चे साली को भी है। "मैं चारों बच्चे को पालने के लिए तैयार हूं" मेरा ससुराल जंदाहा शाहपुर गांव में है। 2015 में मेरी पहली शादी हुई थी। उसके दो तीन साल बाद साली से प्यार हो गया। हमदोनों ने शादी भी कर ली थी, फिर भी उसकी शादी कही और कराई गई। उसने मुझे प्यार का फर्ज निभाने का वचन दिया था। लेकिन बाद में वो मुकर गई। मुझे साली चाहिए मुझें कुछ भी नहीं चाहिए। उसने कहा कि मेरी पत्नी भी कहती है मुझे बहन चाहिए। जब मेरी साली आ जाएगी तब नीचे उतर जाएंगे। मेरी पत्नी बार-बार बेहोश हो रही है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे साली चाहिए। सूचना मिलने पर देसरी और चांदपुरा थाना की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस और स्थानीय लोगों ने युवक को नीचे उतारने के लिए घंटों तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। युवक को समझाने-बुझाने का प्रयास किया गया। काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने युवक को सुरक्षित टावर से नीचे उतारा। इस घटना के कारण क्षेत्र में तनाव का माहौल बन गया था, जिसे पुलिस ने शांत किया।

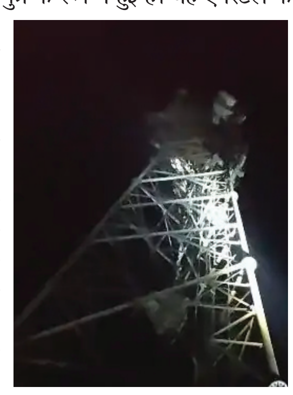

शराब शराब तस्कर अरेस्ट, बिहार एसटीएफ ने रेलवे स्टेशन से दबोचा, 16 मामले है दर्ज, 10 हजार कैश जब्त

मुजफ्फरपुर। बिहार पुलिस की विशेष कार्य बल (STF) ने मुजफ्फरपुर के कुख्यात शराब माफिया राजा साह उर्फ राजा गुप्ता को गिरफ्तार किया है। हथौड़ी थाने का वांछित बदमाश मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन परिसर से पकड़ा गया। STF को गुप्त सूचना मिली थी कि लंबे समय से फरार चल रहा राजा साह रेलवे स्टेशन के पास मौजूद है। इसी सूचना के आधार पर 07/08 अप्रैल 2026 की दरम्यानी रात STF की टीम ने जाल बिछाकर उसे गिरफ्तार किया। राजा साह हथौड़ी थाना क्षेत्र के बेरई का निवासी है और उसके पिता का नाम राम बिनोद साह है। राजा साह के खिलाफ मुजफ्फरपुर के अलग-अलग थानों में 16 से अधिक मामले दर्ज हैं। ये मामले शराब तस्करी के अलावा आर्म्स एक्ट के तहत भी हैं। वह हथौड़ी थाना कांड संख्या 219/25 में बिहार मद निषेध और उत्पाद अधिनियम की धारा 30(ए) के तहत फरार था। गिरफ्तारी के समय पुलिस ने राजा साह के पास से 10,695 रुपये नकद, दो मोबाइल फोन, तीन अतिरिक्त सिम कार्ड, दो क्रेडिट कार्ड, एक घड़ी और चांदी जैसी धातु की दो अंगूठियां बरामद की हैं। STF ने राजा साह को आगे की कार्रवाई के लिए संबंधित थाने को सौंप दिया है। पुलिस उसके नेटवर्क में शामिल अन्य लोगों और बरामद सिम कार्डों के उपयोग की जांच कर रही है। इस गिरफ्तारी को मुजफ्फरपुर में शराब माफियाओं के नेटवर्क को तोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

मुजफ्फरपुर में आभूषण कारोबारी से छिनतई, जेवर से भरा झोला छीनकर भागे बाइक सवार बदमाश

मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में मंगलवार की देर रात आभूषण कारोबारी से छिनतई हुई। घटना मीनापुर थाना क्षेत्र के पानापुर ओपी के ओवरब्रिज के नीचे हुई। बाइक सवार बदमाश आभूषण कारोबारी से सोने-चांदी के जेवर छीनकर भाग गए। जेवर में 260 ग्राम सोना और 2 किलो चांदी के आभूषण शामिल थे। बाजार मूल्य के हिसाब से इसकी कीमत करीब 40 लाख रुपए बताई जा रही है। घटना को अंजाम देकर बदमाश एनएच के रास्ते मोतीपुर की दिशा में भाग गए। महज 5 मिनट के अंदर बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। सूचना मिलते ही पानापुर ओपी की पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन शुरू की। घटना की गंभीरता को देखते हुए एसडीपीओ पूर्वी वन अलय वत्स भी मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गए। पीड़ित कारोबारी कांटी थाना क्षेत्र के वीरपुर निवासी सुरेंद्र प्रसाद है। उनकी पानापुर बड़ा बाजार में आभूषण की दुकान है। कारोबारी के अनुसार, मंगलवार को वे दुकान बंद कर अकेले बाइक से घर लौट रहे थे। इसी दौरान पानापुर ओवरब्रिज के नीचे 2 बाइक पर सवार 4 बदमाश आए और उन्हें घेरकर झोले में रखे सोने-चांदी के आभूषण लूट लिए। झोला बाइक की टंकी पर रखा हुआ था। पीड़ित कारोबारी ने बदमाशों का काफी दूर तक पीछा भी किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। वापस लौटकर उन्होंने ओपी पुलिस को घटना की जानकारी दी। पुलिस ने बदमाशों की पहचान के लिए चौक और आसपास की कई दुकानों में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले। एसडीपीओ पूर्वी वन अलय वत्स ने बताया कि बाइक की टंकी पर रखे आभूषण से भरे झोले को लेकर बदमाश फरार हो गए। घटनास्थल पर पहुंचकर जांच की गई है। कारोबारी से पूछताछ कर पूरी जानकारी ली गई है और बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि घटना की जांच जारी है, हालांकि प्रथम दृष्टया मामला संदिग्ध प्रतीत होता है। जांच के बाद ही पूरी स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

पटना-बांका समेत 11 जिलों में बारिश, पूरे बिहार में अलर्ट

◆ 12 में हेवी रेन की संभावना, ठनका गिरने की चेतावनी

एजेंसी, पटना

पटना समेत बिहार के कई जिलों में मौसम बदला हुआ है। प्रदेश के ज्यादातर जिलों में सुबह से बादल छाए हैं। पटना में सुबह बूंदाबांदी के बाद दोपहर में तेज बारिश हुई। गोपालगंज, बेगूसराय, बांका समेत 11 जिलों में भी तेज बारिश हो रही है।

मौसम विभाग ने आज 12 में ऑरेंज और 26 जिलों में यलो अलर्ट जारी किया है। ऑरेंज अलर्ट वाले जिलों में तेज आंधी, गरज-चमक के साथ भारी बारिश, बिजली गिरने और कहीं-कहीं ओले की भी आशंका जताई है। इन जिलों में हवा की रफ्तार 60 किमी प्रति घंटा रह सकती है। यलो अलर्ट वाले जिलों में हल्की से मध्यम बारिश, गरज-चमक और तेज हवाओं की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार, यह खराब मौसम अभी दो दिनों तक जारी रहेगा। खासकर आज और कल इसका असर ज्यादा देखने को मिलेगा। इस दौरान कई जगहों पर अचानक तेज बारिश, बिजली गिरने और आंधी की स्थिति बन सकती है।

ऐसा मौसम क्यों बना हुआ है: इस असामान्य मौसम के पीछे कई कारण एक साथ काम कर रहे हैं। सबसे पहले, पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत में सक्रिय है, जो मौसम में बदलाव ला रहा है। इसके साथ ही बंगाल की खाड़ी से नमी वाली हवाएं लगातार बिहार की ओर आ रही हैं। इन दोनों के मिलने से वातावरण में नमी बढ़ी और अस्थिरता पैदा हो गई है। इसके अलावा, क्षेत्र में एक चक्रवाती परिसंचरण भी बना हुआ है, जो बादलों के तेजी से बनने और गरज-चमक के साथ बारिश को बढ़ावा दे रहा है। यही वजह है कि आंधी, वज्रपात और ओलावृष्टि जैसी स्थितियां बन रही हैं।

लोगों और किसानों के लिए जरूरी सलाह: मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि खराब मौसम के दौरान अनावश्यक रूप से बाहर न निकलें। वज्रपात के समय खुले स्थान, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहें और सुरक्षित जगह पर शरण लें। किसानों को सलाह दी गई है कि वे तैयार फसलों की जल्द कटाई कर लें और सुरक्षित भंडारण करें। खेत में रखी फसल को ढंककर रखें ताकि बारिश और ओलावृष्टि से नुकसान कम हो सके।

बेटे को घुड़सवारी सिखा रहे अनंत सिंह, दे रहे रहे ट्रेनिंग

बोले- आराम से दौड़ाओ, बेटे को आईपीएस बनाना चाहते हैं

एजेंसी, पटना

मोकामा से जदयू विधायक अनंत सिंह इन दिनों अपने बेटे को घुड़सवारी की ट्रेनिंग दे रहे हैं। बेटे अभिनव को घुड़सवारी सिखाने का वीडियो भी सामने आया है। बताया जा रहा है कि यह वीडियो पटना स्थित उनके आवास का है। वीडियो में अनंत सिंह कुछ लोगों के साथ कुर्सी पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। इसी दौरान अभिनव सफेद घोड़े पर सवार होकर आता है और उसे रोकने की कोशिश करता है। इस पर अनंत सिंह कहते हैं, "धीरे-धीरे, आराम से।"

बेटे को घुड़सवारी सिखाने का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें अभिनव काले घोड़े पर सवार नजर आ रहा है। इस वीडियो में भी अनंत सिंह बेटे को घोड़े पर संतुलन बनाने के गुर सिखाते दिख रहे हैं। अनंत सिंह को घोड़ों का बहुत शौक है। उनके पास कई महंगे घोड़े हैं। जिस काले घोड़े के साथ अभिनव दिख रहे हैं, वो अनंत सिंह के महंगे घोड़ों में से एक है।

जेल से निकलने के बाद अपने पसंदीदा घोड़े के साथ दिखे थे अनंत सिंह: 28 मार्च को अनंत सिंह पटना वाले अवास के बाहर अपने पसंदीदा काले रंग के घोड़े की लगाम थामे दिखे। इसका वीडियो भी सामने आया। वीडियो में दिख रहा है कि अनंत सिंह घोड़े की लगाम थामे कह रहे हैं- चल तो, घोड़ा चलने लगता है। फिर कहते हैं आगे बढ़ तो, घोड़ा आगे बढ़ने लगाता है।

पटना का मोस्ट वांटेड शिव गोप अरेस्ट एसटीएफ ने जक्कनपुर से दबोचा

एजेंसी, पटना

❐ टॉप-10 अपराधियों में शामिल, हत्या सहित कई मामलों में था फरार

पटना पुलिस और STF को बड़ी सफलता मिली है। राजधानी के टॉप-10 अपराधियों में शामिल शिव गोप को जक्कनपुर इलाके से गिरफ्तार कर लिया गया है। उस पर हत्या, लूट और रंगदारी समेत दो दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस के अनुसार, शिव गोप को वर्ष 2018 में हुई एक हत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया है। लंबे समय से उसकी तलाश चल रही थी।

दीपक मेहता हत्याकांड में भी नाम: जेडीयू नेता और दानापुर नगर उपाध्यक्ष दीपक मेहता हत्याकांड में भी शिव गोप का नाम सामने आया था। इस हत्याकांड में शामिल शूटर ने शिव गोप और रवि गोप का नाम लिया था। 28 मार्च 2022 को कार्बाइन से दीपक मेहता की गोली मारकर हत्या की गई थी। उस समय शूटर्स ने बताया था कि जमीन विवाद में रवि और शिव ने 7 लाख की सुपारी देकर हत्या कराई है।

2024 में श्मशान घाट से हुई थी गिरफ्तारी: शिव को वर्ष 2024 में पूर्व राजद विधायक रीतलाल यादव के पिता के दाह संस्कार में शामिल होने के लिए दीघा घाट आया था। इसी दौरान STF और पटना पुलिस ने उसे दबोच लिया था। सूत्रों के मुताबिक, 90 के दशक में मीठापुर समेत पटना के कई इलाकों में शिव गोप का दबदबा था। उसके खिलाफ पटना के अलग-अलग थानों में संगीन अपराधिक मामले दर्ज हैं। करीब 21 साल जेल में रहने के बाद बाहर निकलते ही वह दोबारा अपराध की दुनिया में सक्रिय हो गया। उसके मजबूत नेटवर्क हैं। पुलिस के अनुसार, जेल से छूटने के बाद शिव गोप अपराध करने के लिए शूटर और अपराधी मुहैया कराता था।

पटना ईओयू दफ्तर पहुंचे सहरसा डीआरडीए निदेशक वैभव कुमार, एक घंटे से पूछताछ जारी

एजेंसी, पटना

बिहार में आय से अधिक संपत्ति के मामलों में आर्थिक अपराध इकाई (EOU) की कार्रवाई तेज हो गई है। EOU ने सहरसा के डीआरडीए निदेशक वैभव कुमार को पूछताछ के लिए तलब किया, जिसके बाद आज बुधवार को वे पटना स्थित EOU दफ्तर पहुंचे हैं। पिछले एक घंटे से EOU की पांच सदस्यीय टीम उनसे पूछताछ कर रही है। यह कार्रवाई आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में की जा रही है। इससे पहले भी मंगलवार को EOU ने उन्हें बुलाया था, लेकिन वे उपस्थित नहीं हुए थे।

EOU ने छह ठिकानों पर की छापेमारी: पिछले मंगलवार को EOU की टीम ने मुजफ्फरपुर और सहरसा सहित कुल छह ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस दौरान अधिकारियों को 16 संपत्तियों से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले। छापेमारी में पटना और मुजफ्फरपुर में स्थित कई कीमती जमीन के प्लॉट सहित अन्य संपत्तियों के दस्तावेज बरामद हुए हैं।

2.41 करोड़ आय से अधिक संपत्ति का मामला: जांच एजेंसियों के मुताबिक, वैभव कुमार के खिलाफ 2.41 करोड़ रुपये की आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मामला पहले ही दर्ज किया जा चुका था। छापेमारी में मिले साक्ष्य इस मामले को और मजबूत कर रहे हैं। जांच में यह भी सामने आया है कि वैभव कुमार ने मुजफ्फरपुर के हरिशंकर मनियारी गांव में 'ऐश्वर्या मैक्स ग्लो आईटीआई' नाम से एक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किया है। इस संस्थान के निर्माण और वर्कशॉप पर लगभग डेढ़ करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। यह संस्थान एक चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से संचालित हो रहा है, जिसमें उनके पिता को प्रबंधक बनाया गया है। संस्थान के लिए एक बीघा जमीन वार्षिक लीज पर ली गई है, जिसका उपयोग खेल मैदान के रूप में किया जा रहा है।

❐ 2.41 करोड़ की आय से अधिक संपत्ति का मामला

बैंक खाते, जमीन और निवेश पर ईओयू की नजर: छापेमारी के दौरान वैभव कुमार और उनकी पत्नी के बैंक खातों में 20 लाख रुपए से अधिक की राशि जमा मिलने की पुष्टि हुई है। इसके बाद ईओयू ने संबंधित खातों और लॉकर को फ्रीज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जांच एजेंसी को यह भी पता चला है कि वैभव कुमार ने अपने स्वजनों के नाम पर पटना और मुजफ्फरपुर में 16 भूखंड खरीद रखे हैं। इसके अलावा उनके पास दो वाहन भी पाए गए हैं, जिनमें एक टाटा नेक्सन शामिल है। इतना ही नहीं, ईओयू को शेयर बाजार और बीमा कंपनियों में निवेश से जुड़े दस्तावेज भी मिले हैं, जो उनकी आय और संपत्ति के बीच असंतुलन की ओर इशारा करते हैं।

स्नेक बाइट वाले एंटी वेनम का नशे में इस्तेमाल, 1 करोड़ की खेप जब्त, सरकारी कर्मियों की भूमिका की जांच

एजेंसी, पटना

राजधानी पटना के अगमकुंआ इलाके में नशीली दवाओं के बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ है। भगवत नगर स्थित एक मकान में छापेमारी कर पुलिस ने करीब 1 करोड़ रुपए की नशीली दवाएं बरामद की हैं। 6 अप्रैल को गुप्त सूचना के आधार पर की गई कार्रवाई में पुलिस को 9,370 यूनिट नशीले इंजेक्शन और 5,537 यूनिट कोडीन युक्त कफ सिरप मिले हैं। इसके अलावा एंटीबायोटिक और एंटी-वेनम जैसी दवाएं भी बरामद की गईं।

गुप्त सूचना की गई छापेमारी: गुप्त सूचना के आधार पर 6 अप्रैल को पटना पुलिस ने भगवत नगर इलाके में स्थित अजय कुमार के मकान में छापेमारी की थी। इस दौरान मकान से एक करोड़ की नशीली दवा बरामद की गई थी। इसमें विभिन्न कंपनियों के लगभग 9,370 यूनिट नशीले इंजेक्शन, विभिन्न कंपनियों के कोडीन युक्त कफ सिरप के लगभग 5,537 यूनिट शामिल थे। मकान से कदमकुआं का रहने वाला जयंत कुमार (35 वर्ष) पकड़ा गया था।

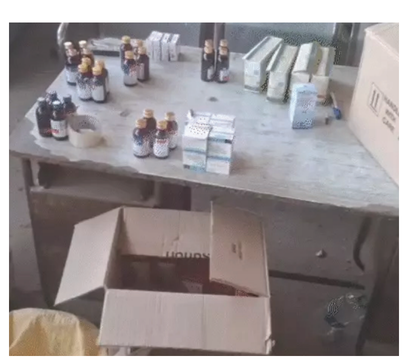

नशीली दवा के साथ एक गिरफ्तार, दूसरा फरार: पटना पूर्वी एसपी परिचय कुमार ने बताया कि, 'जयंत कुमार और नीरज कुमार ने किराए पर अजय कुमार से रुम लिया था। जयंत को गिरफ्तार कर लिया गया है। जयंत शराब के कारोबार में पूर्व में जेल जा चुका है। जेल से छूटने के बाद नीरज के साथ मिलकर नशीली दवा की कारोबार पर शामिल हो गया था। अलग-अलग कंपनी के कोडिन युक्त कफ सिरप (गुजरात, हिमाचल और उत्तराखंड निर्मित) मिले हैं। बहुत सारी स्नैक बाइट की एंटी वैनम, एंटी बायोटीक दवा मिली है।'

◆ नेपाल बॉर्डर तक फैला नेटवर्क

दो FIR दर्ज, ट्रांसपोर्ट कंपनी भी कार्रवाई संभव: पूर्वी एसपी कुमार ने बताया कि, 'इस मामले में एनडीपीएस एक्ट और सरकारी दवा की चोरी समेत दो FIR दर्ज की गई है। इसमें कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट कंपनी की भी संलिप्तता है। इसकी भी जांच की जा रही है। भूमिका निकलकर सामने आने पर उन पर भी केस दर्ज किया जाएगा।'

10 सालों से अवैध दवा का कारोबार: नीरज अपने पार्टनर कुंदन और जयंत के साथ मिलकर पिछले 10 सालों से नशीली दवा का कारोबार कर रहा है। सप्लाई चैन नेपाल बॉर्डर इलाके तक फैला है। पुलिस जांच में यह बात निकाल कर सामने आई है कि नशे के तौर पर एंटी वेनम का भी इस्तेमाल हो रहा था। जयंत ने पुलिस की पूछताछ में बताया है कि, नीरज अस्पताल और सरकारी कर्मियों की मदद से एक्सपायर दवा खरीदना था और उसकी भी रीपैकेजिंग करके फिर इस्तेमाल करता था।

पटना के अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट में मजदूरों का हल्लाबोल

एजेंसी, पटना

पटना के दनियावां स्थित अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड (पाटलिपुत्र सीमेंट वर्क्स) के मुख्य गेट पर बुधवार को सैकड़ों मजदूरों ने विरोध प्रदर्शन किया। अपनी मांगों को लेकर मजदूरों ने कामकाज ठप कर दिया है। मजदूरों की मुख्य मांग केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन लागू करना और मजदूरी में बढ़ोतरी करना है। उनका कहना है कि मौजूदा वेतन में परिवार का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा है।

783 की जगह मिल रहे 436 रुपए- प्रमोद प्रसाद: प्रदर्शन में शामिल मजदूर प्रमोद प्रसाद ने बताया कि नियमानुसार उन्हें प्रतिदिन 783 रुपए मिलने चाहिए, लेकिन उन्हें केवल 436 रुपए ही दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वेतन से PF कटने और छुट्टियों का पैसा काटे जाने के कारण हाथ में आने वाली राशि और कम हो जाती है।

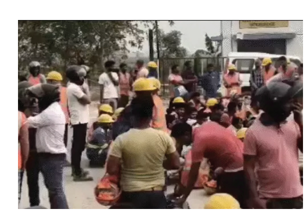

प्रबंधन पर शोषण का आरोप: मजदूरों ने आरोप लगाया कि जब वे अपनी मांग उठाते हैं, तो प्रबंधन उन्हें नौकरी से निकालने की धमकी देता है। उनका कहना है कि मामूली बढ़ोतरी कर उन्हें शांत कराने की कोशिश की जाती है। इस मामले में जब फैक्ट्री के एचआर हेड श्यामेंद्र दधीचि से संपर्क किया गया, तो उन्होंने तत्काल कोई प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया। हालांकि, बढ़ते विरोध को देखते हुए प्रबंधन ने मजदूरों से उनकी मांगों का लिखित आवेदन मांगा है। फिलहाल स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है और मजदूर अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं।

मनेर में 7 साल की बच्ची से दुष्कर्म मां छोड़ कर बाजार गई थी

एजेंसी, पटना

पटना जिले के मनेर थाना क्षेत्र के एक गांव में सात वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोप है कि 13 वर्षीय चचेरे भाई ने मंगलवार को इस घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी नाबालिग को निरुद्ध कर लिया है। पुलिस के अनुसार, घटना के समय बच्ची की मां उसे घर में अकेला छोड़कर बाजार गई हुई थी। इसी दौरान पड़ोस में रहने वाला उसका चचेरा भाई घर में घुस आया और बच्ची के साथ दुष्कर्म किया।

दुष्कर्म कर नानी के घर भागा लड़का: दुष्कर्म के बाद बच्ची अचेत हो गई, जिससे डरकर आरोपी नाबालिग अपने नानी के घर भाग गया। बच्ची के परिजनों ने इसकी शिकायत पुलिस में दर्ज कराई।

पीड़ित लड़की की मां ने बताया मेरी बच्ची के साथ गलत हुआ है। बच्ची का चचेरा भाई जो घर के पास ही रहता है उसने मेरी सात साल की बेटी के साथ दुष्कर्म किया है। घटना तब हुई जब मैं मनेर बाजार गई थी और बच्ची घर में अकेली थी।

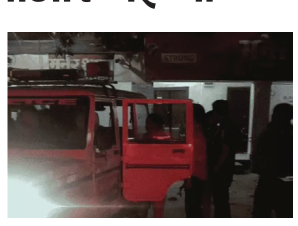

आरोपी को हिरासत में लिया गया: परिजनों की शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी को 8 किलोमीटर दूर उसके नानी के घर से हिरासत में ले लिया। थाना प्रभारी रजनीश कुमार ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए फोरेंसिक साइंस लैब (FSL) की टीम भी मनेर पहुंची और घटनास्थल की छानबीन की। एफएसएल की टीम ने लड़की के अंतः वस्त्रों को जांच के लिए लिया है। पुलिस ने दुष्कर्म की पुष्टि की है और बताया कि विधि विरुद्ध बालक को निरुद्ध कर आगे की जांच की जा रही है।

मुंगेर शिक्षिका के ड्रेस विवाद में डीईओ ने रखा पक्ष

एजेंसी, पटना

मुंगेर में एक शिक्षिका के ड्रेस मामले में DEO पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगा था। इस मामले में बिहार राज्य महिला आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया था। इस पर अपना पक्ष रखने के लिए आज जिला शिक्षा पदाधिकारी महिला आयोग पहुंचे थे। उन्होंने आयोग की अध्यक्ष के सामने इन आरोपों को पूरी तरह बेबुनियाद बताया। डीईओ ने कहा कि जिले में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए लगातार निरीक्षण और कार्रवाई की जा रही है। लेकिन कुछ लोग मनगढ़ंत आरोप लगाकर उन्हें अनावश्यक रूप से परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं।

शिक्षक संघ पर भ्रामक खबर फैलाने का आरोप: बिहार राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष प्रो अप्सरा ने कहा कि, 'जिला शिक्षा पदाधिकारी कुणाल गौरव खुद महिला आयोग आए थे। उन्होंने इस मामले में अपना पक्ष रखा है। DEO का कहना है कि कि शिक्षक संघ द्वारा यह भ्रामक समाचार फैलाई गई है। जिसने यह भ्रामक समाचार फैलाई है, वह बर्खास्त किए गए पूर्व शिक्षक हैं। वह अपने पोस्ट का गलत उपयोग कर आजकल पैसे उगाही में रहते हैं। उन्होंने शिक्षिका को अपने झांसे में लिया और यह गलत समाचार फैलाई।

जिला शिक्षा पदाधिकारी ने 11 मार्च को पत्र जारी कर हवेली खड़गपुर प्रखंड के एक विद्यालय में कार्यरत वरीय शिक्षिका से स्पष्टीकरण मांगा था। पत्र में बताया गया था कि ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर उपस्थिति समीक्षा के दौरान सेल्फी अटेंडेंस में जो ड्रेस है, वह अमर्यादित है। यह शिक्षिका की आचरण के हिसाब से ठीक नहीं है। इस मामले में वह अपना जवाब दें। ड्रेस पर मांगे गए इसी स्पष्टीकरण पर प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक संघ के मुख्य संरक्षक अमित विक्रम ने आपत्ति जताई थी।

❐ पटना महिला आयोग में बोले- शिक्षक संघ ने भ्रमाक समाचार फैलाई, सभी आरोप बेबुनियाद

शिक्षिका ने दिया था शोकॉज का जवाब: वहीं, शोकॉज का जवाब देते हुए शिक्षिका ने कहा था कि उस समय ठंड का मौसम था। उन्होंने गर्म कपड़े पहने हुए थे। दुपट्टा सूट के साइड में था। उपस्थिति दर्ज करते समय दुपट्टा की तस्वीर स्पष्ट रूप से नहीं आयी होगी। उन्होंने खेद जताते हुए कहा कि वह भविष्य में सावधानी बरतेगी।

संक्षिप्त समाचार

किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ कांग्रेस का बड़ा आंदोलन

लोकतंत्र कि शान हसन रसीद जबलपुर कटनी मध्य प्रदेश, एड.अमित शुक्ला जिला कांग्रेस कमेटी शहर अध्यक्ष के जानकारी अनुसार प्रदेश की भाजपा सरकार की किसान विरोधी नीतियों के कारण आज किसान गंभीर समस्याओं का सामना कर रहे हैं। गेहूं उपार्जन की तिथियों में लगातार बदलाव, कर्ज वसूली का दबाव एवं उपज को कम दामों में बेचने की मजबूरी ने किसानों की स्थिति अत्यंत चिंताजनक बना दी है। इन्हीं परिस्थितियों के विरोध में दिनांक - 9 अप्रैल 2026टाइम -12 बजे सभी कार्यकर्ता जिला कांग्रेस कार्यालय आस्था प्लाजा में एकत्रित हो*जिला मुख्यालय कलेक्ट्रेट में किसानों के समर्थन में धरना-प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष माननीय जीतू पटवारी जी के निर्देशानुसार यह आंदोलन आयोजित किया जा रहा है। किसान हित में –

सिरसा: बुजुर्ग की हत्या के आरोप में मास्टरमाइंड समेत चार आरोपी गिरफ्तार

लोकतंत्र की शान : सिरसा। स्थानीय पुलिस ने सिरसा जिले के गांव कुरंगावाली में बुजुर्ग व्यक्ति की हत्या मामले का पर्दाफाश करते हुए मास्टर माइंड सहित चार लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें दो नाबालिग शामिल हैं। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने उधार दिए पैसे मांगने पर इस वारदात को अंजाम दिया। रोड़ी थाना प्रभारी अनिल कुमार ने बुधवार को बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में जगपाल, जगजीत सिंह सहित दो नाबालिग शामिल हैं। मृतक लीला गिर के बेटे हरदीप सिंह की शिकायत पर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया था। हरदीप सिंह ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह प्राइवेट बस चालक है। गांव के ही शंभू ने उससे एक हजार रुपये उधार मांगे थे, लेकिन पैसे न होने के कारण वह उसे राशि नहीं दे सका। इसी बात को लेकर शंभू उसके प्रति रंजिश रखने लगा। बीती चार मार्च की रात को शंभू अपने चार-पांच साथियों के साथ दीवार फांदकर उसके घर में घुस गया। उस समय उसका पिता घर के आंगन में सो रहा था। आरोपियों ने तेजधार हथियारों से उस पर हमला कर उसकी हत्या कर दी। शोर सुनकर जब परिवार के अन्य सदस्य बाहर आए तो हमलावरों ने उसके भाई गुरदीप को भी पकड़ लिया और उसे गली में घसीटकर ले गए। उस पर धारदार हथियारों से हमला किया गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। बाद में उसे इलाज के लिए बठिंडा रेफर किया गया। सिरसा के पुलिस अधीक्षक ने घटना पर तुरंत संज्ञान लेते हुए विशेष टीमों का गठन किया और मामले को जल्द सुलझाने के निर्देश दिए। रोड़ी थाना पुलिस ने नामजद आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस ने इस मामले में संलिप्त चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें दो नाबालिग भी शामिल हैं। दोनों आरोपियों को अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। वहीं नाबालिग आरोपियों को पुलिस अभिरक्षा में ऑब्जरवेशन हाल अंबाला व करनाल भेजा गया है।

बैंक खातों, एफडी व ब्याज राशि की जांच करेंगे सभी विभाग

लोकतंत्र की शान : चंडीगढ़। हरियाणा में आए दिन सामने आ रहे बैंक घोटालों पर सरकार सतर्क हो गई है। राज्य सरकार के वित्त विभाग ने राज्य के सभी विभागों, बोर्डों, निगमों और विश्वविद्यालयों को बैंक खातों और फिक्स्ड डिपॉजिट (एफडी) पर मिलने वाले ब्याज की तत्काल जांच और मिलान करने के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव की ओर से जारी पत्र के बाद अब विभाग ने रिमाइंडर-1 जारी कर इसे अत्यंत जरूरी और समयबद्ध कार्य बताया है। वित्त विभाग के पत्र के अनुसार, सरकार ने पहले 17 मार्च 2026 को जारी निर्देशों में सभी विभागों को अपने बैंक खातों और एफडी की समीक्षा कर यह सुनिश्चित करने को कहा था कि बैंकों द्वारा ब्याज तय दरों के अनुसार ही जमा किया गया है और परिपक्वता राशि भी सही है, लेकिन अधिकांश विभागों ने इस पर गंभीरता नहीं दिखाते हुए रिपोर्ट नहीं भेजी। वित्त विभाग ने निर्देश जारी किए हैं कि सभी विभाग अपने बैंक खातों और एफडी की तुरंत जांच करें। बैंक द्वारा दी गई ब्याज दर और वास्तविक जमा ब्याज का मिलान करें। यदि ब्याज कम जमा हुआ है, तो संबंधित बैंक से तुरंत अंतर राशि दिलवाए। प्रत्येक एफडी पर लागू ब्याज दर और जमा ब्याज की पुष्टि का प्रमाण पत्र बैंक से प्राप्त करें। वित्त विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह पूरा कार्य संबंधित कार्यालयों को 15 अप्रैल 2026 तक हर हाल में रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए गए हैं।

अंबेडकर जयंती पर भाजपा ने तैयार की कार्यक्रमों की शृंखला

लोकतंत्र की शान : चंडीगढ़। हरियाणा में भाजपा ने संविधान निर्माता बाबा साहब डॉ. भीमराव आंबेडकर की 135वीं जयंती समानता व सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। इस अवसर पर कई कार्यक्रमों की शृंखला तैयार की गई है। हरियाणा के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण कुमार बेदी के अनुसार, भाजपा 13 से 20 अप्रैल तक पूरे राज्य में बाबा साहब की जयंती पर करीब एक दर्जन बड़े कार्यक्रमों का आयोजन करेगी। इन कार्यक्रमों के आयोजन के लिए भाजपा ने कैबिनेट मंत्री कृष्ण कुमार बेदी के नेतृत्व में पांच सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 14 अप्रैल को पंचकूला में राज्य स्तरीय रैली को संबोधित करेंगे। इस दिन दलित कल्याण की कई योजनाओं की घोषणा संभव है।डॉ. भीमराव आंबेडकर की जयंती की पूर्व संध्या पर यानी 13 अप्रैल की रात को पूरे राज्य में उन सभी स्थानों पर स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा, जहां-जहां बाबा साहब डॉ. भीमराव आंबेडकर की प्रतिमाएं लगी हैं। इसी दिन रात को दीपोत्सव होंगे। 14 अप्रैल को सुबह प्रतिमाओं पर माल्यार्पण किए जाएंगे, जिसके बाद मिष्ठान वितरण होगा। मुख्यमंत्री नायब सैनी 14 अप्रैल को पंचकूला स्थित इंद्रधनुष स्टेडियम में राज्य स्तरीय रैली को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता कृष्ण बेदी करेंगे, जबकि विशिष्ट अतिथि पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार होंगे। सभी विधायकों को कार्यक्रम में रहने के लिए कहा गया है। राज्य स्तरीय आयोजन कमेटी में कृष्ण कुमार बेदी के अलावा एसपी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सत्यप्रकाश जरावता, पूर्व मंत्री अनूप धानक, एससी मोर्चा के प्रदेश महामंत्री मक्खन सिंह और राजकुमार कटारिया को शामिल किया गया है।भाजपा ने 15 व 16 अप्रैल को राज्य के सभी एससी छात्रावास और संस्थाओं में जाकर संविधान पर लोकसभा में दिए गए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के भाषण का प्रचार-प्रसार करने की रूपरेखा तैयार की गई है। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि 20 अप्रैल को सभी जिला मुख्यालयों पर बुद्धिजीवी लोगों के सम्मेलन आयोजित होंगे। जिन दलित बस्तियों में 100 से ज्यादा लोग रहते हैं, वहां भाजपा के लोग पहुंचेंगे तथा बाबा साहब के कार्यों की जानकारी देंगे। कृष्ण कुमार बेदी ने पार्टी कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है कि वे अपने-अपने क्षेत्र में बाबा साहब की जयंती पर होने वाले कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर भागीदारी करें।

राज्यपाल ने एमडीएस विश्वविद्यालय की नई वेबसाइट का किया लोकार्पण

लोकतंत्र की शान : जयपुर। राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने बुधवार को लोकभवन में महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर की भारतीय ज्ञान परम्परा के आलोक में तैयार विद्यार्थी केंद्रित नई वेबसाइट का बटन दबाकर लोकार्पण किया। उन्होंने नई तैयार वेबसाइट में विद्यार्थियों और अन्य संबंधित जनों के लिए शैक्षिक जानकारियों और विश्वविद्यालय से जुड़ी प्रवेश, पाठ्यक्रम आदि प्रक्रियाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराने की पहल की सराहना की।उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय में शिक्षण में नवाचार इस तरह से हों कि भारत के अन्य स्थानों और विदेश स्थित विद्यार्थी भी हमारे यहां पढ़ने लिए प्रोत्साहित हों। विश्वविद्यालय के कुलगुरु सुरेश अग्रवाल ने बताया कि महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय जीरो कार्बन कैम्पस हो गया है। यहां भारतीय ज्ञान परम्परा और वैदिक वांग्मय से जुड़े अध्ययन को आधुनिक परिप्रेक्ष्य में विकसित किए जाने की पहल की गई है।

लापरवाह प्रधानाध्यापक के खिलाफ की बड़ी कार्यवाही

» खबर प्रशासन के बाद खुली डीपीसी की नींद
» मामला मझौली ब्लॉक के पूर्व माध्यमिक विद्यालय पोंडी का

लोकतंत्र की शान (ऋचा पाण्डेय ब्यूरो प्रमुख)

सीधी। जिले के जनपद शिक्षा केंद्र मझौली अंतर्गत जन शिक्षा केंद्र कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मझौली के शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय पोंड़ी में प्रधानाध्यापक के लापरवाही को लेकर 8 अप्रैल बुधवार को खबर प्रकाशित की गई थी जिसे गंभीरता से लेते हुए डीपीसी विनय मिश्रा ने जांच कार्यवाही करते हुए लापरवाह प्रधानाध्यापक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। बताते चलें कि स्थानीय अविभावक एवं शाला प्रबंधन समिति के अध्यक्ष राम सजीवन यादव द्वारा आरोप लगाया गया था कि विद्यालय में पदस्थ प्रधानाध्यापक शिवप्रकाश बैगा विद्यालय से नदारत रहते हैं व जब कभी रहते भी हैं तो नशे की हालत मे। कोई भी शौंचालय उपयोग में नहीं हैं बच्चे जंगली नाले में शौंच के लिए जाते हैं जहां कोई भी अप्रिय घटना घटित हो सकती है।शैक्षणिक स्तर काफी कमजोर है।बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं मिली है। जैसे ही खबर का प्रकाशन हुआ तो उसे गंभीरता से लेते हुए उसी दिन डीपीसी विनय मिश्रा संबंधित विद्यालय जांच करने पहुंच गए जहां प्रकाशित खबर को अक्षरशः सत्य पाया तब उन्होंने प्रधानाध्यापक शिवप्रकाश बैगा को तत्काल प्रभार से पृथक कर शाला में पदस्थ अन्य शिक्षक को प्रधानाध्यापक का प्रभार दिए जाने का आदेश जारी करते हुए सभी भुगतान पत्रक,बिल वाउचर सहित सभी बिंदुओं की जांच कर तीन दिन के अंदर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए जन शिक्षक संतोष कुमार कचेर एवं बीआरसीसी अयोध्या प्रसाद पटेल को निर्देशित किया गया। साथ ही नाराजगी जाहिर करते हुए कहा गया कि इतनी लापरवाही होने के बाद भी आप लोगों के द्वारा ठोस कार्रवाई के लिए प्रतिवेदन क्यों नहीं दिया गया।

मिशन शक्ति 5.0 के तहत संभल में महिलाओं को किया गया जागरूक, चौपाल लगाकर दी सुरक्षा व साइबर जानकारी

लोकतंत्र की शान, सैय्यद कुमैल ज़ैदी

संभल। थाना नखासा क्षेत्र में पुलिस अधीक्षक संभल कृष्ण कुमार के निर्देशन में जनपद में चलाए जा रहे मिशन शक्ति अभियान 5.0 के तहत थाना नखासा पुलिस टीम द्वारा महिला सुरक्षा एवं सशक्तिकरण को लेकर व्यापक जागरूकता अभियान चलाया मिशन शक्ति प्रभारी महिला उप निरीक्षक राखी सिंह की टीम ने थाना क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर महिलाओं और बालिकाओं को जागरूक करते हुए नारी सुरक्षा, आत्मनिर्भरता तथा साइबर जागरूकता के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी दी। इस दौरान महिलाओं को उनके अधिकारों, सुरक्षा उपायों और डिजिटल ठगी से बचाव के तरीकों के बारे में विस्तार से बताया गया। अभियान के दूसरे चरण में मोहल्ला रुकंदी सराय व नखासा चौराहा एवं आसपास के बाजार क्षेत्रों में विशेष चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। चौपाल के माध्यम से सरकारी योजनाओं की जानकारी देने के साथ-साथ हेल्पलाइन नंबर 1076, 112, 1090, 1930 तथा

मिशन शक्ति सीयूजी नंबर के बारे में भी अवगत कराया गया। पुलिस टीम ने महिलाओं को किसी भी आपात स्थिति में तुरंत हेल्पलाइन का उपयोग करने और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। यह अभियान महिलाओं में सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन की भावना को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल साबित हो रहा है। मिशन शक्ति टीम थाना नखासा जनपद संभल

उत्कर्ष बने असिस्टेंट प्रोफेसर हासिल किये 129 वीं रैंक

लोकतंत्र की शान (ऋचा पाण्डेय ब्यूरो प्रमुख)

सीधी। जिले के प्रतिभाशाली छात्र उत्कर्ष त्रिपाठी पुत्र मनोज कुमार त्रिपाठी ने यू जी सी नीट की प्रतिष्ठित परीक्षा में 99.77 प्रतिशत अंक प्राप्त करते हुए ऑल इंडिया रैंक (AIR) मे 129 रैंक हासिल कर जे आर एफ (Junior Research Fellowship) प्राप्त किये हैं । यह उपलब्धि उनकी असाधारण प्रतिभा, कठोर परिश्रम एवं अटूट संकल्प का प्रतीक है। उत्कर्ष ने अपनी स्नातक एवं स्नातकोत्तर की शिक्षा दिल्ली विश्वविद्यालय से पूर्ण किये हैं , जहाँ उन्होंने निरंतर उत्कृष्ट शैक्षणिक प्रदर्शन किया। उनकी इस उल्लेखनीय सफलता से न केवल उनके परिवार, बल्कि पूरे सीधी जिले में गर्व एवं हर्ष का वातावरण है। राजेन्द्र शुक्ला गोतरा , योगेंद्र गौतम, अजीत सिंह बघेल, अतुल त्रिपाठी, राहुल त्रिपाठी, अनूप तिवारी, संदीप द्विवेदी शिक्षकों एवं उनके शुभचिंतकों ने उन्हें बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य एवं शोध एवं शिक्षण क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान की कामना किये है।जिले भर मे हर्ष का माहौल है।

ऑपरेशन मुस्कान के तहत दो नाबालिग सकुशल बरामद, एक आरोपी गिरफ्तार

लोकतंत्र की शान (ऋचा पाण्डेय ब्यूरो प्रमुख)

सीधी। पुलिस मुख्यालय भोपाल द्वारा प्रदेश स्तर पर चलाए जा रहे मुस्कान अभियान के तहत सीधी पुलिस निरंतर प्रभावी कार्यवाही कर रही है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक सीधी संतोष कोरी के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अरविन्द श्रीवास्तव एवं एसडीओपी चुरहट रवि प्रकाश कौल के सतत मार्गदर्शन में थाना कमर्जी पुलिस को दो अलग-अलग मामलों में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार विगत दिवस थाना कमर्जी अंतर्गत एक 17 वर्षीय बालक के गुम होने की सूचना प्राप्त हुई थी। फरियादी बालक के पिता की रिपोर्ट पर तत्काल प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी उनि इन्द्राज सिंह ने तत्काल एक विशेष टीम गठित की। साइबर सेल की मदद और मुखबिर तंत्र के जरिए बालक की लोकेशन ट्रेस की गई। पुलिस के निरंतर दबाव और सर्चिंग के चलते बालक को ग्राम रायखोर थाना रामपुर नैकिन से महज 21 घंटे के भीतर सकुशल ढूंढ निकाला गया। काउंसलिंग के दौरान पता चला कि बालक अपने पिता की डांट से भयभीत होकर बिना बताए घर से निकल गया था। बालक को समझा-बुझाकर सुरक्षित परिजनों के सुपुर्द किया गया।

अपहत बालिका को पुलिस ने किया दस्तयाब, पुलिस ने किया गिरफ्तार

थाना क्षेत्र से करीब एक सप्ताह पूर्व एक नाबालिग बालिका के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। मामले में पुलिस ने धारा 137(2) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर गहन तलाश शुरू की थी। विवेचना के दौरान यह तथ्य सामने आया कि एक आरोपी द्वारा नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाया गया था। पुलिस टीम ने त्वरित घेराबंदी करते हुए बालिका को सकुशल दस्तयाब किया। मामले में संलिप्त आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके विरुद्ध अग्रिम वैधानिक कार्यवाही प्रचलित है। बालिका की उचित काउंसलिंग कराई जाकर उसके परिजनों को सौंप दिया गया। इन दोनों महत्वपूर्ण कार्यवाहियों में थाना प्रभारी उनि इन्द्राज सिंह, एएसआई मनोज वर्मा और महिला आरक्षक सुनीता पटेल का विशेष एवं समर्पणपूर्ण योगदान रहा।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने चलाया पंच-ज अभियान

» न्यायालय परिसर में पक्षियों के लिए पानी के सकोरे रखवाए
» पक्षियों के दाना पानी का इंतजाम करना पुण्य का काम- प्रधान न्यायाधीश पी एल दिनकर

लोकतंत्र की शान (ऋचा पाण्डेय ब्यूरो प्रमुख)

सीधी। मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर की मंशानुरूप एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रयाग लाल दिनकर के मुख्य आतिथ्य में तथा समस्त न्यायाधीशगण की विशेष उपस्थिति में आज जिला न्यायालय परिसर सीधी में पक्षियों को गर्मी से बचाव के लिए पानी एवं दाना रखने के लिए सकोरे वृक्षों पर लगाए जाने संबंधी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीधी द्वारा न्यायालय परिसर में पक्षियों के लिए वृक्षों पर सकोरे लगवाकर बताया गया कि गर्मी के मौसम में पक्षियों के लिए दाना-पानी की व्यवस्था करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जल की कमी के कारण उन्हें अत्यधिक परेशानी का सामना करना पड़ता है। उन्होंने सभी नगरिकों से अपील की कि वे भी अपने घर, कार्यालय, बालकनी, छत अथवा बगीचे एवं आसपास के क्षेत्रों में पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था करें, साथ ही उनके रहने के स्थान को छायादार एवं हवादार बनाया जाना आवश्यक है। इस अवसर पर विशेष न्यायाधीश यतीन्द्र कुमार गुरू, प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय दीपक शर्मा, द्वितीय जिला न्यायाधीश मनीष कुमार श्रीवास्तव, प्रथम जिला न्यायाधीश राकेश कुमार सोनी, प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सीधी के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश सुश्री उर्मिला यादव, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मुकेश कुमार शिवहरे, प्रभारी अधिकारी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सुश्री सुनीता रावत, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सोनू जैन, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सुश्री सरिता चौधरी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कपिल देव काछी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मृदुल लटौरिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अभिषेक साहू, जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री मनीष कौशिक, चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल देवेन्द्र प्रसाद मिश्रा, डिप्टी चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल विनोद कुमार श्रीवास्तव, बाबूलाल सिंह, असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल देवेन्द्र प्रसाद द्विवेदी, सत्यप्रकाश पाण्डेय, ऋषभ सिंह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं न्यायालयीन कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

जुवे की फड़ और नशे के कारोबार से फलता फूलता गुडम्बा

लोकतंत्र की शान, अब्दुल्लाह खान ब्यूरो चीफ

राजधानी लखनऊः गुड़म्बा थाना क्षेत्र में पुलिस संरक्षण में जुए का खेल? भाखामऊ में खुलेआम चल रहा अवैध कारोबार लखनऊ। राजधानी लखनऊ के थाना गुड़म्बा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली गढ़ी पुलिस चौकी के पास भाखामऊ स्थित किरण इन्क्लेव के पीछे अवैध रूप से जुए का खेल संचालित किए जाने का मामला सामने आया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, इलाके में सलमान नामक व्यक्ति द्वारा लंबे समय से जुआ खिलवाया जा रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि यह अवैध कारोबार बिना संरक्षण के संभव नहीं है। बताया जा रहा है कि गढ़ी पुलिस चौकी के दो पुलिसकर्मियों के संरक्षण में यह जुए का अड्डा संचालित हो रहा है, जिसके चलते इलाके में कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि क्षेत्र में इस तरह के अवैध जुए के कारण युवाओं पर गलत प्रभाव पड़ रहा है और आपराधिक गतिविधियों को बढ़ावा मिल रहा है। इसके बावजूद जिम्मेदार अधिकारियों की ओर से अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर पुलिस चौकी के नजदीक चल रहे इस जुए के अड्डे की जानकारी पुलिस को नहीं है, या फिर सब कुछ मिलीभगत से चल रहा है? जनता ने पुलिस कमिश्नर लखनऊ और उच्च अधिकारियों से मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है

रामपुर में इंसानियत शर्मसार: दो बेजुबान कुत्तों पर फेंका तेजाब, लोगों में आक्रोश

लोकतंत्र की शान, मंडल प्रभारी अवनीत कुमार शर्मा

रामपुर। कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत जैन मंदिर के निकट सरस्वती स्कूल के सामने एक बेहद दर्दनाक और अमानवीय घटना सामने आई है। अज्ञात व्यक्ति द्वारा दो बेजुबान कुत्तों पर तेजाब डाल दिया गया, जिससे दोनों कुत्ते गंभीर रूप से झुलस गए। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश फैल गया। लोगों ने मौके पर पहुंचकर इस घटना को लेकर कड़ी नाराजगी जाहिर की और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन अब तक दोषियों पर ठोस कार्रवाई नहीं हो रही। घटना के बाद से क्षेत्र में तनाव का माहौल है और लोग प्रशासन से जल्द से जल्द आरोपी की पहचान कर गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि घटना की सूचना पुलिस को भी दी गई है। स्थानीय लोगों ने मांग की है कि आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच कर आरोपी की पहचान की जाए और उसके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए। फिलहाल दोनों घायल कुत्तों का उपचार कराए जाने की बात सामने आ रही है।

स्थानीय नागरिकों की मांगः आरोपी की जल्द पहचान कर गिरफ्तारी पशु क्रूरता अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी बढ़ाई जाए यह घटना समाज में बढ़ती संवेदनहीनता को दर्शाती है, जिस पर प्रशासन को गंभीरता से कदम उठाने की जरूरत है।

मिशन शक्ति 5.0 के तहत हजरत नगर गढ़ी में महिलाओं को किया गया जागरूक, चौपाल के माध्यम से दी सुरक्षा व साइबर जानकारी

लोकतंत्र की शान, सैय्यद कुमैल ज़ैदी

संभल। थाना हजरत नगर गढ़ी क्षेत्र में पुलिस अधीक्षक संभल के निर्देशन में जनपद में संचालित मिशन शक्ति अभियान 5.0 के अंतर्गत महिला सुरक्षा एवं सशक्तिकरण को लेकर व्यापक जागरूकता अभियान चलाया गया। थाना प्रभारी सुधीर पवार एवं मिशन शक्ति प्रभारी उपनिरीक्षक रश्मि मलिक के नेतृत्व में पुलिस टीम ने क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर महिलाओं और बालिकाओं को जागरूक करते हुए नारी सुरक्षा, आत्मनिर्भरता तथा साइबर सुरक्षा के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की। इस दौरान महिलाओं को उनके अधिकारों, सुरक्षा उपायों तथा ऑनलाइन ठगी से बचने के प्रभावी तरीकों के बारे में विस्तार से बताया गया। पुलिस टीम ने विशेष रूप से डिजिटल युग में बढ़ते साइबर अपराधों से सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना देने पर जोर दिया। अभियान के तहत मोहल्ला क्षेत्रों एवं बाजारों में विशेष चौपाल कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। चौपाल के माध्यम से विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी देने के साथ-साथ हेल्पलाइन नंबर 1076, 112, 1090 और 1930 के बारे में भी विस्तार से अवगत कराया गया। पुलिस टीम ने महिलाओं को किसी भी आपात स्थिति में बिना झिझक हेल्पलाइन सेवाओं का उपयोग करने तथा आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। यह अभियान महिलाओं में सुरक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भरता की भावना को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल साबित हो रहा है।

संक्षिप्त समाचार

नेपाल में विभिन्न देशों के राजदूतों से मिले प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह, किया सामूहिक संवाद

काठमांडू। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ने आज काठमांडू स्थित विभिन्न देशों के राजदूतों और कूटनीतिक मिशनों के प्रमुखों के साथ सामूहिक बैठक और संवाद किया। प्रधानमंत्री शाह ने सुशासन, आर्थिक विकास और नेपाली नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार के प्रति सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता जताई। प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद् कार्यालय, सिंहदरबार में हुई इस बैठक में भारत, पाकिस्तान, कोरिया गणराज्य, ब्रिटेन, कतर, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, इजराइल, जापान, बांग्लादेश, जर्मनी, मिस्र, श्रीलंका, सऊदी अरब, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र के राजदूत एवं मिशन प्रमुख उपस्थित रहे। राजदूतों और मिशन प्रमुखों ने प्रधानमंत्री शाह को बधाई देते हुए उनके सफल कार्यकाल की कामना की। उन्होंने नेपाली जनता के हित में परिणाम देने वाले सरकारी कार्यों में सहयोग और समर्थन का भी आश्वासन दिया। प्रधानमंत्री शाह ने नेपाल की संतुलित और व्यावहारिक विदेश नीति को दोहराते हुए पड़ोसी, मित्र देशों और विकास साझेदारों के साथ विश्वास, पारस्परिक सम्मान और साझा समृद्धि पर आधारित संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि शांति सभी की साझा प्राथमिकता होनी चाहिए और विदेशों में कार्यरत नेपाली श्रमिकों तथा प्रवासी नेपाली समुदाय की सुरक्षा और हित सरकार की उच्च प्राथमिकता में हैं। इस अवसर पर विदेश मंत्री शिशिर खनाल, प्रधानमंत्री के राजनीतिक सलाहकार असीम शाह, मुख्य सचिव सुमनराज अर्याल, विदेश सचिव अमृत राई तथा अन्य सरकारी अधिकारी भी उपस्थित रहे।

उत्तराखंड- चारों धाम में बर्फबारी, राजस्थान में भी ओले गिरे

भोपाल/लखनऊ/शिमला/देहरादून। देश में एक साथ दो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय होने से मौसम बदल गया है। उत्तराखंड के चारों धाम-केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री में बर्फबारी हो रही है। राज्य के सभी जिलों में बारिश हो रही है। राजस्थान के श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, नागौर समेत कई जिलों में तूफानी बारिश के साथ ओले भी गिरे। कई जिलों में एक इंच से ज्यादा पानी बरसा।

वहीं, भरतपुर जिले में मकान पर बिजली गिरने से सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया। बारिश की वजह से तापमान में 7 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। यूपी के मेरठ, बरेली और शाहजहांपुर में दोपहर में ओले गिरे। लखनऊ, गोरखपुर, गोंडा, जौनपुर, अलीगढ़ समेत 25 जिलों में आज तेज हवाओं के साथ रुक-रुककर बारिश हो रही है। इस दौरान 60 किमी की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं।पिछले हफ्ते आंधी-बिजली से 15 लोगों की मौत हो चुकी है। मध्य प्रदेश में 3 साइक्लोनिक एक्टिविटी हैं। मौसम विभाग ने भोपाल, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, पन्ना, सतना, रीवा समेत 18 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। दतिया, निवाड़ी, छतरपुर और टीकमगढ़ में ओले गिर सकते हैं। जम्मू-कश्मीर के रामबन में लैंडस्लाइड से जम्मू-श्रीनगर हाईवे बंद हो गया है।

11 साल बाद जेल से बाहर आएगा रामपाल

चंडीगढ़। सतलोक आश्रम के प्रमुख रामपाल को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हत्या व अन्य धाराओं में दर्ज केस में उम्रकैद की सजा काट रहे रामपाल को जमानत मिल गई है। रामपाल 11 साल, 4 महीने और 20 दिन से जेल हिसार सेंट्रल जेल-2 में बंद है। हिसार सेंट्रल जेल-2 के सुपरिंटेंडेंट उमेश कुमार ने दैनिक भास्कर को बताया कि हाईकोर्ट के जमानत ऑर्डर संबंधित कोर्ट में जाएंगे। उसके बाद वहां बॉन्ड भरा जाएगा। इसके बाद ऑर्डर आएंगे। फिर रामपाल को जेल से रिलीज किया जाएगा। रामपाल को 19 नवंबर 2014 को हिसार जिले के बरवाला स्थित सतलोक आश्रम से गिरफ्तार किया गया था। हाईकोर्ट ने उसे कोर्ट की अवमानना के एक मामले में पेश होने का आदेश दिया था, लेकिन वह पेश नहीं हुआ। जब पुलिस उसे गिरफ्तार करने पहुंची, तो समर्थकों से झड़प हो गई। इस टकराव में 5 महिलाओं और डेढ़ साल के बच्चे की मौत हुई थी। इसी मामले में रामपाल पर देशद्रोह का केस दर्ज किया गया था। रोहतक के करौंथा और हिसार के सतलोक आश्रमों में पहले हुए विवादों को देखते हुए, रामपाल कुरुक्षेत्र में पिपली के पास बने सतलोक आश्रम में जा सकता है। अगले महीने, 1 से 3 मई तक, इसी आश्रम में विश्व शांति के लिए पाठ का आयोजन किया गया है, जिसमें देशभर से रामपाल के समर्थक जुड़ेंगे। यह भी अनुमान लगाया जा रहा है कि इस आश्रम को हेडक्वार्टर बनाया जा सकता है। पिपली आश्रम के मुख्य सेवादार पुरुषोत्तम दास ने कहा- यह उनका आश्रम है, वह यहां जरूर आएंगे। वह पहले कहां जाएंगे, इसकी जानकारी नहीं है। सेवादारों में बहुत खुशी है कि गुरुजी आ रहे हैं।

5 घंटे तालाब में छिपा रहा 400 चोरियों का मास्टरमाइंड

जबलपुर। जबलपुर में पुलिस और एक शातिर अंतरराज्यीय चोर के बीच मंगलवार शाम फिल्मी ड्रामा देखने को मिला। पुलिस को चकमा देने के लिए आरोपी खितौला रेलवे स्टेशन के पास एक काई से भरे तालाब में कूद गया। वह करीब 5 घंटे तक पानी के अंदर छिपा रहा। चौंकाने वाली बात यह है कि वह सांस लेने के लिए कमल की डंठल (कमल-नाल) का सहारा लेता रहा। आखिरकार गोताखोरों की मदद से उसे दबोच लिया गया। घटना रीवा-इतवारी एक्सप्रेस ट्रेन की है। एसी कोच में एक महिला का पर्स चोरी करने की कोशिश के दौरान आरोपी आरपीएफ (RPF) की नजर में आ गया। जैसे ही ट्रेन सिहोरा रोड रेलवे स्टेशन के पास धीमी हुई, आरोपी कूदकर भागने लगा। आरपीएफ जवानों ने पीछा किया तो वह खितौला के एक गहरे और काई से भरे तालाब में जा कूदा। रात के अंधेरे और घनी शैवाल के कारण वह पुलिस की आंखों से ओझल हो गया। खितौला थाना पुलिस और गोताखोरों की टीम ने जब रेस्क्यू शुरू किया तो पाया कि आरोपी पानी की सतह पर नहीं है। शातिर चोर ने खुद को पूरी तरह पानी में डुबो लिया था। केवल एक पाइपनुमा कमल-नाल के जरिए बाहर से ऑक्सीजन ले रहा था। करीब 5 घंटे की मशक्कत के बाद गोताखोरों ने उसे काई के बीच से ढूंढ निकाला।

सारधा चिटफंड प्रमुख सुदीप्त सेन 13 वर्ष बाद निकलेंगे जेल से बाहर, सभी मामलों में मिली जमानत

कोलकाता। पश्चिम बंगाल के बहुचर्चित सारधा चिटफंड घोटाले के मुख्य आरोपित सुदीप्त सेन को सभी लंबित मामलों में जमानत मिल गई है और लगभग 12 वर्ष और 11 माह जेल में रहने के बाद उनकी रिहाई का रास्ता साफ हो गया है। फिलहाल वह कोलकाता के प्रेसिडेंसी जेल में बंद हैं और संभावना है कि वह गुरुवार को रिहा हो सकते हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति राजर्षि भारद्वाज की खंडपीठ ने बुधवार को राज्य पुलिस के अधीन दो मामलों में उन्हें जमानत दे दी। इसके साथ ही उनके जेल से बाहर आने में कोई कानूनी बाधा नहीं रह गई है। हालांकि, अदालत ने जमानत के साथ कुछ शर्तें भी लगाई हैं। बताया गया है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के पास कुल 76 मामले थे, जिनमें सुदीप्त सेन को पहले ही जमानत मिल चुकी थी। इसके अलावा बारासात थाने के दो मामलों में वह अब तक जेल में थे और इन्हीं मामलों में जमानत मिलने के बाद उनकी रिहाई संभव हो पाई है। मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत को बताया कि सारधा समूह के खिलाफ कुल 389 मामले दर्ज हुए थे। सुदीप्त सेन को 27 अप्रैल, 2013 को विधाननगर थाने में दर्ज एक मामले में गिरफ्तार किया गया था। बाद में केंद्रीय एजेंसी ने 76 मामलों की जांच अपने हाथ में ली और कई मामलों में आरोपपत्र दाखिल किया गया। शेष मामलों में राज्य पुलिस ने कार्रवाई की। बताया गया कि केंद्रीय एजेंसियों के मामलों में जमानत मिलने के बावजूद राज्य पुलिस के अधीन 308 मामलों में से दो मामलों के कारण उनकी रिहाई अटकी हुई थी। बुधवार को उच्च न्यायालय में सुनवाई के बाद उन मामलों में भी जमानत दे दी गई। इस बीच तृणमूल कांग्रेस के नेता और बेलियाघाटा सीट से उम्मीदवार कुणाल घोष ने कहा कि किसी को जमानत मिलना या नहीं मिलना पूरी तरह अदालत का विषय है और यह कानून की प्रक्रिया का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि सुदीप्त सेन ने जमानत की अर्जी दी थी और अदालत ने उसे मंजूर किया है, इसलिए इस पर अलग से टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है।

देश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की सप्लाई स्थिर : सरकार

एजेंसी, नई दिल्ली

अबतक 5 किलो के 8,90,000 सिलेंडर की हुई बिक्री

पश्चिम एशिया में सीजफायर की घोषणा का स्वागत करते हुए केंद्र सरकार ने बुधवार को कहा कि इससे क्षेत्र में स्थायी शांति आएगी। सरकार ने कहा कि देश में पेट्रोल और डीजल की सप्लाई स्थिर है। तेल रिफाइनरियां पर्याप्त कच्चे तेल के साथ पूरी क्षमता से चल रही हैं, जबकि 23 मार्च से अब तक 5 किलो के लगभग 8,90,000 सिलेंडर बेचे जा चुके हैं। कोयला आधारित बिजली देश की ऊर्जा जरूरतों का लगभग 70 फीसदी हिस्सा पूरा करना जारी रखे हुए है। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव (मार्केटिंग और ऑयल रिफाइनरी) सुजाता शर्मा ने अंतर-मंत्रालयी प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए यह जानकारी दी। सुजाता शर्मा ने कहा कि पिछले पांच दिनों में ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने करीब 1,600 जागरूकता कैंप लगाए हैं, जिनमें लगभग 14,000 सिलेंडर बांटे गए हैं। उन्होंने कहा कि कल लगभग 1.1 लाख गैस सिलेंडर की सप्लाई की गई, जिससे 23 मार्च से अब तक पांच किलो वाले गैस सिलेंडर की कुल बिक्री लगभग 8.9 लाख हो गई है। उन्होंने बताया कि घरेलू जरूरतों को प्राथमिकता दी जा रही है, जिसमें खाद बनाने वाले प्लांटों को लगभग 95 फीसदी गैस की सप्लाई मिल रही है। पेट्रोल और डीजल की सप्लाई स्थिर है और कहीं भी कमी नहीं है क्योंकि रिफाइनरियां पर्याप्त कच्चे तेल के साथ पूरी क्षमता से चल रही हैं। शर्मा ने कहा कि सरकार ने सप्लाई बढ़ाने के लिए C3 और C4 स्ट्रीम को एलपीजी पूल में भेजने का निर्देश दिया है, जबकि पेट्रोकेमिकल्स के लिए सीमित इस्तेमाल की अनुमति दी है।

सुजाता शर्मा ने बताया कि नेचुरल गैस के संबंध में घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता दी गई है और उनकी आपूर्ति को सुरक्षित रखा गया है। इसके साथ ही उद्योगों को भी नेचुरल गैस की सप्लाई शुरू की गई है। ड्राफ्ट स्टेट सीबीजी पॉलिसी जारी की गई है, जो राज्य इस पॉलिसी को अपनाएंगे, उन्हें अतिरिक्त कमर्शियल एलपीजी आवंटन में प्राथमिकता दी जाएगी। भारत सरकार ने सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि वे ऐसे सुधार लागू करें, जिससे प्राथमिकता वाले कमर्शियल एलपीजी की आपूर्ति आसान हो सके। इसके तहत लगभग 18 राज्यों ने कदम उठाए हैं और उन्हें अतिरिक्त एलपीजी का आवंटन दिया गया है।

पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव ने कहा कि मार्च से अब तक लगभग 3,87,000 पीएनजी कनेक्शन दिए गए हैं और लगभग 4,21,000 नए उपभोक्ता पंजीकृत हुए हैं। जिन उपभोक्ताओं के पास एलपीजी और पीएनजी दोनों कनेक्शन हैं, उनसे एलपीजी कनेक्शन सरेंडर करने का अनुरोध किया गया है। उन्होंने कहा कि अब तक 17,000 से अधिक उपभोक्ता अपना एलपीजी कनेक्शन सरेंडर कर चुके हैं। इसके साथ ही सभी नागरिकों से अपील है कि अफवाहों पर ध्यान न दें और अपनी जरूरत के अनुसार ही ईंधन खरीदें।

इजरायल में नेपाली दूतावास ने अपने नागरिकों के लिए जारी किया हाई अलर्ट

एजेंसी, काठमांडू

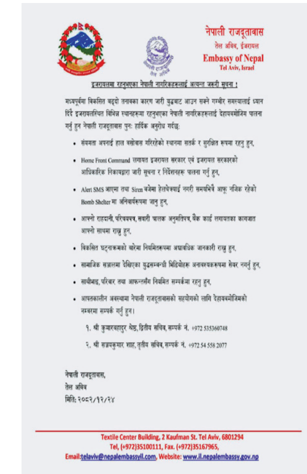

इज़राइल स्थित नेपाली दूतावास ने इज़राइल के विभिन्न क्षेत्रों में रह रहे नेपाली नागरिकों के लिए एक हाई अलर्ट संदेश जारी करते हुए उनसे संयमित, सतर्क और सुरक्षित तरीके से रहने की अपील की है। नेपाली दूतावास ने बुधवार आठ बिंदुओं वाला एक 'अत्यावश्यक' परामर्श जारी कर यह आग्रह किया है। आपातकालीन स्थिति में सहायता के लिए दूतावास ने द्वितीय सचिव कुमार बहादुर श्रेष्ठ और तृतीय सचिव संज कुमार शाह से मोबाइल फोन के माध्यम से संपर्क करने को कहा है।

दूतावास के द्वारा जारी बयान के अनुसार, द्वितीय सचिव कुमार बहादुर श्रेष्ठ का संपर्क नंबर +972-535360748 और तृतीय सचिव संज कुमार शाह का संपर्क नंबर +972-545582077 है। दूतावास ने होम फ्रंट कमांड सहित इज़राइल सरकार और उसके आधिकारिक निकायों द्वारा जारी निर्देशों और सूचनाओं का पालन करने का भी अनुरोध किया है।

साथ ही, अलर्ट एसएमएस प्राप्त होने या खतरे का संकेत देने वाले सायरन बजने पर लापरवाही न करते हुए तुरंत अपने निकटतम बम शेल्टर में जाने की सलाह दी गई है। इज़राइल में रह रहे नेपाली नागरिकों से अपने पासपोर्ट, पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक कार्ड आदि महत्वपूर्ण दस्तावेज हमेशा अपने साथ रखने और ताज़ा घटनाक्रम की नियमित जानकारी लेते रहने को भी कहा गया है।

इसके अलावा, सोशल मीडिया पर प्रसारित युद्ध संबंधी वीडियो को अनावश्यक रूप से साझा न करने तथा अपने दोस्तों, परिवार और रिश्तेदारों के साथ नियमित संपर्क में रहने की भी अपील की गई है।

नेपाल सरकार ने सार्वजनिक यातायात का किराया 17 से 22 प्रतिशत तक बढ़ाया

एजेंसी, काठमांडू

नेपाल सरकार ने सार्वजनिक परिवहन का किराया 17 से 22 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया है। इसी तरह विभाग ने माल ढुलाई के किराए में भी बढ़ोतरी की है। नई दरें बुधवार से लागू हो गई हैं।

पेट्रोलियम पदार्थ की कीमतों भारी वृद्धि के बाद सार्वजनिक यातायात में 16.71 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। तराई क्षेत्र में ढुलाई किराया 15.75 प्रतिशत और पहाड़ी क्षेत्र में 21.68 प्रतिशत बढ़ाया गया है। भौतिक पूर्वाधार तथा परिवहन मंत्री सुनिल लम्साल ने मंगलवार को किराया समायोजन को स्वीकृति देने के बाद बुधवार को विभाग ने यह निर्णय लिया।

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रीय महासंघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटौला के अनुसार अंतरराष्ट्रीय बाजार में पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में हुई वृद्धि और अन्य तकनीकी कारणों से भाड़ा में बढ़ोतरी की गई है। उन्होंने कहा कि परिवहन व्यवसायी लंबे समय से किराया समायोजन की मांग कर रहे थे। नए किराया दर लागू होने के साथ ही आम जनता की दैनिक यात्रा और उपभोग्य वस्तुओं की कीमतों पर भी प्रभाव पड़ने की आशंका जताई गई है।

वैज्ञानिक किराया समायोजन कार्यविधि के अनुसार वाहन किराए में पेट्रोलियम पदार्थों का 35 प्रतिशत और बीमा, वाहन, बैंक ब्याज, स्पेयर पार्ट्स, टायर, लुब्रिकेंट सहित 13 मदों में हुई मूल्य वृद्धि का 65 प्रतिशत योगदान निर्धारित किया जाता है। इसमें यह भी उल्लेख है कि ईंधन की कीमत में 5 प्रतिशत की वृद्धि या कमी होने पर किराया दर स्वतः समायोजित हो जाएगी।

केंद्र ने जयपुर मेट्रो फेज-2 को दी मंजूरी, 41 किमी लंबा कॉरिडोर बनेगा

एजेंसी, नई दिल्ली

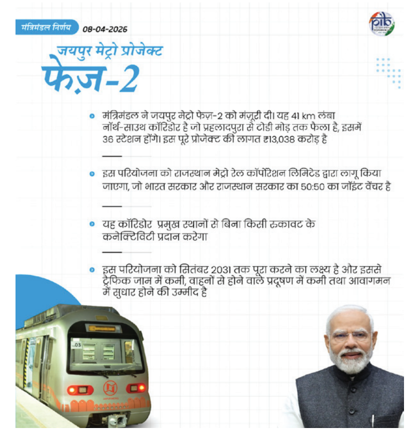

केंद्र सरकार ने जयपुर शहर की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में बड़ा फैसला लेते हुए जयपुर मेट्रो फेज-2 परियोजना को मंजूरी दे दी है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस 41 किलोमीटर लंबे नॉर्थ–साउथ कॉरिडोर को स्वीकृति प्रदान की गई। जयपुर तेजी से विकसित हो रहा शहर है और इसकी बढ़ती आबादी एवं पर्यटन को देखते हुए यह परियोजना बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि फेज-2 के शुरू होने से शहर के बड़े हिस्से को मेट्रो से जोड़ दिया जाएगा और यह ईस्ट-वेस्ट एवं नॉर्थ-साउथ दोनों कॉरिडोर को एकीकृत करेगा।

यह मेट्रो कॉरिडोर प्रह्लादपुरा से टोड़ी मोड़ तक बनाया जाएगा, जिसमें कुल 36 स्टेशन होंगे। इनमें से दो स्टेशन भूमिगत होंगे जबकि शेष एलिवेटेड होंगे। परियोजना की कुल लागत 13,038 करोड़ रुपये निर्धारित की गई है। इसका निर्माण राजस्थान मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आरएमआरसीएल) द्वारा किया जाएगा, जो केंद्र और राजस्थान सरकार का संयुक्त उपक्रम है। यह परियोजना जयपुर के प्रमुख क्षेत्रों जैसे सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया, वीकेआईए, जयपुर एयरपोर्ट, टोंक रोड, एसएमएस अस्पताल, स्टेडियम, अंबाबाड़ी और विद्याधर नगर को आपस में जोड़ेगी। एयरपोर्ट क्षेत्र में कुछ स्टेशन भूमिगत होंगे, जबकि बाकी हिस्सा एलिवेटेड रहेगा।

फेज-2 को वर्तमान में संचालित फेज-1 से जोड़ा जाएगा, जिससे पूरे शहर में एकीकृत मेट्रो नेटवर्क तैयार होगा। फेस-1 के साथ खासाकोटी में इसका बड़ा इंटरचेंज बनेगा। अभी फेज-1 के 11.64 किमी लंबे कॉरिडोर पर रोजाना करीब 60,000 यात्री सफर करते हैं, और फेज-2 के शुरू होने के बाद इस संख्या में काफी वृद्धि होने की संभावना है।

सरकार के अनुसार इस परियोजना से शहर में ट्रैफिक जाम कम होगा, प्रदूषण में कमी आएगी और लोगों को बेहतर व तेज परिवहन सुविधा मिलेगी। परियोजना का आर्थिक आंतरिक प्रतिफल दर (ईआईआरआर) 14 प्रतिशत से अधिक है, जो इसकी आर्थिक व्यवहार्यता को दर्शाता है। इस मेट्रो प्रोजेक्ट को राजस्थान टीओडी नीति-2025 और राष्ट्रीय शहरी परिवहन लक्ष्यों के अनुरूप तैयार किया गया है। इसे सितंबर 2031 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

त्रिपुरा : मुख्यमंत्री की रैली से लौट रहे भाजपा समर्थकों पर ग्रेनेड हमला और फायरिंग

एजेंसी, अगरतला

त्रिपुरा के खोवाई जिले के तेलियामुरा में मंगलवार रात उस वक्त तनाव फैल गया, जब कुछ बदमाशों ने मुख्यमंत्री डॉ. माणिक साहा की रैली में शामिल होने के बाद लौट रहे भाजपा समर्थकों के वाहनों फायरिंग करते हुए ग्रेनेड से हमला कर दिया। ज्ञात हो कि, भाजपा समर्थक त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल (एडीसी) चुनावों से पहले मुख्यमंत्री डॉ. माणिक साहा की जनसभा से लौट रहे थे।

पुलिस के मुताबिक, यह हमला बीती रात मेरेंग बाज़ार के पास पराकाल्क इलाके में हुआ। हमलावरों ने कथित तौर पर गाड़ियों पर तीन राउंड फायरिंग की और एक ग्रेनेड से धमाका करने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि उनका मकसद मतदाताओं के बीच डर फैलाना था। इस हमले में कम से कम 10 लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

हालात को काबू में करने के लिए पुलिस और सुरक्षा बलों की भारी तैनाती की गई। हालांकि, पुलिस का कहना है कि प्रशासन प्रभावित इलाके में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए तेज़ी से काम कर रहा है।

मुख्यमंत्री ने इस घटना की कड़ी निंदा की और तिपरा मोथा के सदस्यों पर चुनाव प्रक्रिया को बाधित करने के लिए इस हमले की साज़िश रचने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अपनी शर्मनाक हार को देखते हुए उन्होंने ऐसा किया। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी समर्थकों को परेशान किया गया और डराया-धमकाया गया। साथ ही, रैली में शामिल लोगों के बीच डर पैदा करने के लिए जान-बूझकर हथियारों का इस्तेमाल किया गया।

मुख्यमंत्री ने ऐसी हरकतों की आलोचना करते हुए कहा कि यह जानते हुए कि आने वाले एडीसी चुनावों में उनकी हार तय है, कुछ लोग 1970 के दशक की हिंसक राजनीतिक संस्कृति को फिर से जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने तिपरा मोथा पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की प्रगति में बाधा डालने के लिए आतंक फैलाने वाली तरकीबें अपनाने का आरोप लगाया, लेकिन समर्थकों को भरोसा दिलाया कि कोई भी धमकी या हिंसक कार्रवाई उन्हें स्थानीय चुनावों में जीत हासिल करने से नहीं रोक पाएगी।

ममता बनर्जी के मामले में चुनाव आयोग पहुंचा भाजपा प्रतिनिधिमंडल

एजेंसी, नई दिल्ली

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का एक प्रतिनिधिमंडल बुधवार को मुख्य निर्वाचन आयोग पहुंचा। पार्टी नेताओं ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस नेता अभिषेक बनर्जी के खिलाफ चार पत्रों की शिकायत दर्ज कराई। प्रतिनिधिमंडल में केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार, अर्जुन मेघवाल और भाजपा महासचिव अरुण सिंह शामिल थे। भाजपा ने आरोप लगाया है कि ममता बनर्जी ने चुनावी रैलियों में ऐसे बयान दिए हैं, जिससे लोगों में डर और भ्रम फैल सकता है। शिकायत के अनुसार, एक रैली में ममता बनर्जी ने कहा कि "सीआरपीएफ की 200 गाड़ियां लोगों पर हमला करने आ रही हैं।" वहीं, दूसरी रैली में उन्होंने आरोप लगाया कि "सीआरपीएफ की गाड़ियों से पैसे लाए जा रहे हैं।"

भाजपा ने अपनी शिकायत में कहा कि ऐसे बयान केंद्रीय सुरक्षा बलों की छवि खराब करते हैं। लोगों में डर पैदा कर सकते हैं। चुनाव की निष्पक्षता को प्रभावित कर सकते हैं। भाजपा ने भारत निर्वाचन आयोग से मामले की जांच कर उचित कार्रवाई की मांग की है। आयोग से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए भाजपा नेता अरुण सिंह ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी ने कथित तौर पर सीआरपीएफ जवानों के खिलाफ हिंसा भड़काने वाला बयान दिया है। अरुण सिंह ने कहा कि अभिषेक बनर्जी ने भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों के हाथ-पैर तोड़ने जैसी बात कही है, जो लोकतंत्र के लिए बेहद चिंताजनक है।

खरीफ फसलों के लिए 'पीएंडके' उर्वरकों पर पोषक तत्व आधारित सब्सिडी को मंजूरी

एजेंसी, नई दिल्ली

केंद्र सरकार ने देश में इस साल की खरीफ की फसल (एक अप्रैल से 30 सितंबर) के लिए फॉस्फेटिक और पोटाशिक (पीएंडके) उर्वरकों पर पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) को मंजूरी दे दी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में उर्वरक विभाग के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। इस साल की खरीफ फसलों के लिए अनुमानित बजट लगभग 41,533.81 करोड़ रुपये है, जो पिछले साल की खरीफ की फसलों की तुलना में करीब 4,317 करोड़ रुपये अधिक है। पिछले वर्ष खरीफ 2025 के लिए बजट 37,216.15 करोड़ रुपये था।

केंद्र ने कहा कि इस निर्णय से किसानों को डीएपी और एनपीकेएस ग्रेड सहित 'पीएंडके' उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित होगी और उन्हें सब्सिडी दरों पर किफायती मूल्य पर उर्वरक मिलेंगे।

केंद्र ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में उर्वरकों हालिया कीमतों को ध्यान में रखते हुए सब्सिडी दरों को मंजूरी दी गई है। वर्तमान में सरकार 28 ग्रेड के 'पीएंडके' उर्वरक, जिनमें डीएपी भी शामिल है, किसानों को सब्सिडी दरों पर दी जा रही है।

उल्लेखनीय है कि एनबीएस योजना अप्रैल 2010 से लागू है और इसके तहत उर्वरक कंपनियों को अनुमोदित दरों पर सब्सिडी दी जाती है ताकि किसानों तक उर्वरक सस्ती दरों पर पहुंच सके।

केन्द्र ने राजस्थान के बालोतरा पेट्रोकेमिकल परियोजना की लागत और निवेश में की बढ़ोत्तरी

एजेंसी, नई दिल्ली

केन्द्र सरकार ने एचपीसीएल की राजस्थान के बालोतरा जिले के पचपदरा में बन रही राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड (एचआरआरएल) की लागत और उसमें इक्विटी निवेश में संशोधन किया है। संशोधित परियोजना लागत अब 79,459 करोड़ रुपये की गई है। परियोजना से भारत की ऊर्जा आत्मनिर्भरता बढ़ेगी और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र की आयात पर निर्भरता कम होगी। परियोजना के 1 जुलाई, 2026 को वाणिज्यिक परिचालन शुरू होने की उम्मीद है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने आज संशोधन को मंजूरी दी। परियोजना की लागत पहले 43,129 करोड़ रुपये थी। वहीं, परियोजना में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) भी 8,962 करोड़ रुपये का अतिरिक्त इक्विटी निवेश करेगा।

मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी देते हुए केन्द्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे ऊर्जा सुरक्षा बढ़ेगी, पेट्रोकेमिकल्स के लिए आयात पर निर्भरता कम होगी और घरेलू विनिर्माण क्षेत्रों को बढ़ावा मिलेगा। इससे इस क्षेत्र में औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा, स्थानीय कच्चे तेल का उपयोग होगा और भारत एक रिफाइनिंग हब के रूप में स्थापित होगा। इससे रोज़गार के महत्वपूर्ण अवसर (लगभग 25,000 नौकरियाँ) पैदा होंगे और समग्र आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। उल्लेखनीय है कि राजस्थान के बालोतरा जिले के पचपदरा स्थित एचआरआरएल एक 90 लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष (एमएमटीपीए) की क्षमता वाला ग्रीनफील्ड रिफाइनरी-सह-पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स है। इसकी पेट्रोकेमिकल उत्पादन क्षमता 24 लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष है। परियोजना का कार्यान्वयन एचआरआरएल कर रहा है। एचआरआरएल एचपीसीएल और राजस्थान सरकार का संयुक्त उद्यम (जेवी) है। इसमें क्रमशः दोनों की हिस्सेदारी 74 प्रतिशत और 26 प्रतिशत है।

ईरान-अमेरिका युद्धविराम 8 अप्रैल 2026- युद्धविराम या केवल रणनीतिक विराम अस्थायी राहत,गहरी अनिश्चितता और वैश्विक शक्ति- संतुलन का जटिल समीकरण -समग्र विश्लेषण

लोकतंत्र की शान

» युद्धविराम क्रा वैश्विक प्रभाव ऊर्जा,अर्थव्यवस्था और कूटनीति पर असर होगा जो आम जनता के लिए राहत की बात

» वैश्विक समुदाय के लिए यह एक चेतावनी है कि केवल सैन्य शक्ति से नहीं, बल्कि संवाद, सहयोग और समझ से ही स्थायी शांति संभव है -एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र

गोंदिया - वैश्विक स्तरपर 8 अप्रैल 2026 को पश्चिम एशिया एक बार फिर वैश्विक चिंता का केंद्र बन गया,जब डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा ईरान के साथ दो सप्ताह के अस्थायी युद्धविराम की घोषणा की गई। यह घोषणा चेतावनी की समय सीमा समाप्त होने के 90 मिनटपूर्व उस समय आई जब सैन्य टकराव अपने चरम पर था और सभ्यता के अंत जैसी कठोर चेतावनियां दी जा चुकी थीं। यद्यपि इस कदम से वैश्विक स्तरपर राहत की सांस ली गई,परंतु युद्धविराम के कुछ ही घंटों बाद ईरान की ऑयल रिफाइनरी में धमाका और खाड़ी देशों यूएई व कुवैत पर मिसाइल एवं ड्रोन हमले इस तथ्य को रेखांकित करते हैं कि यह शांति स्थायी नहीं बल्कि अत्यंत नाजुक है। मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं गोंदिया महाराष्ट्र यह मानता हूं क्रि इस पूरे घटनाक्रम को समझना आवश्यक है, क्योंकि यह केवल दो देशों के बीच संघर्ष नहीं,बल्कि वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा, कूटनीतिक संतुलन,और क्षेत्रीय शक्ति समीकरणों का व्यापक प्रतिबिंबहै।अमेरिका और ईरान के बीच हुआ यह युद्धविराम मूलतः एक टैक्टिकल पॉज है, न कि स्थायी समाधान। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने स्पष्ट किया है कि यह युद्ध का अंत नहीं बल्कि वार्ता की संभावनाओं को खोलने के लिए लिया गया कदम है। ईरान ने यह भी स्पष्ट किया कि उसकी सैन्य गतिविधियां पूरी तरह बंद नहीं होंगी,बल्कि यह इस बात पर निर्भर करेगा कि उस पर हमले रुकते हैं या नहीं।इस प्रकार, यह युद्धविराम शर्तों पर आधारित है,एक ऐसा संतुलन जहां दोनों पक्ष अपनी सैन्य तैयारियों को बनाए रखते हुए कूटनीतिक संवाद का रास्ता तलाश रहे हैं। यही कारण है कि ईरान ने साफ कहा कि हमारे हाथ ट्रिगर पर हैं, जो इस समझौते की अस्थिरता को उजागर करता है। साथियों बात अगर हम स्ट्रेट ऑफ होर्मुजः वैश्विक ऊर्जा राजनीति का केंद्र इसको समझने की करें तो इस पूरे संघर्ष का सबसे महत्वपूर्ण पहलू स्ट्रैट ऑफ़ होर्मूज़ है, जिससे होकर विश्व के लगभग 20 प्रतिशत तेल की आपूर्ति होती है। अमेरिका की प्रमुख मांग रही है कि इस जलमार्ग को तुरंत और सुरक्षित रूप से खोला जाए।ईरान ने इस पर सैद्धांतिक सहमति तो दी है,लेकिन अपनी शर्तों के साथ,जिसमें उसकी सैन्य निगरानी औरतकनीकी नियंत्रण शामिल है। यह दर्शाता है कि ईरान इस जलमार्ग को केवल व्यापारिक मार्ग नहीं बल्कि एक रणनीतिक हथियार के रूप में देखता है।यदि होर्मुज बंद होता है, तो वैश्विक तेल कीमतों में भारी उछाल, सप्लाई चेन बाधित होना, और आर्थिक अस्थिरता निश्चित है। इसीलिए इस जलमार्ग का खुलना पूरी दुनिया के लिए राहत का संकेत माना जा रहा है। साथियों बात अगर हम ईरान की 10 शर्तेंः शांति यारणनीतिक दबाव? इसको समझने की करें तो ईरान ने युद्धविराम को स्थायी शांति में बदलने के लिए 10 सूत्रीय प्रस्ताव रखा है,जो केवल सैन्य संघर्ष समाप्त करने तक सीमित नहीं बल्कि व्यापक भू-राजनीतिक पुनर्संतुलन की मांग करता है।इन शर्तों में अमेरिकी प्रतिबंधों को हटाना, जब्त संपत्तियों की वापसी, पुनर्निर्माण के लिए वित्तीय सहायता, और क्षेत्रीय संघर्षों जैसे यमन, लेबनान, इराक—का स्थायी समाधान शामिल है। साथ ही, ईरान ने परमाणु हथियार न बनाने की प्रतिबद्धता भी जताई है, लेकिन इसके साथ यूरेनियम संवर्धन के अधिकार की बात भी रखी है।यहीं सबसे बड़ा विवाद उत्पन्न होता है। अमेरिका लंबे समय से ईरान के परमाणु कार्यक्रम को समाप्त करना चाहता है, जबकि ईरान इसे अपनी संप्रभुता का हिस्सा मानता है। फारसी और अंग्रेजी दस्तावेजों में यूरेनियम संवर्धन को लेकर अंतर इस वार्ता को और जटिल बनाता है। साथियों बात अगर हम जमीनी हकीकतः युद्धविराम के बावजूद जारी हमले इसको समझने की करें तोयुद्धविराम की घोषणा के बावजूद, खाड़ी क्षेत्र में मिसाइल और ड्रोन हमलों की खबरें लगातार आ रही हैं। इजराइल द्वारा ईरान पर हमले जारी रखना और ईरान की ओर सेजवाबी कार्रवाई इस बात का संकेत है कि जमीनी स्तरपर स्थिति अभी भी नियंत्रण में नहीं है।यह विरोधाभास राजनीतिक घोषणाएं बनाम वास्तविक घटनाएं इस संघर्ष की जटिलता को उजागर करता है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि युद्ध केवल दो देशों तक सीमित नहीं बल्कि एक व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष बन चुका है, जिसमें कई प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष खिलाड़ीसटीक रूप से शामिल हैं। साथियों बात अगर हम इस संपूर्ण मामले पर भारत की प्रतिक्रियाः संतुलित कूटनीति और मानवीय चिंता को समझने की करें तो,भारत ने इस युद्धविराम का स्वागत करते हुए इसे शांति की दिशा में एक सकारात्मक कदम बताया है। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि भारत हमेशा से संवाद और कूटनीति का समर्थक रहा है।हालांकि, भारत की प्राथमिक चिंता अपने नागरिकों की सुरक्षा है। 8 अप्रैल 2026 को एम्बेस्सी ऑफ़ इंडिया इन तेहरान ने एक आपातकालीन एडवाइजरी जारी कर ईरान में रह रहे लगभग 9,000 भारतीयों से देश छोड़ने की अपील की।यह कदम दर्शाता है कि भारत स्थिति की गंभीरता को समझ रहा है और किसी भी संभावित खतरे से पहले अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालना चाहता है। यह प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी का उदाहरण है। साथियों बात अगर हम सीज़फायर के मुद्दे पर भारत में राजनीतिक प्रतिक्रियाः कूटनीति बनाम राजनीति को समझने की करें तो इस अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम का प्रभाव भारत की आंतरिक राजनीति पर भी पड़ा है। महाराष्ट्र क्षेत्रीय पार्टी के एक नेता ने केंद्र सरकार और पीएम पर तीखा हमला करते हुए कहा कि भारत इस वैश्विक संकट में प्रभावी भूमिका निभाने में असफल रहा।उन्होंने पाकिस्तान की कथित मध्यस्थता का हवाला देते हुए सरकार की विदेश नीति पर सवाल उठाए। इसके जवाब में सत्ताधारी दल ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि स्थिति की गंभीरता को समझना आवश्यक है और भारत अपनी रणनीतिक प्राथमिकताओं के अनुसार कार्य कर रहा है।यह बहस दर्शाती है कि विदेश नीति भी अब घरेलू राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बन चुकी है। साथियों बात कर हम सीजफायर क्रे इस मुद्दे पर पाकिस्तान की भूमिकाः कूटनीतिक अवसर या अतिशयोक्ति? इसको समझने की करें तो इस युद्धविराम में पाकिस्तानी पीएम और सेवा प्रमुख की भूमिका को लेकर चर्चा हो रही है। ट्रंप ने स्वयं दावा किया कि पाकिस्तान के अनुरोध पर उन्होंने सैन्य कार्रवाई रोकी फ़िर भी हालांकि इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि सीमित है, लेकिन यह स्पष्ट है कि पाकिस्तान इस स्थिति को एक कूटनीतिक अवसर के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा है। इससे दक्षिण एशिया की भू-राजनीति में भी नए समीकरण बन सकते हैं।इसी बीच, भारत द्वारा पाकिस्तान सीमा के पास नोटम जारी करना और बंगाल की खाड़ी में जीएनएसएस (जीपीएस) जैमिंग ट्रायल की योजना इस बात का संकेत है कि आधुनिक युद्ध केवल पारंपरिक हथियारों तक सीमित नहीं रहा।सैटेलाइट सिग्नल को बाधित करने की क्षमता भविष्य के युद्धों में निर्णायक भूमिका निभा सकती है। यह कदम भारत की तकनीकी और सामरिक तैयारी को दर्शाता है, जो बदलते वैश्विक सुरक्षा वातावरण के अनुरूप है। साथियों बात अगर हम इस पूरे मामले और सीज़ फायर को अंतरराष्ट्रीय परिपेक्ष में समझने की करें तो वैश्विक प्रभावः ऊर्जा, अर्थव्यवस्था और कूटनीति पर असर होगा इस संघर्ष का प्रभाव केवल क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक है। ऊर्जा आपूर्ति, व्यापार मार्ग, और वित्तीय बाजार—आल इंटरकनेक्टेड हैं। होर्मुज जलडमरूमध्य के खुलने या बंद होने का सीधा असर तेल की कीमतों और वैश्विकअर्थव्यवस्था पर पड़ता है।इसके अलावा, यह संघर्ष अमेरिका, ईरान, इजरायल, खाड़ी देशों और अन्य शक्तियों के बीच शक्ति संतुलन को भी प्रभावित करता है। यदि यह युद्ध लंबा खिंचता है, तो इसका असर वैश्विक मंदी तक पहुंच सकता है। अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे क्रि अनिश्चित शांति और लंबी कूटनीतिक यात्रा 8 अप्रैल 2026 का यह युद्धविराम एक राहत अवश्य प्रदान करता है, लेकिन यह स्थायी शांति का संकेत नहीं है। ईरान और अमेरिका के बीच अविश्वास, परमाणु कार्यक्रम पर मतभेद, और क्षेत्रीय संघर्षों की जटिलता इस समझौते को बेहद नाजुक बनाती है।भारत जैसे देशों के लिए यह समय संतुलित कूटनीति, नागरिक सुरक्षा, और रणनीतिक तैयारी का है। वहीं, वैश्विक समुदाय के लिए यह एक चेतावनी है कि केवल सैन्य शक्ति से नहीं, बल्कि संवाद, सहयोग और समझ से ही स्थायी शांति संभव है।इस प्रकार, यह युद्धविराम एक अंत नहीं बल्कि एक अंतराल है एक ऐसा अंतराल, जिसमें दुनिया को यह तय करना है कि वह संघर्ष की ओर बढ़ेगी या सहयोग की ओर बढ़ेगी

-संकलनकर्ता लेखक - क्रर विशेषज्ञ स्तंभकार साहित्यकार अंतरराष्ट्रीय लेखक चिंतक कवि संगीत माध्यम सीए (एटीसी) एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं गोंदिया महाराष्ट्र 9284141425

"लमहों ने ख़ता कीथी, सदियों ने सज़ा पाई"

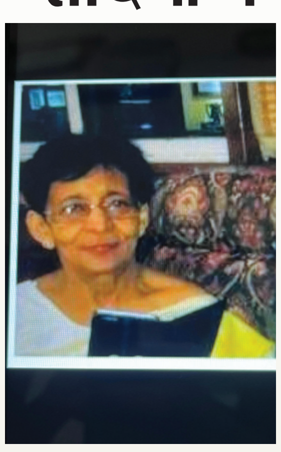

— डॉ.जया शुक्ला

इतिहास स्वयंको दोहराता है। पहले 1971 मेँ श्रीमती इंदिरा गाँधी के सामने बाँगलादेश बनने के समय; फिर 1975 मेँ वियतनाम; फिर 2026 मेँ ईरान। यह पुनः सिद्ध हुआ कि किसी परमाणु शक्ति सम्पन्न महाशक्ति को हरानेके लिये उसके बराबर संसाधनोँकी नहीँ, बल्कि अपने पास रीढ़की हड्डी, गहरी देशभक्ति, और दृढ़ नीयत की आवश्यकता होतीहै। यह 117वीँ बार ट्रम्प ने यू-टर्न लिया; 7 अप्रैल, 2026 की रात्रिमेँ 9 बजे "एक बड़ी सभ्यता दुनियाँ से मिट जायेगी"; मात्र 11 बजे युद्धविराम। ट्रम्प ने ईरान की सभी दस शर्तेँ मान लीँ, ईरान ने होर्मुज़ का रास्ता खोल दिया। यह दस शर्तेँ हैंः-

1) अमेरिका हमला नहींकरेगा (Non-aggression)।

2) Strait of Hormuz पर ईरानका कंट्रोल बनारहेगा।

3) यूरेनियम enrichment कोमंज़ूरी।

4) सभी primary sanctions हटाए जाएंगे।

5) सभी secondary sanctions भी खत्महोंगे।

6) United Nations Security Council के सभी प्रस्ताव खत्मकिए जाएंगे।

7) अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेन्सी के बोर्ड औफ़ डाइरेक्चर्स के सभी प्रस्ताव खत्मकिए जाएंगे।

8) ईरानको मुआवज़ा दिया जाएगा।

9) इलाकेसे अमेरिकी फौज हटेगी।

The 10) हरमोर्चे पर जंग बंदहोगी, जिसमें हिज़बुल्ला (पाकिस्तान लेबनान की इस्लामिक रेजिस्टेंस) केखिलाफ कार्रवाईभी शामिल है।

फ़िलहाल यह युद्धविराम दो सप्ताह के लिये है, इस्लामाबाद मेँ वार्ता के बाद पूरी स्थिति साफ़ होगी। किन्तु स्थितियाँ दूसरे प्रकार की भी बदलेँगी। अमरीका सुपरपावर के पदसे हटेगा। सुपरपावर रहने के लिये तीन शक्तियाँ आवश्यक हैँ - सैन्य और हथियारोँकी शक्ति, आर्थिक शक्ति, और अपनी शक्ति के प्रति दूसरोँ के हृदयमेँ भया। अमरीका का मिसाइलोँ का ज़ख़ीरा काफ़ी खाली हो चुका है, जबकि ईरान की 10,000 किमी वाली मिसाइल भी खड़ी होगई है। साथही दो मज़बूत ताकतेँ, चीन और रूस की एलायेंस ईरान के पासहै। डॉलर के आगे अपनी करेंसी मज़बूत करनेके लिये चीन पहलेही व्यापार मेँ ख़रीददारोँ से डॉलर के बदले येन मेँ पैसे लेने की शर्त रखता रहा, अब युद्ध के दौरान ईरान ने तेल बेचने के लिये येन की शर्त रख दी। तीसरी ताक़त भय की थी, तो वह तो इस 40 दिनोँ के युद्ध के बाद घट ही गई, विशेषकर जब अमरीका की केन्द्रीय सरकार डगमगाने की स्थिति में है, वहाँ 85 सीनेटर ट्रम्प को हटाने के लिये लिखकर देचुके हैं। कुछ भयप्रद परिस्थितियाँ भी उत्पन्न होती दीख रही हैं। चीन की मानसिकता साम्राज्यवादी है, विशेषकर भारत इसका बहुत नुकसान उठारहा है। अब वह अपनी "दबंगई" बढ़ाएगा, और पूरे हिन्द महासागर क्षेत्र के देश चिंतित रहेंगे। किन्तु सबसे ख़तरनाक वह ज्वालामुखी है, जिसने सुलगना प्रारंभ कर दिया। उत्तरी कोरिया ने, जिसे अनेक कारणोँ से अभीतक चुप बैठना पड़ा था, दोदिन पूर्व ईरान पर अटैक की स्थिति मेँ वॉशिंगटन और तेलअवीव पर न्यूक्लियर हमलेकी खुली चेतावनी दी। अब युद्धविराम होतेही उसने अपनी मिसाइल जापान की दिशा मेँ छोड़दी। फ़िलहाल सन्तोष है कि पृथ्वी और मानव समाज बहुत बड़े विनाशसे अभी बच गया है।

- जया शुक्ला

कमजोर वर्गों के लिए योजनाएँः विवाद का विषय या विकास का आधार?

लेखक - डॉ. सत्यवान सौरभ

कमजोर वर्गों के लिए बनाई गई विकास और कल्याणकारी योजनाओं को अक्सर 'भेदभावपूर्ण' कहकर आलोचना की जाती है। पहली नज़र में यह तर्क आकर्षक लग सकता है कि जब सरकार कुछ खास वर्गों को लक्षित करके लाभ देती है, तो यह बाकी लोगों के साथ अन्याय है। लेकिन जब इस बात को गहराई से समझा जाता है, तो स्पष्ट होता है कि यह सोच सामाजिक न्याय की मूल भावना को चुनौती देती है। भारत जैसे देश में, जहाँ लंबे समय से जाति, आर्थिक और सामाजिक असमानताएँ जड़ें जमाए हुए हैं, ऐसी योजनाएँ केवल विकल्प नहीं बल्कि आवश्यकता हैं, और साथ ही यह संविधान द्वारा निर्धारित जिम्मेदारी भी हैं। भारतीय समाज की ऐतिहासिक संरचना ने कुछ वर्गों को विशेषाधिकार दिए, जबकि कुछ वर्गों को निरंतर वंचना और भेदभाव का सामना करना पड़ा। सदियों से चली आ रही इस असमानता ने अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक सम्मान से दूर रखा। ऐसे में यदि राज्य केवल 'समान व्यवहार' की नीति अपनाता, तो यह असमानता और गहरी हो जाती। इसलिए संविधान निर्माताओं ने यह समझा कि समानता का वास्तविक अर्थ सबको समान स्थिति में लाना है, न कि केवल समान नियम लागू करना। इसी संदर्भ में संविधान का अनुच्छेद 46 विशेष महत्व रखता है, जो राज्य को यह निर्देश देता है कि वह कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा दे तथा उन्हें सामाजिक अन्याय और शोषण से बचाए। यह प्रावधान यह स्पष्ट करता है कि लक्षित योजनाएँ किसी प्रकार का पक्षपात नहीं, बल्कि न्याय की दिशा में उठाया गया आवश्यक कदम हैं। यही 'सकारात्मक भेदभाव' या 'affirmative action' की अवधारणा है, जो ऐतिहासिक असमानताओं की भरपाई करने का प्रयास करती है। इन योजनाओं का प्रभाव केवल सैद्धांतिक नहीं, बल्कि व्यावहारिक स्तर पर भी स्पष्ट दिखाई देता है। पिछले कुछ दशकों में शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति इसका प्रमाण है। जहाँ पहले कमजोर वर्गों की साक्षरता दर बहुत कम थी, वहीं आज इसमें उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। छात्रवृत्ति योजनाओं, आवासीय विद्यालयों और विशेष शैक्षिक कार्यक्रमों ने लाखों बच्चों को स्कूल और उच्च शिक्षा तक पहुँचने का अवसर प्रदान किया है। इसी प्रकार, ग्रामीण रोजगार योजनाओं, स्वयं सहायता समूहों और कौशल विकास कार्यक्रमों ने आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया है। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में भी इन योजनाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को न केवल आय के साधन मिले हैं, बल्कि उन्होंने सामाजिक स्तर पर भी अपनी पहचान बनाई है। इससे परिवार और समाज दोनों में सकारात्मक परिवर्तन आया है। यह दर्शाता है कि लक्षित योजनाएँ केवल आर्थिक लाभ तक सीमित नहीं होतीं, बल्कि वे सामाजिक बदलाव का माध्यम भी बनती हैं। हालाँकि, इन योजनाओं को लेकर विवाद भी कम नहीं हैं। आलोचकों का कहना है कि जब किसी विशेष वर्ग को प्राथमिकता दी जाती है, तो यह अन्य वर्गों के साथ अन्याय है। उदाहरण के लिए, कई बार आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग का व्यक्ति केवल इसलिए किसी योजना का लाभ नहीं ले पाता क्योंकि वह निर्धारित श्रेणी में नहीं आता। इससे 'रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन' की भावना उत्पन्न होती है, जो सामाजिक असंतोष को जन्म दे सकती है। यह तर्क पूरी तरह निराधार नहीं है, लेकिन यह अधूरा अवश्य है। यह इस तथ्य को नजरअंदाज करता है कि सभी व्यक्ति समान परिस्थितियों में जन्म नहीं लेते। कुछ लोग ऐसे सामाजिक और आर्थिक परिवेश में पले-बढ़े होते हैं जहाँ उन्हें बेहतर शिक्षा, संसाधन और अवसर मिलते हैं, जबकि कुछ लोग अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवन की शुरुआत करते हैं। ऐसे में, यदि दोनों को समान अवसर दिए जाएँ, तो परिणाम समान नहीं होंगे। इसलिए, समानता को वास्तविक रूप देने के लिए असमान लोगों के साथ अलग व्यवहार करना आवश्यक हो जाता है। फिर भी, यह स्वीकार करना होगा कि इन योजनाओं के क्रियान्वयन में कई कमियाँ हैं। भ्रष्टाचार, लाभ का असमान वितरण और पारदर्शिता की कमी जैसी समस्याएँ इनकी प्रभावशीलता को प्रभावित करती हैं। कई बार देखा गया है कि जिन लोगों को इन योजनाओं की सबसे अधिक आवश्यकता होती है, वे इससे वंचित रह जाते हैं, जबकि अपेक्षाकृत सक्षम लोग इसका लाभ उठा लेते हैं। 'क्रीमी लेयर' की अवधारणा इसी समस्या को दूर करने के लिए लाई गई थी, लेकिन इसे सभी वर्गों में प्रभावी रूप से लागू नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त, बदलते समय के साथ समाज की समस्याएँ भी बदल रही हैं। आज शहरी क्षेत्रों में गरीबी का स्वरूप अलग है, जहाँ विभिन्न जातियों के लोग समान आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। ऐसे में केवल जाति के आधार पर योजनाएँ बनाना पर्याप्त नहीं है। नीतियों को अधिक समावेशी और बहुआयामी बनाना होगा, जिसमें आर्थिक स्थिति, शिक्षा और क्षेत्रीय असमानताओं को भी ध्यान में रखा जाए। सुधार के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है—पारदर्शिता और सटीकता। लाभार्थियों की पहचान को अधिक प्रभावी बनाने के लिए डिजिटल तकनीकों का उपयोग किया जा सकता है। आधार-आधारित सत्यापन, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) और डेटा एनालिटिक्स के माध्यम से योजनाओं को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाया जा सकता है। इसके साथ ही, योजनाओं के क्रियान्वयन की नियमित निगरानी और स्वतंत्र ऑडिट भी आवश्यक है, ताकि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को समय रहते रोका जा सके। निजी क्षेत्र और नागरिक समाज की भागीदारी भी इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल विकास के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा, स्थानीय समुदायों को योजनाओं के क्रियान्वयन में शामिल करने से उनकी प्रभावशीलता और भी बढ़ सकती है, क्योंकि स्थानीय स्तर पर समस्याओं की समझ अधिक गहरी होती है। अंततः, यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि कमजोर वर्गों के लिए बनाई गई योजनाएँ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं, बल्कि न्याय की स्थापना का माध्यम हैं। ये योजनाएँ उस ऐतिहासिक असमानता को दूर करने का प्रयास हैं, जिसने समाज के एक बड़े वर्ग को लंबे समय तक अवसरों से वंचित रखा। यदि इन्हें समाप्त कर दिया जाए, तो यह केवल असमानता को और गहरा करेगा तथा सामाजिक असंतुलन को बढ़ावा देगा। अंबेडकर का सपना केवल राजनीतिक समानता तक सीमित नहीं था, बल्कि सामाजिक और आर्थिक समानता भी उसका अभिन्न अंग था। 'एक व्यक्ति, एक वोट' के साथ 'एक व्यक्ति, एक अवसर' की अवधारणा को साकार करने के लिए इन योजनाओं का अस्तित्व अनिवार्य है। आवश्यकता इस बात की है कि हम इनके अस्तित्व पर प्रश्न उठाने के बजाय इनके क्रियान्वयन को और अधिक प्रभावी, पारदर्शी और समावेशी बनाएँ। जब भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहा है, तब यह याद रखना होगा कि विकास का वास्तविक अर्थ केवल आर्थिक प्रगति नहीं, बल्कि समाज के हर वर्ग का सशक्तिकरण है। यदि समाज का सबसे कमजोर व्यक्ति भी आत्मनिर्भर और सम्मानजनक जीवन जीने में सक्षम हो जाता है, तभी सच्चे अर्थों में विकास संभव है।

कब पुनः शुरू होगी वरिष्ठ नागरिकों की रेल यात्रा छूट?

लेखिका- निर्मल रानी

मार्च 2020 में कोरोना महामारी के दौरान दुनिया के अनेक देशों में तरह तरह के अभूतपूर्व फ़ैसले लिये गये थे। प्रायः ऐसे फ़ैसलों का मक़सद कोरोना महामारी के संक्रमण को यथासंभव रोकना था। इसी दौरान पूरे विश्व में हवाई यातायात तक ठप्प हो गया था। अनेक देशों में लॉक डाउन लगा दिया गया था। कल-कारख़ाने सभी प्रकार के यातायात, व्यवसाय, उद्योग बाज़ार आदि सभी बंद कर दिये गये थे। भारत भी उन्हीं देशों में एक था जहाँ पूर्ण लॉक डाउन लगा दिया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं 24 मार्च 2020 की रात को पहले चरण के राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की थी। 25 मार्च 2020 की मध्यरात्रि से लागू हुआ प्रथम चरण का यह पूर्ण लॉकडाउन पहले तो केवल 21 दिनों का बताया गया था परन्तु बाद में भी इसे कई चरणों में आगे बढ़ाया गया था। इसी पूर्ण लॉकडाउन के दौरान रेल सहित देश की सभी यातायात सुविधाओं को पूर्णतः स्थगित कर दिया गया था। कोरोना का प्रभाव कम होने के बाद भारतीय रेलवे ने 12 मई से चरणबद्ध तरीक़े से यात्री ट्रेनों को फिर से शुरू करने की योजना बनाई थी। इसके अंतर्गत सर्वप्रथम 15 विशेष ट्रेनों के द्वारा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन को असम, बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, जम्मू, झारखंड,कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु, तेलंगाना और त्रिपुरा के प्रमुख शहरों से जोड़ा गया था। बाद में धीरे धीरे इनका विस्तार किया गया। भारत सरकार ने इस अवसर का लाभ उठाते हुये वरिष्ठ नागरिकों को रेल यात्रा में रेल टिकट पर मिलने वाली आंशिक छूट को पूरी तरह समाप्त कर दिया था। वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाली छूट को समाप्त करते समय सरकार द्वारा यह तर्क दिया गया था कि "अनावश्यक यात्रा रोकने" के लिये यह छूट समाप्त की गयी है। परन्तु आज पूरे छः वर्ष बीत जाने के बाद भी जबकि देश भर में ट्रेन सेवाएं लगभग सामान्य हो चुकी हैं, यह छूट आज तक बहाल नहीं हुई है। ग़ौरतलब है कि उसी दौरान प्रधानमंत्री ने यह कहा था कि इतनी बड़ी आपदा, भारत के लिए एक संकेत लेकर आई है, एक संदेश लेकर आई है, एक अवसर लेकर आई है। भारत ने आपदा को, अवसर में बदल दिया है । रेल विभाग ने भी इसी आपदा में अवसर देखते हुये कोरोना काल की आड़ में कई ऐसे निर्णय ले डाले जो सरकार के लिये भले ही लाभदायक रहे हों परन्तु रेल यात्रियों के लिये तो हरगिज़ नहीं थे। मिसाल के तौर पर अनेक पैसेंजर ट्रेन को एक्सप्रेस ट्रेन बताकर कहीं स्टॉपेज कम कर दिये गये तो कहीं किराया बढ़ा दिया गया। कई ट्रेन स्थाई रूप से कैंसिल कर दी गयी तो कई ट्रेन के रुट बदल दिये गये। इनमें से कोरोना काल के समय किये गये कुछ परिवर्तन तो यथापूर्व किये गये परन्तु कुछ कोरोना काल समाप्त होने के बावजूद आज तक वैसे ही हैं। जैसे कि कोरोना काल में वरिष्ठ नागरिकों को रेल यात्रा में रेल टिकट पर मिलने वाली आंशिक छूट को पूरी तरह समाप्त कर दिया जाना। सवाल यह है कि जब यह छूट समाप्त करते समय "अनावश्यक यात्रा रोकने" जैसा तर्क दिया गया था तो आज तक उस छूट को पुनः लागू क्यों नहीं किया गया ? जबकि अब न केवल कोरोना काल के पूर्व की लगभग सभी ट्रेन्स चल रही हैं बल्कि अनेक नई ट्रेन्स भी पटरियों पर दौड़ने लगी हैं? ग़ौरतलब है कि भारतीय रेल ने छात्र, दिव्यांगजन, रोगी, स्वतंत्रता सेनानी, युद्ध विधवाएँ जैसी कुल 53 श्रेणियों में विभिन्न स्तर पर छूट दी थी। इन्हीं में वरिष्ठ नागरिक भी शामिल थे। वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाली टिकट छूट की सुविधा विभिन्न चरणों में 1985 में शुरू की गई थी। अगस्त 2001 से इसे स्वैच्छिक बना दिया गया अर्थात वरिष्ठ नागरिक चाहें तो छूट ले सकते थे। लेकिन यात्रा के दौरान छूट लेने वालों को अपनी आयु का कोई न कोई प्रमाण जैसे आधार, पैन कार्ड या पासपोर्ट आदि यात्रा के समय अपने साथ रखना अनिवार्य कर दिया गया था। इस सुविधा का लाभ देश के बुज़ुर्गों ने 35 वर्षों तक उठाया परन्तु स्वयं को लोकहितकारी बताने का ढिंढोरा पीटने वाली मोदी सरकार ने इसे कोरोना की आड़ में समाप्त कर दिया। जो सरकार छूट समाप्त करते समय "अनावश्यक यात्रा रोकने" जैसा तर्क दे रही थी वही सरकार अब इसे सरकार पर "वित्तीय बोझ" मान रही है। सरकार का तर्क है कि रेलवे पहले से ही भारी घाटे में चल रही है । रेल मंत्री संसद में बता भी चुके हैं कि रेलवे सभी यात्रियों को औसतन 45% सब्सिडी दे रही है । गोया प्रत्येक यात्री को पहले से ही काफ़ी राहत मिल रही है। कुछ आंकड़े बताते हैं कि सरकार अनावश्यक यात्रा रोकने जैसे उपाय कर देश के बुज़ुर्गों से अब तक दस हज़ार करोड़ से अधिक रूपये कमा चुकी है। इसी सन्दर्भ में इस बात का ज़िक्र करना भी ज़रूरी है कि बुज़ुर्गों की रेल यात्रा छूट समाप्त करने वाली यही सरकार जब चाहती है और जहाँ से चाहती है विभिन्न तीर्थ स्थलों की मुफ़्त यात्रा हेतु विशेष ट्रेन चला देती है। जब चाहती है चुनावी राज्यों के लिये स्थानीय प्रवासियों हेतु विशेष ट्रेन चलाकर उन्हें मतदान करने हेतु निःशुल्क भेजती है। गोया अपने वोट बैंक साधने के लिये तो सरकार तत्पर रहती है परन्तु इसी सरकार के पास न तो कोरोना काल की शुरुआत में इन्हीं प्रवासी मज़दूरों को उनके राज्यों व शहरों तक भेजने के लिये कोई ट्रेन थी न ही आज उन ट्रेन्स पर चलने वाले बुज़ुर्गों के लिये पूर्व में मिलने वाली छूट ? हालाँकि कभी कभार अपुष्ट सूत्रों से यह ख़बर सुनाई देती है कि शायद सरकार पुनः यह छूट देने पर विचार कर रही है। परन्तु इस पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया जा सका है। विपक्षी सांसदों ने इसे "बुज़ुर्गों के साथ अन्याय" बताते हुये लोकसभा में भी कई बार सवाल उठाए परन्तु सत्ता पक्ष ने "वित्तीय कारण" देकर यह सुविधा शुरू करने से इनकार कर दिया। बुज़ुर्ग संगठनों में भी इसे लेकर काफ़ी नाराज़गी व गहरी निराशा है। इसी लिये देश यह सवाल कर रहा है कि जब सांसदों विधायकों को आजीवन पेंशन देने के लिये "वित्तीय कारण" आड़े नहीं आते तो आख़िर सरकार बुज़ुर्गों को ट्रेन में छूट क्यों नहीं दे रही?" वरिष्ठ नागरिकों को आज भी इस बात की आस है कि आख़िर रेल यात्रा में मिलने वाली छूट कब शुरू होगी?

17 वर्षीय दृष्टिबाधित भारतीय तैराक ने

रचा इतिहास

● 11 घंटे 15 मिनट में तय की 38 किलोमीटर की यात्रा

नागपुर (एजेंसी)। कहते हैं कि दृढ़ संकल्प एक ऐसी शांत शक्ति है जो बाधाओं को मील के पत्थरों में बदल देती है और असंभव को संभव बना देती है. नागपुर की 17 वर्षीय दृष्टिबाधित तैराक ईश्वरी पांडे ने पाक स्ट्रैट को तैरकर सफलतापूर्वक पार करके इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लिया है. वह दुनिया की पहली ऐसी दृष्टिबाधित तैराक बन गई हैं जिन्होंने यह कारनामा कर दिखाया है।

11 घंटे 15 मिनट तक तैरना

जन्म से ही दृष्टिबाधित ईश्वरी ने श्रीलंका के तलाईमन्नार से अपनी तैराकी शुरू की और भारत के धनुषकोडी (तमिलनाडु) तक की 38 किलोमीटर की यात्रा 11 घंटे 15 मिनट में पूरी की. उन्होंने 6 अप्रैल को सुबह करीब 4 :00 बजे उरमालाई पॉइंट के पास पानी में प्रवेश किया और 7 अप्रैल की दोपहर 3 :15 बजे धनुषकोडी स्थित अरिचलमुनाई पहुंचीं।

कई प्रकार की चुनौतियों का किया सामना– इस अभियान को पूरा करने के लिए उन्हें समुद्र की तेज धाराओं, बदलते ज्वार-भाटा, भारी बारिश और तेज हवाओं का सामना करना पड़ा. उन्होंने जेलीफिश और शार्क जैसे खतरनाक समुद्री जीवों के बीच से भी रास्ता बनाया, जो इस उपलब्धि को और भी अधिक उल्लेखनीय बनाता है।

प्रकृति ने भी उनकी खूब परीक्षा ली

ईश्वरी के कोच संजय बटवे ने अपनी शिष्या द्वारा बनाए गए विश्व रिकॉर्ड पर प्रसन्नता व्यक्त की. उन्होंने कहा कि ईश्वरी का यह कारनामा सचमुच तारीफ के काबिल है. इस मिशन के दौरान उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा. प्रकृति ने भी उनकी खूब परीक्षा ली. बारिश, हवा और तेज लहरों की वजह से उन्हें काफी तकलीफ उठानी पड़ी. इसी वजह से, इस कार्यक्रम की शुरुआत चार घंटे देर से हुई. आखिरकार, श्रीलंकाई सरकार से हरी झंडी मिलने के बाद, ईश्वरी सुबह 4 बजे तलाईमन्नार जेटी से समुद्र में कूद गईं।

कई लोगों का सहयोग और ईश्वरी की महानता नागपुर के अनुभवी तैराकों की एक टीम ईश्वरी के साथ 'पेस स्विमर' (गति बनाए रखने वाले तैराक) के तौर पर मौजूद थी।

2026 में सबसे लंबे छक्के मारने वाले टॉप-5 बल्लेबाज

मुंबई (एजेंसी)। इंडियन प्रीमियर लीग 2026 का 14वां मैच आज दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटन्स के बीच खेला जाना है. हर मैच में छक्कों की बरसात होती है. पिछले ही मैच में कुल 15 छक्के लगे थे. जिसमें मुंबई और राजस्थान आमने सामने थे. इससे पहले आरसीबी और सीएसके के मैच में कुल 30 छक्के लगे थे. इस मैच में कुल 14 अलग-अलग बल्लेबाजों ने कम से कम एक-एक छक्का लगाया।

जिसके बाद फैंस के मन में अब ये सवाल उठ रहे हैं कि अब खेले गए मैच में सबसे लंबा छक्का किस बल्लेबाज ने लगाया है? इसलिये इस प्रश्न का जवाब देने के लिए हम इस कॉपी में उन पांच बल्लेबाज के बारे में बताने वाले हैं, जो अब तक सबसे लंबे छक्के लगाने वालों की सूची में शामिल हैं।

लिस्ट में आरसीबी का जलवा जारी

आईपीएल 2026 का सबसे लंबा छक्का– आईपीएल 2026 में खेले गए अब तक के मैचों में सबसे लंबा छक्का मारने का नाम आरसीबी के टिम डेविड के नाम है. उन्होंने चेन्नई के खिलाफ 5 मार्च को 106 मीटर लंबा छक्का जड़ा था, जो एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर चला गया था. उसके बाद इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर पंजाब किंग्स के कूपर कोनोली हैं. उन्होंने गुजरात टाइटंस के खिलाफ 103 मीटर का गगनचुंबी छक्का जड़ा था. तीसरे नंबर पर सनराइजर्स हैदराबाद के अनिकेत वर्मा हैं. उन्होंने आरसीबी के खिलाफ 100 मीटर का सिक्स जड़ा था. लिस्ट में चौथे और पांचवें नंबर पर आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार हैं. जिन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ 94 और 92 मीटर का छक्का जड़ा था। बता दें कि आईपीएल 2026 के पॉइंट्स टेबल में अभी राजस्थान रॉयल्स 3 मैच में से तीन जीत के साथ टॉप पर है. पंजाब तीन मैच में दो जीत और एक मैच रद्द होने से 5 अंक लेकर दूसरे स्थान पर है. जबकि आरसीबी दो मैच में दो जीत के साथ 4 अंक लेकर तीसरे नंबर पर है. वहीं ऑरेंज कैप यशस्वी जायसवाल के नाम है।

टॉप-5 बल्लेबाज

1– टिम डेविड (आरसीबी) 106 मीटर
2– कूपर कोनोली (पीबीकेएस) 103 मीटर
3– अनिकेत वर्मा (एसआरएच) 100 मीटर
4– रजत पाटीदार (आरसीबी) 94 मीटर
5– रजत पाटीदार (आरसीबी) 92 मीटर

सीएम धामी ने किया 25वीं एआईपीडब्ल्यूएससी प्रतियोगिता का वर्चुअली शुभारंभ

440 खिलाड़ी दिखाएंगे दम

19 टीमों ले रही हिस्सा

देहरादून (एजेंसी)। उत्तराखंड में पहली बार 25वीं ऑल इंडिया पुलिस वाटर स्पोर्ट्स क्लस्टर चैंपियनशिप का शंखनाद हो गया। बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टिहरी गढ़वाल के वाटर स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर इंस्टीट्यूट में आयोजित इस प्रतियोगिता का वर्चुअली उद्घाटन किया। इस मौके पर सीएम ने देश के अलग-अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आए पुलिस व अर्धसैनिक बलों के खिलाड़ियों और अधिकारियों का देवभूमि में स्वागत किया।

राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन से साबित हुआ, हम तैयार हैं

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'खेलो इंडिया' और 'फिट इंडिया मूवमेंट' का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में अब खेल संस्कृति मजबूत हो रही है।

उन्होंने याद दिलाया कि उत्तराखंड ने हाल ही में 38वें राष्ट्रीय खेलों का सफल आयोजन किया है। इससे स्पष्ट है कि देवभूमि अब 'खेलभूमि' के रूप में भी तेजी से उभर रही है। राज्य में आधुनिक खेल इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जा रहा है ताकि भविष्य में अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जा सकें।

19 टीमों के 440 से ज्यादा खिलाड़ी ले रहे हिस्सा

चैंपियनशिप में देशभर की 19 टीमों के 440 से ज्यादा महिला और पुरुष खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। ये खिलाड़ी कैनोइंग, रोइंग और कयाकिंग की विभिन्न स्पर्धाओं में अपनी क्षमता का प्रदर्शन करेंगे। सीएम धामी ने अखिल भारतीय पुलिस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड का आभार जताते हुए कहा कि यह उत्तराखंड के लिए बेहद गर्व का विषय है कि राज्य को पहली बार इस राष्ट्रीय आयोजन की मेजबानी मिली है। ऐसे आयोजनों से राज्य को साहसिक खेलों (एडवेंचर स्पोर्ट्स) और पर्यटन के क्षेत्र में नई पहचान मिलेगी।

राज्य को पहली बार मिली मेजबानी

कार्यक्रम में इनकी रही मौजूदगी

उद्घाटन के इस खास अवसर पर टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय, जिला पंचायत अध्यक्ष (टिहरी) इशिता सजवान, नगर पालिका अध्यक्ष मोहन सिंह रावत, विशेष प्रमुख सचिव (खेल) अमित सिन्हा, एडीजी आईटीबीपी संजय गुंज्याल, आईजी (नॉर्दन फ्रंटियर आईटीबीपी) मनु महाराज, आईजी (सीआरपीएफ) दिनेश उनियाल, आईजी (आईटीबीपी एकेडमी) गिरीश चंद्र उपाध्याय, जिलाधिकारी नीतिका खण्डेलवाल और एसएसपी श्वेता चौबे समेत कई अधिकारी और खेल प्रेमी उपस्थित रहे।0

आपदा प्रबंधन और रेस्क्यू में मददगार हैं वाटर स्पोर्ट्स

खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि देश की सुरक्षा, कानून व्यवस्था और जनता का विश्वास बनाए रखने में हमारे जवानों की अहम भूमिका होती है, इसलिए उनका शारीरिक और मानसिक रूप से फिट रहना जरूरी है। खेल न केवल फिटनेस बढ़ाते हैं, बल्कि अनुशासन और मुश्किल हालात में काम करने की क्षमता भी विकसित करते हैं। सीएम ने एक अहम बात यह भी कही कि वाटर स्पोर्ट्स जैसे खेल आपदा प्रबंधन, बाढ़ राहत, नदी बचाव और तटीय सुरक्षा में काफी उपयोगी साबित होते हैं। इन खेलों की दक्षता आपातकालीन परिस्थितियों में जीवन रक्षक बनती है।

हार पर हार्दिक ने कहा हम गेंदबाजों के कारण हारे

वैभव के खेल में निडरता दिखती है

गुवाहाटी (एजेंसी)। मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या ने राजस्थान रॉयल्स से मिली 27 रनों की हार की जिम्मेदारी गेंदबाजों पर डाल दी. मैच के बाद उन्होंने कहा कि गेंदबाजों ने राजस्थान रॉयल्स के ओपनर्स को खुलकर खेलने का मौका दिया, जिसकी बदौलत राजस्थान ने गुवाहाटी में बारिश से प्रभावित 11–11 ओवर के मैच में 150/3 का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया. जवाब में मुंबई की टीम 11 ओवर में 123/9 रन ही बना सकी।

'मैं बल्लेबाजी पर दोष नहीं डालूंगा'

मैच के बाद की प्रस्तुति में पांड्या ने कहा, 'हमने वैसी गेंदें नहीं डालीं जैसी हमें डालनी चाहिए थीं. उन्होंने (राजस्थान) बहुत अच्छा खेला. गेंदबाजों को जिम्मेदारी लेनी होगी. एक गेंदबाजी ग्रुप के तौर पर, हम उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाए।'

उन्होंने आगे कहा, 'मैं बल्लेबाजी पर दोष नहीं डालूंगा. निश्चित रूप से यह गेंदबाजी यूनिट की गलती थी, जिसे जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी. बात हमेशा अच्छी गेंदें डालने की होती है. अगर हमने सही गेंदें डाली होती, तो हम मैच में बने रहते. उनके ओपनर्स ने हमें हमारे खेल से भटका दिया और हम बस उनके पीछे–पीछे भागते रह गए और मैच में पिछड़ गए।' राजस्थान रॉयल्स के टीनएज बैटिंग संसेशन, वैभव सूर्यवंशी के बारे में पूछे जाने पर पांड्या ने कहा, '17 या 16 साल के लड़के (वैभव) को इस तरह खेलते देखना काफी दिलचस्प है. जिस तरह से वह बैटिंग करता है, उसमें जो निडरता है, उसे देखना कमाल का है. मैं उसके भविष्य के लिए उसे शुभकामनाएं देता हूं।'

हार्दिक पांड्या द्वारा पहले फील्डिंग चुनने के बाद, मुंबई इंडियंस की गेंदबाजी यूनिट परिस्थितियों का फायदा उठाने में नाकाम रही. जिसका नतीजा ये निकला कि राजस्थान के यशस्वी जायसवाल (32 गेंदों पर 77 रन नाबाद) और वैभव सूर्यवंशी (14 गेंदों पर 39 रन) ने छक्कों की बारिश कर दी और 3.2 ओवर के पावर–प्ले में ही 56 रन ठोक डाले।

व्यापार

एलआईसी के लाखों निवेशकों की चांदी, बोनस शेयर बांटने की तैयारी में बीमा कंपनी

नईदिल्ली, एजेंसी। सरकारी बीमा कंपनी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के शेयरों में बुधवार को जबरदस्त तेजी आई है। एलआईसी के शेयर बुधवार को 7 पर्सेंट से ज्यादा के उछाल के साथ 803 रुपये पर पहुंच गए हैं। एलआईसी ने अपने शेयरधारकों को बड़ा तोहफा देने का ऐलान किया है। बीमा कंपनी अपने निवेशकों को बोनस शेयर बांटने की तैयारी में है। एलआईसी के शेयर फिलहाल अपने प्राइस से नीचे कारोबार कर रहे हैं। कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 980.05 रुपये है। वहीं, एलआईसी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 722 रुपये है। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया है कि सोमवार 13 अप्रैल को कंपनी के बोर्ड की बैठक है। इस मीटिंग में कंपनी के शेयरधारकों को बोनस शेयर जारी करने के प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा। अभी तक अपने शेयरधारकों को कोई बोनस शेयर नहीं दिया है। अगर कंपनी का बोर्ड बोनस शेयर जारी करने की मंजूरी देता है तो यह पहला मौका होगा, जब अपने निवेशकों को बोनस शेयर देगी। एलआईसी अब तक अपने शेयरधारकों को डिविडेंड्स के जरिए रिवॉर्ड देती आई है। करीब 21 लाख आम निवेशकों को मिल सकता है तोहफा लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 96.50 पर्सेंट है, जबकि पब्लिक शेयरहोल्डिंग 3.50 पर्सेंट है। अगर 2 लाख रुपये तक की नॉमिनल शेयर कैपिटल होल्ड करने वाले आम निवेशकों की बात करें तो उनकी संख्या फिलहाल 20,97,116 है। कंपनी में आम निवेशकों की हिस्सेदारी 1.52 पर्सेंट है। अगर टोटल पब्लिक शेयरहोल्डर्स की बात करें तो इनकी संख्या 21,55,209 है। अगर पिछले एक साल की बात करें तो एलआईसी के शेयर करीब 3 पर्सेंट चढ़े हैं। वहीं, पिछले 6 महीने में कंपनी के शेयरों में 10 पर्सेंट की गिरावट देखने को मिली है। पिछले एक महीने में कंपनी के शेयर लगभग फ्लैट हैं। यह 9 मई तक ओपन रहा। आईपीओ में कंपनी के शेयर का दाम 949 रुपये था।

क्रूड ऑयल के गिरते ही रॉकेट बने आरआईएल, एचपीसीएल समेत कई स्टॉक्स

नईदिल्ली, एजेंसी। वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतों में आई तेज गिरावट ने भारतीय ऑयल कंपनियों के शेयरों में बड़ा उतार-चढ़ाव पैदा कर दिया है। हाल ही में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान के साथ दो हफ्ते के सीजफायर की घोषणा के बाद कच्चे तेल की कीमतों में करीब 15-17 प्रतिशत की भारी गिरावट देखी गई। इसका सीधा असर भारतीय शेयर बाजार में ऑयल सेक्टर पर पड़ा, जहां कुछ कंपनियों के शेयर उछल गए तो कुछ में गिरावट देखने को मिली। आइए इसको जरा विस्तार से समझते हैं। तेल की कीमतों में गिरावट का सबसे ज्यादा फायदा डाउनस्ट्रीम कंपनियों को हुआ। इन कंपनियों का काम कच्चे तेल को रिफाइन करके पेट्रोल-डीजल बनाना होता है। जब कच्चा तेल सस्ता होता है, तो इनकी लागत घटती है और मुनाफा बढ़ता है। यही वजह है कि इनके शेयरों में 6 प्रतिशत से 9 प्रतिशत तक की तेजी देखी गई। वहीं रिलायंस के शेयरों में भी बढ़त दर्ज हुई, क्योंकि इसका रिफाइनिंग बिजनेस भी इस ट्रेंड से फायदा उठाता है। दूसरी ओर अपस्ट्रीम कंपनियों के लिए यह गिरावट नुकसानदायक साबित हुई। ऑयल और नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन और ऑयल इंडिया जैसी कंपनियों के शेयर 8 अप्रैल 2026 को 3.43 प्रतिशत तक गिर गए। ये कंपनियां सीधे कच्चे तेल का उत्पादन करती हैं, इसलिए तेल की कीमत गिरने से उनकी कमाई पर असर पड़ता है। रिपोर्ट्स के अनुसार, कच्चे तेल में हर 1 डॉलर की गिरावट से के राजस्व पर 300-400 करोड़ रुपये का असर पड़ सकता है। इस पूरे घटनाक्रम की जड़ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज है, जो दुनिया के करीब 20 प्रतिशत तेल सप्लाई का प्रमुख मार्ग है।

स्टॉक पिक्सः इन्फोसिस, गेल समेत 6 शेयरों में रह सकती है बड़ी हलचल

नईदिल्ली, एजेंसी। शेयर मार्केट में आज तूफानी तेजी की उम्मीदों के बीच निवेशकों की नजरें इन्फोसिस, गेल, अरबिंदो फार्मा, अदित्य बिड़ला रियल एस्टेट, प्रोस्टार्म इन्फो सिस्टम्स, क्लीन मैक्स एनवायरो एनर्जी, जैसे शेयरों पर होंगी। ये स्टॉक अपने विभिन्न अपडेट्स के कारण आज खबरों में हैं।

शेयर मार्केट में आज तूफानी तेजी की उम्मीदों के बीच निवेशकों की नजरें इन्फोसिस, गेल, अरबिंदो फार्मा, अदित्य बिड़ला रियल एस्टेट, क्लीन मैक्स एनवायरो एनर्जी, प्रोस्टार्म इन्फो सिस्टम्स जैसे शेयरों पर होंगी। एआई से सॉफ्टवेयर डिलीवरी में क्रांति

इन्फोसिस ने हार्नेस नामक एआई सॉफ्टवेयर डिलीवरी प्लेटफॉर्म के साथ साझेदारी की है। इसका उद्देश्य दुनियाभर की कंपनियों में एजेंटिक एआई के जरिए सॉफ्टवेयर डिलीवरी को बदलना है। यह साझेदारी इंजीनियरिंग टीमों की उन समस्याओं को हल करेगी, जहां उनका अधिकतर समय टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट जैसे कामों में लग जाता है।

सरकारी कंपनी गेल ने ग्रीस की अल्फा गैस के साथ लंबी अवधिक का चार्टर समझौता किया है। यह समझौता 'एनर्जी फिडेलिटी' नाम के एलएनजी जहाज के लिए है, जिसकी क्षमता 1,74,000 घन मीटर है। इस जहाज का उपयोग अमेरिका और रूस जैसे देशों से एलएनजी आयात करने के लिए किया जाएगा। यह करार एथेंस में साइन किया गया। अरबिंदो फार्मा को अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन से डापाग्लिफ्लोज़िन और मेटफोर्मिन हाइड्रोक्लोराइड की एक्सटेंडेड-रिलीज टैबलेट बनाने और बेचने की अंतिम मंजूरी मिल गई है। ये टैबलेट एस्ट्राजेनेका की दवा 'जिग्डुओ एक्सआर' के समान हैं। इनका उत्पादन कंपनी की सहायक कंपनी हेल्थकेयर की यूनिट में होगा।

अदित्य बिड़ला रियल एस्टेटः1600 करोड़ की बुकिंगः कंपनी की सहायक कंपनी बिरला एस्टेट्स को गुरुग्राम के लक्जरी प्रोजेक्ट 'बिरला अरिका फेज 2' में जबरदस्त सफलता मिली है। लॉन्च के एक महीने के भीतर ही 1,600 करोड़ रुपये से अधिक की बुकिंग हो चुकी है। कुल 156 यूनिट में से 152 यूनिट बिक चुकी हैं।

ट्रंप के सीजफायर के ऐलान से कच्चे तेल में भारी गिरावट, 100 डॉलर के नीचे आया भाव

नईदिल्ली, एजेंसी। अमेरिका और ईरान के बीच दो सप्ताह के सीजफायर पर सहमति बनने के बाद ग्लोबल ऑयल मार्केट में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। इस समझौते के तहत स्ट्रेट ऑफ होर्मूज को फिर से खोलने की उम्मीद है, जिससे सप्लाई में रुकावटें कम होने की उम्मीदें बढ़ गई हैं। इसी उम्मीद में कच्चे तेल की कीमतें तेजी से फिसलकर 100 डॉलर प्रति बैरल के नीचे आ गई हैं। ब्लूमबर्ग के मुताबिक तेल कीमतों में आई गिरावट बेहद तेज रही। ब्रेंट क्रूड करीब 16 प्रतिशत तक टूटकर 92 डॉलर प्रति बैरल से नीचे आ गया, जबकि वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट में पिछले छह वर्षों की सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई और यह करीब 95 डॉलर के स्तर पर पहुंच गया। ट्रंप ने कहा कि यह सीजफायर पूरी तरह इस बात पर निर्भर करेगा कि ईरान होर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह खोलता है या नहीं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराकची के अनुसार, पाकिस्तान द्वारा पेश की गई युद्धविराम योजना को स्वीकार कर लिया गया है। अगले दो हफ्तों तक सुरक्षित समुद्री मार्ग सुनिश्चित किया जाएगा। वहीं, व्हाइट हाउस के अधिकारियों के मुताबिक इजरायल ने भी इस प्रस्ताव पर सहमति जताई है, जिससे वैश्विक बाजारों को राहत मिली है। होर्मुज स्ट्रेट दुनिया के सबसे अहम तेल मार्गों में से एक है, जहां से वैश्विक तेल और ल्हत्र का करीब 20 प्रतिशत गुजरता है। इसके बंद होने से ऊर्जा बाजार में भारी उथल–पुथल मच गई थी।हालांकि, कीमतों में गिरावट के बावजूद फरवरी के बाद से अब भी करीब 50 प्रतिशत ऊपर बना हुआ है, जो यह दिखाता है कि संकट पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। एक्सपर्ट रॉबर्ट रेनी के अनुसार, 'तेल सप्लाई तुरंत सामान्य नहीं होगी। बंद कुओं को फिर से शुरू करने, जहाजों की तैनाती और स्टॉक भरने में महीनों लग सकते हैं।'

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक सैयद ज़की हैदर के लिए इरानीयन आर्ट प्रिंटर्स 1534 कासिमजान स्ट्रीट दरियागंज नई दिल्ली 11006 से मुद्रित कराकर, 2684 गली काले खां कूचा चलान दरियागंज नई दिल्ली 02 से प्रकाशित किया।
संपादक : सैयद ज़की हैदर- हैड ऑफिस :- एफ19/4 सेकेंड फ्लोर नफीश रोड जामिया नगर दिल्ली- 110025., सम्पर्क सूत्र :- 9911371802, 9810383593
जितेन्द्र कुमार बिस्वाल ब्यूरो चीफ उड़ीसा/ गोविंद कनोडिया/ पटना/ सैय्यद यूसुफ अली नक़वी-पॉलिटिकल एडिटर। ई-मेलः- (LOKTANTRAKISHAAN@GMAIL.COM

किसी भी प्रकार के विवाद हेतु निपटारे के लिए केवल दिल्ली न्यायालय ही मान्य होगी।
नोट- किसी भी समाचार/आलेख पर दावा प्रति दावा/आपत्ति समाचार प्रकाशन के 15 दिनों के अन्तराल तक ही मान्य होगा। समाचार पत्र में प्रकाशित आलेख से संपादक/प्रकाशक का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

क्षेत्रीय कार्यालय अनवार मंजिल नया टोला गंज नंबर 01 बेतिया/ बिहार/ पिन नंबर 84 5438/>> संवाददाता, सना खान/(डॉ. अमानुल हक) स्थानीय संपादक/बिहार)